लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

[खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, सोमवार, 20 नवम्बर, 1967/29 कार्तिक, 1889 (शक)

No. 5, Monday, November 20, 1967/Kartika 29, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
*121.	नाथुला में हुए संघर्ष के बारे में पेकिंग रेडियो द्वारा प्रसारण	Peking Radio Broadcast on Nathula Clash	665—674
122.	पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों का प्रशिक्षण	Training of Mizo Rebels in East Pakistan	674—679
126.	इलेक्ट्रानिक उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Electronic Equipments	679—681
127.	अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों तथा अफसरों के लिए सुविधायें।	Amenities to Jawans and Officers on Forward Areas	681—683

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
125.	ट्रांसमीटरों का निर्माण	Manufacture of Transmitters	684
128.	नागाओं का चीन से वापिस आना	Return of Nagas from China	684
130.	पाकिस्तान के साथ वार्ता	Talks with Pakistan	684—685
131.	वार्षिक योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन	Mobilisation of additional resources for Annual Plan	685

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
132.	राष्ट्रीय छात्र सेना दल द्वारा नेताजी की तलवार का सम्मान अभिवादन (गार्ड आफ आनर)	N.C.C. Guard of Honour to Netaji's Sword	685—686
133.	विमान द्वारा वस्तुओं के गिराये जाने पर होने वाला नुकसान	Losses during air dropping of supplies	686
134.	जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर पाकिस्तान सेना जमाव	Pakistani Troop Concentration on Jammu and Kashmir Border	686—687
135.	सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को हथियारों का दिया जाना	Supply of arms by Saudi Arabia to Pakistan	687
136.	टंगस्टेन धातु का खरीदा जाना	Purchase to Tungsten Metal	687
137.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट	A.I.R. Staff Artistes	687—688
138.	भारतीयों द्वारा कीनिया तथा अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों का परित्याग	Indians leaving Kenya & other East African Countries	688
139.	राज्यों की वार्षिक योजनाएं	Annual Plans of States	689
141.	अमरीका द्वारा अरब देशों को दिये गये हथियारों का पाकिस्तान पहुंचना	USA arms from Arab countries reaching Pakistan	689
142.	राज्यों की योजनाएं	State Plans	689
143.	सेनाध्यक्ष (चीफ आफ आर्मी-स्टाफ) की पाकिस्तान यात्रा	Chief of Army Staff's visit to Pakistan	690
144.	पाकिस्तान में ईरान के विमान	Iranian planes in Pakistan	690—691
145.	नाथूला की मुठभेड़ों के बारे में समाचारपत्र वालों को हिदायतें	Briefing to Newsmen on Nathu La Clashes	691
146.	स्पाट लाइट आसाम का पुनर्गठन प्रसारण	Spot Light Reorganisation of Assam Broadcast	692

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
147.	चीन के खतरे के बारे में दक्षिण एशिया के देशों के साथ वार्ता	Talks with South Asian Countries regarding Chinese Threat	692
148.	नागाओं का चीन चला जाना	Nagas crossing over to China	692—693
149.	भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन	Indian Statistical Institute, Calcutta Review Committee Report	693
150.	भारतीय शिष्टमंडल का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तानी शिष्टमण्डल का भारत आना	Delegations to and from Pakistan	693—694
अतारांकित प्रश्न संख्या U. Q. Nos.			
997.	नागा नेताओं की विदेशों में भेंट	Meeting of Naga leaders in foreign Countries	694
998.	पाकिस्तान का सैन्य बल	Army Strength of Pakistan	695
999.	पाकिस्तान के लिए हथियार और पुर्जे	Arms and Spare Parts for Pakistan	695—696
1000.	भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हताहत जवान	Jawans killed and wounded during Indo-Pak. conflict	696
1001.	पाकिस्तान में नष्ट किये गये मन्दिर तथा गिरजाघर आदि	Temples and Churches destroyed in Pakistan	696—697
1002.	आकाशवाणी में कर्मचारी	Staff in AIR	697—698
1003.	चीन के साथ पत्र व्यवहार	Communications exchanged with China	698
1004.	काठमांडू में भारतीय सहायता से बनाया गया हवाई अड्डा	Airfield built with Indian assistance in Kathmandu	698
1005.	गुजरात में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in Gujrat	698—699
1006.	पर्यटकों को विजा दिया जाना	Issue of Visas to Tourists	699
1007.	गुजरात के दैनिक समाचार पत्रों के लिये विज्ञापन	Advertisement for Gujarat Dailies	699

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1008.	गाजा में मारे गये संयुक्त राष्ट्र सेना के भारतीय जवान	Indian Jawans in UN contingent killed at Gaza	700
1009.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर के कर्मचारी मुहम्मद रहमतुल्ला की कार्यवाहियां	Activities of Mohammed Rahamtullah of HAL Bangalore	701
1010.	वियतनाम के बारे में वक्तव्य	Statements on Vietnam	701
1011.	मुख्य सूचना अधिकारी	Principal Information Officer	702
1012.	जम्मू और काश्मीर के बीच राजपथ	Highway between Jammu and Srinagar	702
1013.	बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीयों की सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन	Repatriation of Properties of Indian Repatriates from Burma	702
1014.	हिन्दू नागा शान्ति मिशन	Hindu Naga Peace Mission	703
1015.	चलचित्रों का वितरण	Distribution of Films	703—704
1016.	चीनी घुसपैठियों के विरुद्ध नागालैंड सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	Steps taken by Nagaland State against Chinese Intruders	704
1017.	जालन्धर (पंजाब) में पकड़े गए जाली पारपत्र के मामले	Forged Passport Cases detected in Jullundhur (Punjab)	704
1018.	गांधी स्मारक निधि	Gandhi Memorial Fund	704—705
1019.	भारत नैपाल सीमा पर कौनाली नदी पर जल विद्युत परियोजना	Hydro electric Project on River Karnali on Indo-Nepal Border	705
1020.	बिना विभाग का मन्त्री	Minister Without Portfolio	705
1021.	केन्द्रीय कानूनों को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करने के बारे में लोक-सभा में पुरः स्थापित विधेयक के बारे में पाकिस्तान का विरोध पत्र	Pak. Protest about introduction of a Bill in Lok Sabha re. extension of Central Laws to Jammu and Kashmir	705—706
1022.	प्रतिरक्षा कार्य सम्बन्धी प्रयोगशालायें	Defence Laboratories	706—707
1023.	अनुसन्धान तथा विकास परियोजनायें	Research and Development Projects	707

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1024.	बेरुत स्थित दूतावास में रखे गये सन्दूक की चोरी के संबंध में की गई शिकायत	Complaint re. Theft of a Box lodged with Mission in Beirut	707—708
1025.	विज्ञापनों पर व्यय	Expenditure on Advertisement	708
1026.	समाचारपत्रों का विज्ञापन देना	Advertisements to Newspapers	708—709
1027.	पर्वतीय सीमा क्षेत्रों के लिये विशेष अनुभाग (सैल)	Special Cell for Hill Border Areas	709—710
1028.	अग्रिम क्षेत्रों में सेवा करने वाले जवानों तथा अफसरों के परिवारों को सुविधायें	Amenities to Families of Jawans and Officers serving in Forward Areas	710—711
1029.	राष्ट्रपति नासर के विदेशी मामलों के सलाहकार का भारत में आना	Visit to India of President Nasser's Foreign Affairs Adviser	711
1030.	चीन से नागाओं की वापसी	Return of Nagas from China	711
1031.	भारत पाकिस्तान सर्वेक्षण सम्बन्धी वार्ता	Indo Pak Survey Talks	711—712
1033.	पंजाब में भूमि का अर्जन	Acquisition of Land in Punjab	712—713
1034.	पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब का भारत पर आरोप	President Ayub's Allegation against India	713
1035.	पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र का विकास	Development of Sundarbans Areas of West Bengal	713
1036.	विदेशों में भेजे गये पर्यटक रुचि वाले चलचित्र	Films of Tourist Interest sent Abroad	713—714
1038.	भारतीय तथा पाकिस्तानी सेना कमांडरों की भेंट	Meetings of Indian and Pakistan Army Commanders	714
1039.	मुरादनगर आयुध कारखाने के आस पास कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land around Muradnagar Ordnance Factory	714—715
1040.	श्रीनगर में एक अड्डा बनाने की अमरीकी योजना की रिपोर्ट	Reported US Plan of a Base in Srinagar	715
1041.	कलपक्कम में परमाणु विद्युत केन्द्र	Atomic Power Station at Kalpakkam	715
1042.	परमाणु विद्युत केन्द्र, कलपक्कम	Atomic Power Station at Kalpakkam	716

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1043. भारतीयों का मलेशिया का दौरा	Visit of Indians to Malaysia	716
1045. गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर में झगड़ा	Clash in Gun and Shell Factory, Kashipur	717
1046. राज्यों के योजना बोर्ड	Planning Boards in States	717
1047. दीवाल समाचारपत्र	Wall Newspapers	717—718
1048. संस्कृत में समाचार	News in Sanskrit	718
1049. चलचित्र सेन्सर व्यवस्था सम्बन्धी समिति	Committee on Film Censorship	718
1050. नये परमाणु विद्युत केन्द्र	New Atomic Power Stations	718—719
1051. विदेशों की खबरों का प्रसारण	Broadcast of Foreign News	719
1052. राडार स्क्रीन	Radar Screen	719
1053. सिक्किम को जाने वाली सीमावर्ती सड़क	Border Road to Sikkim	720
1054. वियतनाम के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग की बैठक	Meeting of International Control Commission on Vietnam	720
1055. येरुसलम में भारतीय होटल	Indian Hotel in Jerusalem	720—721
1056. बर्मा तथा अन्य देशों में नजरबन्द भारतीय	Indians under Detention in Burma and other Countries	721
1057. अफ्रीका के अश्वेत जनता संगठनों द्वारा आन्दोलन	Campaigns by Non-White Peoples' Organisations of Africa	721—722
1058. पूना के निकट मोटर बोट दुर्घटना में सैनिक अधिकारियों की मृत्यु	Death of Army Officers in Motor Boat Accident near Poona	722
1059. नागालैण्ड सम्बन्धी विषय गृह कार्य मन्त्रालय को सौंपा जाना	Transfer of subject of Nagaland to the Ministry of Home Affairs	722—723
1060. गुजरात में भारी पानी तैयार करने वाला कारखाना	Heavy Water Plant in Gujarat	723
1061. नये आयुत्र सामग्री बनाने वाले कारखाने	New Ordnance Factories	723
1062. जापान और फिजी में भवन खरीदना	Purchase of Buildings in Japan and Fiji	724

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1063.	संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से भेंट विमानों का निर्माण	Manufacture of Jets with UAR Collaboration	724
1064.	पहाड़ी डिवीजन	Mountain Divisions	722—725
1065.	आयुत्र कारखानों में प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण	Manufacture of Defence Stores in Ordnance Factories	725
1066.	पत्रकारों का प्रशिक्षण	Training of Journalists	725
1067.	आकाशवाणी से विदेशी भाषाओं में प्रसारण	Foreign Broadcasts by AIR	726
1068.	उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक	Ex-servicemen in Orissa and U.P.	726—727
1069.	1950 की भारत नैपाल सन्धि	Indo Nepalese Treaty of 1950	727
1070.	परमाणु बिजली घर बनाने के लिये ब्रिटेन का प्रस्ताव	Offer from UK for Atomic Power Stations	728
1071.	स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें	Demands of Staff Artists	728
1072.	पाकिस्तान के लिये पनडुब्बियां तथा आधुनिक शस्त्र	Submarines and Modern Arms for Pakistan	729
1073.	विविध भारतीय कार्यक्रम	Vividh Bharti Programme	729
1074.	काश्मीर (पाकिस्तान के कब्जे में) में चीन द्वारा निर्मित सैनिक हवाई अड्डा	Military Airport constructed by Chiniese in Kashmir (P.O.K.)	729—730
1075.	रूस तथा चीन से भारतीय भाषाओं में प्रसारण	Broadcasts in Indian Languages from USSR and China	730
1076.	भूटान को सहायता	Aid to Bhutan	730
1077.	भारतीय चलचित्र संस्था	Film Institute of India	730—731
1078.	विमान तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग	Aircraft and Electronic Industries	731
1079.	चलचित्र निर्माताओं के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Film producers	731—732
1080.	संसत्सदस्यों की नाथूला यात्रा	M.Ps. Visit to Nathu La	732
1081.	आदिवासी लोगों के लिये कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast Programme for Adivasi Population	732

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1082.	सोफिया (बल्गारिया) में दूतावास	Embassy in Sofia (Bulgaria)	732—733
1083.	दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सैनिकों की सहायता के लिये ब्रिटिश फ्रौगमैन	British Frogmen helping American Troops in South Vietnam	733
1084.	विदेशों में भारतीय दूत तथा उच्चायुक्त	Indian Ambassadors and High Commissioners Abroad	733
1085.	दार्जिलिंग में अर्जित भूमि के लिये प्रतिकर	Compensation for Land Acquired in Darjeeling	733—734
1086.	पश्चिम बंगाल के गाँवों में सशस्त्र पाकिस्तानी	Armed Pakistanis in West Bengal Villages	734
1087.	इंजीनियरों को टेलीविजन सम्बन्धी प्रशिक्षण	Training of Engineers in T. V.	734—735
1088.	टेलीविजन का प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार इंजीनियर	Unabsorbed Television Trained Engineers	735
1089.	भारी टैंक	Heavy Tanks	735
1090.	विदेशस्थित भारतीय दूतवासों के अधिकारियों का भाषा सम्बन्धी ज्ञान	Linguistic knowledge of Officers in Indian Embassies Abroad	736
1091.	चीनी दूतवास पर लगाये गये प्रतिबन्ध	Restrictions imposed on Chinese Embassy	736—737
1092.	विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा विदेशों में भारत का गलत स्वरूप पेश किया जाना	Wrong Projection of Image of India Abroad by Foreign Photographers	737
1093.	जम्मू तथा काश्मीर का दौरा करने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी	Officials of I & B Ministry Visiting Jammu and Kashmir	737
1094.	चौथे आम चुनाव में रेडियो काश्मीर से चुनाव सम्बन्धी प्रसारण	Radio Kashmir's role in Fourth General Elections	738
1095.	तिब्बतियों के देश में भारत में प्रवेश करने वाले चीनी लोग	Chinese entering India in the garb of Tibetans	738

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1096. अटौमिक मिनरल्स डिवीजन	Atomic Minerals Division	738—739
1097. नवीन राडार पद्धति	New Radar System	739
1098. कूच बिहार में अज्ञात विमान	Unidentified Plane in Cooch Behar	739
1099. श्रीलंका में कार्य कर रहे भारतीय बैंक	Indian Banks operating in Ceylon	739—740
1100. आणविक खनिज विभाग	Atomic Minerals Divisions	740
1101. भूतत्वज्ञों के पदों पर पदोन्नति	Promotion as Geologists	740—741
1102. परमाणु वैज्ञानिक द्वारा आत्महत्या	Suicide by an Atomic Scientist	741
1103. पेकिंग में भारतीय राजदूतावास के सामने प्रदर्शन	Demonstrations before Indian Embassy as Peking	741—742
1104. परमाणु शक्ति के लिए उपकरण	Equipment for Nuclear Power	742
1105. सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण	Violation of Indian Frontiers by Armed Pakistanis	742—743
1106. पाक चीन साजिश के बारे में राष्ट्रपति अयूब खां का वक्तव्य	Statement of President Ayub Khan about Pak. China Collusion	743
1107. इन्टरनेशनल सिख ब्रदरहुड प्रतिनिधिमंडल के नेता के साथ नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के अधिकारियों का दुर्व्यवहार	Manhandling of Leader of International Sikh Brotherhood Delegation by New Delhi Chinese Embasy Officials	743—744
1108. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर	Bharat Electronics Ltd. Bangalore	744
1109. श्रमिकों से सम्बन्धित पत्रिकाएं	Labour Magazines	745
1110. मिट्टी के कबूतर (क्ले पीजन) पर चांदमारी करने के लिए शॉटगन (छर्रे वाली बन्दूक) के कारतूस	Shotgun Ammunition for Clay Pigeon Shooting	745

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1112. हज की तीर्थयात्रा	Haj Pilgrimage	746
1113. वायु सीमा	Limits of Air Space	746—747
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	747 747—749
भारत में अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) की गतिविधियों के बारे में रहस्योद-घाटन	Disclosures about activites of the CIA in India	
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक	Unlawful Activities (Prevention) Bill	749
(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन-उपस्थापित	(i) Report of Joint Committee Presented	
(2) संयुक्त समिति समक्ष साक्ष्य	(ii) Evidence before Joint Committee	
पाउंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Devaluation of the Pound Sterling	749—751
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	
सूती कपड़ा कम्पनियों (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनः स्थापना) विधेयक-पुरस्थापित	Cotton Textile Companies (Management Undertakings and Liquidation or Reconstruction) Bill-Introduced	751
शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन और शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motions Re: Report of Education Commission and Report of Committee of Members of Parliament on Education	751—765
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani	
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
	श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	
	श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	
	डा० ए० जी० सोनार	Shri A. G. Sonar	
	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
	झरिया में खनन कार्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Mining Operations in Jharia	765—767
	श्री बेनी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	
	श्री हाथी	Shri Hathi	

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 20 नवम्बर, 1967/29 कार्तिक, 1889 (शक)
Monday, November 20, 1967/Kartika 29, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

+

Peking Radio Broadcast on Nathu La clash

*121. **Shri Raghubir Singh Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state;

(a) Whether it is a fact that Peking Radio has claimed in regard to Nathu La clash during September, 1967 that China is in possession of documents signed by Indian officers, wherein they have confessed an attack on China; and

(b) if so, the action taken by Government to counteract this propaganda?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) सरकार को इस बात का पता है कि पेकिंग रेडियो ने तथा कथित दस्तावेजों के बारे में कुछ ऐसा प्रचार किया है जिससे लोगों में यह विश्वास पैदा किया जाय कि भारतीय सेना ने चीनी क्षेत्र पर अतिक्रमण किया था ।

(ख) सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है तथा बाद के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित भी हुआ है कि नाथूला तथा चोला दर्रे पर मृतकों के शव लेने के लिये जो भारतीय अधिकारी भेजे गये थे, उन्होंने उन दस्तावेजों को केवल मृतकों की शव प्राप्ति की रसीदें समझ कर हस्ताक्षर किये थे । इसके अतिरिक्त चोला दर्रे पर चीनियों के प्रचार का पता लगने पर भारतीय अधिकारी ने उस दस्तावेज पर जो उसे हस्ताक्षर करने के लिये पेश किया गया

था, यह स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल मृतकों की शव प्राप्ति कीरसीद दे रहा है। सरकार ने इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है तथा कोई अन्य कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं समझा जाता।

Shri Raghubir Singh Shastri: The propaganda stunt of the Peking radio and the loudspeakers on the Chinese side of the Sikkim-Tibet border is changed daily and every day some new propaganda is launched. On the other hand our propaganda remains unchanged for weeks together. Apart from that the Chinese propaganda is not confied to one Indian language only, but they are carrying it out in all Indian border dialects. May I know whether we are able to carry out our propaganda in those Chinese languages, which are spoken and understood by the Chinese soldiers and people of China of that area.

श्री स्वर्ण सिंह : साधारणतया दूसरी ओर से किये जाने वाले प्रचार के प्रभाव का अनुमान हम वास्तविकता से अधिक लगा लेते हैं। वास्तव में तिब्बत के लिये किये जाने वाला हमारा प्रचार भी काफी प्रभाव शाली है।

Shri Raghubir Singh Shastri: Is it a fact that some of the Kampha labourers engaged on the repair work of the road going to Nathula or breaking the stones have been found to be Chinese spies and whether some of the refugees also are of such character, who cannot be believed and if so, the precautionary action taken by Government in this matter ?

श्री स्वर्ण सिंह : समय समय पर तिब्बती शरणार्थियों की जाँच की गई है। मैं नहीं समझता कि वहाँ सड़क पर काम करने वाले व्यक्तियों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अवांछनीय कहा जा सके। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री नाथ पाई : यह प्रश्न पेकिंग रेडियो के मिथ्या एवं बेहूदा प्रचार को अधिक महत्व देने का नहीं है। हम जानते है कि वहाँ पर हमारी सेनाओं ने कठिनतम स्थिति में शौर्य एवं वीरता का परिचय दिया है परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में कितने भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, तथा मृतकों की अदला बदली कब की गई तथा चीनियों से कितने भारतीयों के शव प्राप्त किये गये ? क्या हमारे कब्जे में भी चीनियों के कुछ शव थे, जिन्हें चीनियों को लौटाया गया अथवा वे चीनी जिनके मारे जाने का दावा भारत सरकार ने किया है, केवल उस तिब्बती क्षेत्र में मारे गये थे, जो इस समय चीन के अधिकार में है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि आरम्भ में जब हमारे सैनिकों एवं अधिकारियों को यह पता नहीं था कि चीनी अचानक गोलीबारी आरम्भ कर देंगे, चीनियों द्वारा अचानक गोलीबारी आरम्भ करने पर हमारे कुछ व्यक्ति हताहत हुए, क्योंकि हमारे सैनिक ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे थे जिसे उत्तेजनात्मक समझा जाये अथवा जिसके बारे में आपत्ति की जा सके। परन्तु बाद में उन्होंने न केवल इसका बदला ही लिया, अपितु विपक्षियों को भारी संख्या में हताहत करने में सफल हुए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, उन्होंने अत्युत्तम वीरता का परिचय दिया।

चीनियों के कब्जों में भारतीयों के शवों के बारे में दो प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है । एक सूचना यह है कि रात के अंधेरे में चीनी कुछ शवों को घसीट कर अपने क्षेत्र में ले गये तथा उन्हें अपने कब्जे में कर लिया । यह भी पता चला है कि चीनियों द्वारा हमला किये जाने के पश्चात हमारे सैनिकों ने चीनी जमीनदोज मोर्चों पर आक्रमण किया । अतः उन्होंने वीरता का एक ऐसा काम किया, जिसका हम सब को गर्व होना चाहिये ।

श्री नाथपाई : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मृतकों की अदलाबदली के समय क्या हमारी ओर से भी चीनिथों को कुछ शव दिये गये थे ? जहाँ तक चीनियों के हताहत होने का प्रश्न है, इस में केवल सन्देह की यह बात है कि चीनी भारी संख्या में हताहत हुए । मैं मानता हूँ कि भारतीय सैनिकों ने अत्यन्त वीरता का परिचय दिया है । मुझे इसकी पूर्ण जानकारी है और मुझे इसका गर्व है । परन्तु मैं यह पूछ रहा हूँ कि मृतकों की अदला बदली के समय भारतीयों द्वारा कितने चीनियों के शव लौटाये गये ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे पास चीनियों के शव नहीं थे, इस लिये उन्हें लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye: Is it a fact that in NathuLa, when Chinese made their first attack, it was surprising and sudden and as our troops were not ready to meet it and some of our officers were off from duty, our troops had to withdraw in the first instance and afterwards they recaptured their position with the help of heavy guns ? The Hon. Minister has stated that our officers signed those documents in good faith as they believed that those were in token of receipts of dead bodies only. It is not a question of exchange of dead bodies, because no Chinese soldier was killed on our side and we had no dead body in our possession. So this was a question about getting back the dead bodies. I want to know whether the paper which was signed was written in Chinese language and whether we have no Chinese knowing person in our army or whether they do not deem it necessary to learn Chinese, because they are English-knowing people, which is an international language. It should be made clear as to why such papers were signed and if those papers were in Chinese language, had we had no Chinese interpreter ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूँ कि वहाँ तैनात हमारे सैनिक को यह आशा नहीं थी कि उन पर अचानक हमला कर दिया जायेगा । इस लिये आरम्भ में हमारे सैनिक हताहत हुए । माननीय सदस्य का यह अनुमान, जो कि उन्होंने पहले प्रश्न में लगाया है कि हमारे सैनिक या तो छुट्टी पर थे अथवा अनुपस्थित थे, सही नहीं है ।

Shri Madhu Limaye: May I know whether no officer of that area was on leave ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं यह कह सकता हूँ कि किसी भी समय हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । मामला यह था कि ज्योंही पहला हमला हुआ हमारे कुछ व्यक्ति हताहत हुए और उसके तुरन्त बाद हमारी सेना ने हमले का उत्तर

दिया तथा देश के हर व्यक्ति ने इस बात की सराहना की है कि उन्होंने बड़ी दृढ़ता एवं वीरता से कार्य किया तथा हम सब को इस बात का गर्व है।

माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न उस दस्तावेज की भाषा के बारे में है जिस पर हमारे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। मैं यह बात स्पष्ट कहूँगा कि हमारे अधिकारी को अधिक सतर्क होना चाहिये था। उसने सद्भाव में हस्ताक्षर किये थे, परन्तु उसे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये था (अन्तर्बाधायें) हमारे पास दुभाषिये हैं, परन्तु इस विशेष मामले में हो सकता है वह चीनी भाषा में हो, उसका अनुवाद भी था।

Shri Madhu Limaye: My question has not been answered. I have asked about the language in which that paper was written, which was signed by our officer, I have not raised the point of translation. I have not asked whether there was a translation of that paper or not. I want to know the language in which that paper was written, which was signed by our officer.

Shri Nath Pai: If we accept that the paper which was signed was written in Chinese, then it was not sufficient to have an English translation of that. It should be made clear whether a Hindi translation was there or not.

ये अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं और इन्हें दोनों सम्बद्ध देशों की भाषा में होना चाहिये। क्या उस का हिन्दी में अनुवाद था, जो कि हमारे जवानों की भाषा है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : भाषा के बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य देने से पहले जो जानकारी प्राप्त हुई है, मुझे उसे पुनः देखना होगा। इस समय मेरे पास जो जानकारी है, मैं बताये देता हूँ। चीनी समाचार पत्रों में जो फोटो छापे गये हैं, उनमें वे दस्तावेज दोनों भाषाओं—चीनी तथा हिन्दी में हैं। उस के नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं उस अधिकारी का नाम जिस ने हस्ताक्षर किये हैं मेजर के० बी० चन्द्राशंकरन है। ऊपर चीनी भाषा है, नीचे हिन्दी भाषा है और इसके नीचे अंग्रेजी में हस्ताक्षर हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह उस तरह का अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज नहीं है और जो महत्ता संधियों जैसे पवित्र अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को दी जाती है, वह इसे नहीं दी जानी चाहिये। उस समय मुख्य उद्देश्य शव प्राप्त करना था। उसने सद्भावना में यह सोचकर कि यह शव प्राप्ति की रसीद है, हस्ताक्षर कर दिये। वह यह नहीं जानता था कि बाद में इसमें कोई अन्य वाक्य जोड़ दिया जायेगा और उसका अनुचित लाभ उठाया जायेगा।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, this is no answer to my question.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है। यदि माननीय सदस्य संतुष्ट न हों, तो मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री वी० चं० शर्मा : हताहत होने के बावजूद हमारे जवानों ने चीनियों को अच्छा सबक सिखाया है। परन्तु कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है तथा इसके बारे में मैंने प्रधान मंत्री को भी लिखा है--कि चीनियों ने जब नाथूला तथा चोला दर्रे पर हमला किया तो सिक्कम

में वे हमारी कुछ भूमि पर कब्जा करने में सफल हो गये थे । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस अनुमान में जो यहां लगाया जा रहा है तथा जिसकी एक प्रकार से श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जैसे महान नेता द्वारा पुष्टि की गई है, कोई सचाई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उस वक्तव्य में कोई सचाई नहीं है। संघर्ष के दौरान चीनियों द्वारा सिक्कम के किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया गया।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, on no occasion of our conflict with the Chinese we have been able either to capture an alive Chinese or have in our possession any of their dead body. Should I understand that our Government had given instructions to our soliders not to capture any alive Chinese and not to try to drag their dead body into their possession as it involves greater risk of life and there is danger of more casualties. If that be the case, I would like to know whether Government are reconsidering its whole policy and attitude in this regard ?

Secondly, I would like to know the contents of the Hindi text which has been referred to by the Hon. Minister and below which our officer has signed. That text should kindly be read in the House. I want to know whether our officers are entitled to sign any paper ? If they wanted to give the receipt of the dead bodies, they should have written it themselves. There was no need for signing a Chinese document.

श्री स्वर्ण सिंह : अपने प्रश्न के आरम्भ में माननीय सदस्य ने जिस अनुदेश का उल्लेख किया है, यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई अनुदेश नहीं हो सकता । किसी स्थान पर संघर्ष होने पर यह स्थानीय सेनापतियों द्वारा निर्णय किया जाता है कि क्या किया जाये तथा यह कर्तव्य संघर्ष में लड़ने वाले व्यक्तियों का है कि वह किस प्रकार कार्यवाही करें।

माननीय सदस्य ने जिस अनुदेश का उल्लेख किया है ऐसा कोई अनुदेश नहीं दिया गया है और इसलिये नीति पर पुनर्विचार करने तथा इस बारे में दिये गये अनुदेशों में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सभा पटल पर एम मुद्रित दस्तावेज रखूंगा, जिसमें हिन्दी तथा चीनी दोनों भाषाओं में वह विषय दिया हुआ है। माननीय सदस्य उसे पढ़ सकते हैं।

Shri Nath Pai: We want that that statement should be read.

अध्यक्ष महोदय : वह उसे सभा पटल पर रखेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : दस्तावेज में लिखित बातों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं देवनागरी लिपि नहीं जानता हूँ ।

Shri Randhir Singh: Mr. Speaker, through you I want to know from the Hon. Minister whether it is not a fact that to counter the propaganda being carried on by the Chinese, a daily programme in Chinese language is broadcast from 4·00 A. M. to 10·00-

11·00 A. M. on behalf of our defence forces ? Is it not a fact that a memorial of late Pt. Jawaharlal Nehru has been set up, at that place in Nathula, where he once paid a visit and beyond that fences have been installed and beyond that at Camel Bridge Nathula 40 to 50 military posts have been set up and that is the place where casualities suffered by the Chinese at the hands of our Jawans from Haryana, Punjab and other northern states of India were ten times more than the casualities sufferred by us ? Is it not a fact that the moral of our armed forces is ten times high than their Chinese counterpart and at that time when a Parliamentary Delegation of which I was a member visited that place, it was seen that the Chinese had hidden themselves at our sight ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य उस शिष्ट मंडल के जो वहाँ गया था, एक सदस्य थे तथा उन्होंने अपने संस्मरण बताये हैं, जो अधिकतर सच है ।

Shri Lakhan Lal Kapoor: I want to know the reasons as to why Chinese started firing at that place ? I want to know whether the Chinese made an attempt to cross over the border to our side, where our forces were guarding it ? Are our forces uncovered there and whether no bunkers have been constructed which may give protection to our forces and whether that was the reason why we suffered heavy casualities ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान कुछ दिन पहले मैं सभा पटल पर एक विवरण रख चुका हूँ जिसमें सब घटनाओं का ब्यौरा दिया हुआ है । चीनियों द्वारा हमला उस समय किया गया, जब हमारे जवान कुछ तारों को खेचने का प्रयत्न कर रहे थे । जमीनदोज मोर्चों में बैठे बैठे वे इस काम को नहीं कर सकते थे। वे खुले मैदान में थे और वे हमारे क्षेत्र में थे । हमने जमीनदोज मोर्चों बनाये हुये हैं तथा सुरक्षा के अन्य सामान्य सैनिक प्रबन्ध भी किये हुये हैं । जिन माननीय सदस्यों ने उस स्थान को देखा है, वे इस बात को जानते हैं ।

श्री नायनार : श्रीमान्, मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगे । मैं जानना चाहता हूँ कि चीनियों द्वारा कितने भारतीय सैनिकों के शव वापस किये गये और हमने कितने चीनियों के शव उन्हें लौटाये ? प्रतिरक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में सही आँकड़े बतायें ? मैं जानना चाहता हूँ कि चीनियों को कितने शव लौटाये गये ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ हमने चीनियों को कोई शव नहीं लौटाया ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the Ministry of Defence have tried to know from the Ministry of Information and Broadcasting the reasons of those news which were broadcast from the All India Radio, New Delhi at the time of Chinese aggression, in which it was stated that India attacked China, and which were hardly objected to by the then Prime Minister, Jawahar Lal Nehru and this Parliament and whether any action has been taken against those officers who were found responsible for that and whether those news have not been quoted in these news now which have been explioted against India ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य वर्ष 1962 के बारे में पूछ रहे हैं । मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इस बार हमारा समाचार प्रसारण संतोषजनक रहा है ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि उस समय जब यह प्रचार किया जा रहा था, तो सेना के गुप्तचर विभाग द्वारा यह पता लग गया था कि उस बार छुम्बी घाटी से जिसे बहुत तनावपूर्ण क्षेत्र समझा जाता है, आक्रमण किया जायेगा ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या छुम्बी घाटी से आक्रमण को रोकने के लिये पर्याप्त एहतियाती उपाय किये गये थे, जैसा कि भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री चवन ने आश्वासन दिलाया था । क्या छुम्बी घाटी से हमले को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की गई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : नाथूला तथा चोला छुम्बी घाटी से ऊँचाई पर हैं । जब कोई हमला किया जाता है, तो वह इसी ओर से किया जाता है । माननीय सदस्य शायद उस क्षेत्र के भूगोल से परिचित नहीं हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : वर्ष 1964 में जब यह प्रश्न उठाया गया था, तब मैंने बताया था कि छुम्बी घाटी बहुत तनावपूर्ण स्थान है, जहाँ से हमला किया जा सकता है तथा प्रतिरक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसकी पर्याप्त हिफाजत की जायेगी । फिर भी परिणाम यह हुआ है हमारे सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए । क्या वह हमें अब यह आश्वासन दे सकते हैं कि उस की हिफाजत की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी हिफाजत की जाती है ।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि नाथूला तथा चोला-दोनों स्थानों पर चीनियों द्वारा अचानक हमला किया गया था तथा वे भारी संख्या में हमारे सैनिकों को हताहत करने में सफल हुए थे ? क्या यह भी सच है कि नाथूला पर हमारे 65 व्यक्ति मारे गये तथा 145 घायल हुए और चोला पर 21 मारे गये तथा 21 घायल हुए ? क्या यह भी सच है कि जब हमारे जवानों ने हमले का उत्तर दिया तो हमारा पलड़ा भारी था तथा चीनियों ने वायु सेना का प्रयोग करने की धमकी दी थी तथा इसके परिणामस्वरूप हमारी ओर से गोलीबारी बन्द कर दी गई, हालांकि चीनी उत्तेजनात्मक कार्यवाही करते रहे थे ? यदि हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमने एकतरफा गोलीबारी बन्द क्यों की, जब कि हमला चीनियों द्वारा किया गया था और हम अपनी रक्षा कर रहे थे, न कि उनपर हमला कर रहे थे ?

श्री स्वर्ण सिंह : बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं तथा प्रत्येक का अलग उत्तर देना आसान नहीं है । मारे गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में तथा तदुपरान्त की घटनाओं के बारे में मैं एक विवरण सभा पटल पर रख चुका हूँ । अचानक हमले के इस प्रश्न का उत्तर भी मैं प्रातः दे चुका हूँ । शायद मानीनय सदस्य उस समय सभा में उपस्थिति नहीं थे, जब मैंने उत्तर दिया था । पिछले दो प्रश्न चीन की तथाकथित धमकी से सम्बन्धित हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : यह तथा कथित धमकी नहीं है । यह वास्तविक धमकी है ।

श्री स्वर्ण सिंह : जिस किसी धमकी का उल्लेख श्री बलराज मधोक द्वारा किया जाता है, वह तथाकथित धमकी होती है ।

श्री नाथ पाई : नहीं, नहीं ।

श्री स्वर्ण सिंह : जो भी हो, हमें शब्दों के लिये नही लड़ना चाहिये। हमें तथ्यों पर विचार करना है। यह सच है कि तीसरे दिन अथवा इसके आसपास चीनियों ने अपने लाऊड-स्पीकरों द्वारा कहा था कि यदि भारत की ओर से हमला बन्द नहीं किया गया, तो वे अपनी वायुसेना का प्रयोग करेंगे। परन्तु यह एक बहुत रोचक बात है कि जब यह समाचार भारतीय समाचारपत्रों में छपा तो पेकिंग रेडियों तथा पेकिंग के समाचार पत्रों ने यह कह कर कि यह केवल भारत की कल्पना है उस का पूर्ण रूप से खण्डन किया था। उनके रेडियो द्वारा इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मैं उन विभिन्न तरीकों का उल्लेख कर रहा हूँ जिनसे चीनी अपना प्रचार कार्य करते हैं। कोई कुछ कहता है और दूसरा उनका खण्डन कर देता है। कभी कभी वे उसकी पुष्टी कर देते हैं। इस तरह सब काम किया जाता है।

Shri Madhu Limaye : And you are pressurised by that?

श्री स्वर्ण सिंह : उत्तेजना तथा घबराहट का प्रदर्शन करके माननीय सदस्य भारत की अपेक्षा चीन की हित सिद्धि कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye: Are you not ashamed of talking like this? You are handing over our soil and blaming us. This Government has become shameless.

श्री स्वर्ण सिंह : यह सर्वथा गलत है।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति।

श्री स्वर्ण सिंह : बहुत समय से हम इस प्रकार की आधारहीन एवं आक्रमणात्मक बातें सहन करते रहे हैं। जैसा कि श्री बलराज मधोक ने कहा है यह सच है कि चीनियों द्वारा अचानक हमला किया गया था, तथापि हमारे सैनिकों ने परमवीरता का प्रदर्शन किया और यह हम सब का परम कर्तव्य है कि हम उनकी वीरता, दिमागी सूझ बूझ तथा शीघ्र कार्यक्षमता की सरहाना करें, परन्तु माननीय सदस्य उनके महत्व को तुच्छ करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : हम आपको याद दिला रहे है कि लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और आप आराम से बैठे हैं। उनकी याद की जानी चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे यह जान कर हर्ष हुआ कि श्री सोंधी आराम से नहीं बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति इस प्रकार सभा में चर्चा नहीं चलाई जा सकती।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं श्री बलराज मधोक के प्रश्न का उत्तर दे रहा था। उन्होंने कहा था कि चीनियों ने ऐसा कहा था इस बात का कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार ने जो कार्यवाही की है वह इस लिये की है क्योंकि चीनियों ने वायुसेना के इस्तेमाल की धमकी दी थी। आप को याद होगा हमने आरम्भ में ही कहा था कि दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिये सहमत हो जाना चाहिये, क्यों कि हम समझे थे कि यह ऐसा हमला नहीं है जिसे सारी सीमा पर हमला समझा जाये, परन्तु हम कहते थे कि यह एक स्थानीय घटना है। इस लिये हमने आरम्भ में ही युद्ध-

विराम का प्रस्ताव रख कर उचित कार्यवाही की थी और हम इसी बात पर ही जोर देते रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : श्रीमान, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न था कि जब उन्होंने हम पर हमला किया था, तो योजना बना कर किया था और जब हमने उनके हमले का उत्तर दिया तो हमें यह पूर्ण अधिकार था कि हम योजना बना कर ऐसा करें। हम अपने जवानों तथा अधिकारियों की तहेदिल से सराहना करते हैं कि उन्होने बड़ी वीरता का परिचय दिया। चीनियों ने हवाई सेना इस्तेमाल करने की धमकी दी, क्योंकि वह हमारे हमले का मुकाबला नहीं कर सके। फिर हमने एकतरफा गोलीबारी बन्द कर दी, हालाँकि वे अपनी तोपों और मोर्टारों से गोलियां चलाते रहे। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है। इसे बार-बार दोहराया जा रहा है।

श्री रा० बरुआ : उस दस्तावेज के बारे में जिस पर हमारे सैनिक अधिकारी तथा चीनी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, यदि मैं ठीक समझा हूँ तो माननीय मंत्री चीनी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पढ़ रहे थे। इससे क्या हम यह समझे कि हमारे कार्यालय में कोई प्रमाणीकृत प्रति प्राप्त नहीं हुई है तथा इसीसे यह उलझन पैदा हुई है? यदि हां, तो सरकार इस बात का क्या उत्तर देगी कि उस दस्तावेज की जिस पर दो स्वतंत्र देशों के हस्ताक्षर हुए है प्रमाणीकृत प्रति प्राप्त क्यों नहीं हुई ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह उस प्रकार का प्रमाणिकृत दस्तावेज नहीं है, जिस पर दो देशों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। यह एक साधारण व्यवहार है कि एक पक्ष द्वारा रसीद पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, तथा उसे दूसरे पक्ष को दे दिया जाता है। चीनियों द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रश्न नहीं था। यह ऐसा दस्तावेज नहीं था, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते ।यह तो एक प्रकार की रसीद थी।

श्री रा० बरुआ : क्या हमारे पक्ष द्वारा उस की प्रति रखी गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर आधे घण्टे का समय लग चुका है (**अन्तर्बाधायें**)

श्री कृष्ण मूर्ति : नाथूला क्षेत्र के विभिन्न अधिकारियों तथा क्षेत्र सेनापतियों ने कहा है कि कि 11तथा 12 सितम्बर को जब चीनियों ने उन पर आक्रमण किया, तो उन्हें भारी हार खानी पड़ी और 13 तथा 14 सितम्बर को उन्हें भारी विजय प्राप्त हुई। अब अचानक ही बिना किसी सैनिक कारण के नई दिल्ली से राजनैतिक अधिकारी ने तार भेज दिया कि हमें गोलीबारी बन्द करनी चाहिये, हालांकि चीनियों की गोलीबारी अभी जारी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह अनुदेश भेजने से पहले स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया था ? जब हमारे जवान कठिनाइयों तथा विपरीत परस्थितियों के बावजूद इन ऊंचाई पर लड़ रहे थे तो 14 तारीख को नई दिल्ली से क्षेत्र सेनापतियों को यह अनुदेश क्यों दिये गये कि गोलीबारी बन्द की जाये, हालांकि हमने चीनियों को भारी नुक्सान पहुंचाया था।

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना गलत है कि हमने केवल तीसरे दिन चीनियों को भारी मार दी थी। पहले तथा दूसरे दिन भी हमारे जवानों ने बहुत वीरता का परिचय दिया था ।

श्री कृष्ण मूर्ति : मैं 14 सितम्बर की घटना की बात कर रहा हूँ ।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ हमने पहले ही दिन स्थिति पर काबू पा लिया था। हमने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, परन्तु उसका कारण वह नहीं था, जो मननीय सदस्य ने बताया है, परन्तु वह तो हमारी उसी नीति का अनुसरण था, जिसकी घोषणा हम ने पहले अथवा दूसरे दिन की थी ।

Shri Achal Singh : On a point of order, Sir.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता । कृपया बैठ जाइये । अगला प्रश्न ।

पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों का प्रशिक्षण

* 122. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मरंडी :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक- कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अगस्त, 1967 में लगभग 300 मिजो विद्रोही मिजो पहाड़ी जिले में आ गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोधपत्र भेजा गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) (क) जी हाँ ।

(ख) खबर है कि जुलाई 1967 में लगभग 300 मिजो विद्रोही पूर्वी पाकिस्तान से मिजो पहाड़ियों में चले गए ।

(ग) पाकिस्तान सरकार के पास कई विरोध-पत्र भेजे जा चुके हैं लेकिन पाकिस्तान ने मिजो विद्रोहियों को कोई सहायता देने से बार-बार इनकार किया है ।

(घ) सीमा पर कठोर सुरक्षात्मक उपाय बरते गए हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, the present question relates to the Mizo rebels then why it is being answered by the Minister of External Affairs? Does our Government treat Mizo land as a foreign country ?

श्री स० मो० बनर्जी : यह इतना छोटा मसला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कई वर्षों से किया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye: This answer can be given by the Defence Minister or the Home Minister.

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न पूर्वी पाकिस्तान में प्रशिक्षण के बारे में है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह प्रश्न पाकिस्तान में प्रशिक्षण के बारे में है । अतः गृह कार्य मंत्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह प्रश्न देश के भीतरी मामलों के बारे में नहीं है। यह पाकिस्तान के बारे में है ।

Shri A. B. Vajpayee: Sir, you kindly also give some consideration to it, the Government is also considering over it. Questions have already been asked regarding Mizos and their going away to Pakistan. The Hon. Home Minister has been answering such questions so far. Now, if some change is to be effected it should be effected with the knowledge of the House.

अध्यक्ष महोदय : कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । यह प्रश्न पाकिस्तान में प्रशिक्षण के बारे में है जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है । यदि उन्हें पाकिस्तान के उच्चयुक्त से कोई जानकारी लेनी है तो केवल वैदेशिक कार्य मंत्रालय ही उनसे जानकारी ले सकता है । गृह कार्य मंत्रालय का इससे कोई तालुक नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : Explosions have taken place recently and a statement has been given by two Mizos that Pakistan has a hand in these explosions. So, may I know the action Government has taken in this regard ? May I know whether Pakistan is really involved in it, if so, the steps Government has taken to prevent such happenings ?

Shri B. R. Bhagat : We admit that Pakistan is helping them in training and otner works and we have lodged a strong protest with the Pakistan Government in this connection.

Shri Yashpal Singh : The Government of India has been protesting for the last sixteen years but of no avail. When this thing is beyond your power then why don't you give up making efforts ? I would like to know the steps Government has taken to ensure that the hostiles don't enter our borders ?

Shri B. R. Bhagat : In order to check their entry we have safe-guarded our borders but our borders are so vast that some people do enter somehow or the other. On the other hand we are fully prepared.

An Hon. Member : The borders should be shortened.

Shri Ram Sewak : The Hon Minister has just now told that 300 Mizo hostiles had gone to Pakistan in July, 1967. May I know when did Government get this information and through which route they had gone there ? Is it a fact that Government had got this information while they were going, if so, what steps were taken to prevent them ?

Shri B. R. Bhagat : I said they came from there and not that they went there.

Shri Ram Sewak Yadav: I want to know whether Government had received this information when the hostile Mizos were going to Pakistan, if so, what steps were taken to prevent them and through which route they had gone there ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पाकिस्तान जाने से रोकने के लिये प्रयास किया गया था।

श्री ब० रा० भगत : विशेष कर यह सीमा बड़ी कठिनाई वाली सीमा है। सब उपाय करने के बावजूद भी हम उन्हें पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं। कुछ व्यक्ति दूसरे राज्यक्षेत्र में घुस ही सकते है। हम निरंतर निगरानी करते हैं और हमने लोगों को जाने से रोका है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : 300 लोग, एक दो नहीं।

Shri Ram Sewak Yadav : After how long Government came to know about their going to Pakistan ?

श्री ब० रा० भगत : हमने उन्हें देश से बाहर जाने और भीतर आने से रोका है ।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या सरकार यह महसूस करती है कि पूर्वी पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने के पश्चात् मिजो विद्रोहियों की गतिविधियां न केवल मिजो पहाड़ी जिले में बल्कि कथर जिले और त्रिपुरा में बढ़ गई है। क्या सरकार का विचार वहां पर सैनिक राज्य स्थापित करने का है क्योंकि मिजो जिले में असैनिक प्रशासन असफल रहा है ।

श्री ब० रा० भगत : यह कहना बहुत कठिन है के प्रशिक्षण लेने वाले दल की गतिविधियां बढ़ी है परन्तु वहां पर खतरा अवश्य है तथा हमारा सुरक्षा दल और प्रशासन इस बात को ध्यान में रख रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : Keeping in view the riots which had taken place in Mizo hills and then going of Mizos to Pakistan for getting training the Government had given more powers to the armed forces there as a result of which law and order had prevailed there. But since these powers of the military have been curtailed they have again started going to Pakistan for getting training and riots have also started taking place in Mizo hills. So, may I know whether the Ministry of External Affairs has again started consulting the Home Ministry to give more powers to military there so that such tendencies may be put under control.

Shri B. R. Bhagat: Consultations take place every now and then. Defence Ministry and Ministry of External Affairs join together on this issue and as I have already said every effort is being made to see that those persons who have gone there don't come back. Efforts have also been made to prevent their entry and such efforts will be made in future also.

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, you might have listened to my question. My question was that under these circumstances the Ministry of External Affairs is having consultations with the Defence Ministry. The Hon. Minister has said that efforts are being

made constantly. So, I want to know that under the new circumstances that have taken place what sort of co-operation the Ministry of External Affairs expects from the Ministry of Defence to curb such tendencies ?

Shri B. R. Bhagat : I have said that it is a question concerning both the Ministries and they do consult each other.

Shri Prakash Vir Shastri : The question is regarding the new circumstances that have taken place.

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

इस मामले का सम्बन्ध वैदेशिक कार्य मंत्रालय से नहीं है परन्तु जैसे पहले बताया जा चुका है यह प्रश्न हमारे पास इसलिये आया क्योंकि यह वैदेशिक कार्य मंत्रालय को लिखा गया था और दूसरे इसका सम्बन्ध मीजो लोगों के पाकिस्तान जाने के बारे में है। पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजना हमारा काम है परन्तु जहाँ तक मीजो पहाड़ियों में कार्यवाही करने के प्रश्न का सम्बन्ध है यह इस मंत्रालय का काम नहीं है, यह काम गृह-कार्य मंत्रालय अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय का है ।

श्री रूप नाथ ब्रह्मा : क्या मैं जान सकता हूँ कि मीजो पहाड़ियों तथा पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या वहां पर सीमा सुरक्षा दल काफी है ?

श्री ब० रा० भगत : सुरक्षा उपाय सुदृढ़ कर दिये गये हैं। तथा सुरक्षा दल भी काफी है।

श्री रूप नाथ ब्रह्मा : सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत: मैं इस प्रश्न का अभी उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री ने यह ठीक ही कहा है कि मीजो पहाड़ियों के अन्तरिक मामलों को देखना गृह-कार्य मंत्रालय का काम है परन्तु उनसे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनको इस बात का पता है कि आसाम में मीजो पहाड़ी के जिले का तीन-चौथाई भाग अब भी मीजो विद्रोहियो के नियंत्रण में है तथा मीजो विद्रोहियों और नागा विद्रोहियों के बीच पारस्परिक सैनिक सम्बन्ध है तथा पाकिस्तान भारत सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाहियों करने के लिये उन्हें सहायता देता है, उसने उन्हें शस्त्र भेजे हैं और वह मीजो विद्रोहियों और नागा विद्रोहियों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षण देने के लिये शिविर बना रहा है। माननीय मीजो ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजे हैं परन्तु उन विरोध पत्रों का क्या होता है यह सब को पता ही है पाकिस्तान उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पूर्वी पाकिस्तान में शिविर है और

पूर्वी पाकिस्तान मीजो विद्रोहियों और नागा विद्रोहियों को शस्त्र भी दे रहा है और यदि हाँ, तो क्या हमारी सरकार पाकिस्तान को यह चेतावनी देगी कि यदि वह अपने देश में छापामार प्रशिक्षण शिविर को समाप्त नहीं करता है और यदि वह नागा विद्रोहियों और मीजो विद्रोहियों को शस्त्रास्त्र देना बन्द नहीं करता है तो हमारी सेना पाकिस्तान पर चढ़ायी कर देगी और हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग इस के बारे में क्या सोचते है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पाकिस्तान को ऐसी चुनौती देने वाली है या नहीं ?

श्री बलराज मधोक : वे पाकिस्तान को इसके लिये सराहना करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : मुझे इसका उत्तर प्रधान मंत्री से मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराज मधोक तीन प्रश्न पहले पूछ चुके हैं । मैं उन्हें पहले ही अवसर दे चुका हूँ ।

श्री ब० रा० भगत : अन्तिम प्रश्न तो कार्यवाही के लिये सुझाव है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ : ... ...

श्री हेम बरुआ : मैं प्रधान मंत्री से इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वह पाकिस्तान को ऐसी चेतावती देंगी या नहीं । अन्यथा वह सारा पूर्वी सीमा का क्षेत्र जहाँ से चुनकर मैं यहां आया हूँ और जिसे सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीति के कारण कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले ही एक से अधिक प्रश्न पूछ चुके है । अब प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देने दीजिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस मामले में श्री माननीय सदस्य ने रुचि ली मैं उसकी सराहना करती हूँ । निस्संदेह यह एक गम्भीर मामला है और हम स्थिति से अवगत है । मैं समझती हूँ कि इस सदन में कई प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि पूर्वी पाकिस्तान में ऐसे प्रशिक्षण शिविर हैं और इसीलिये हम विरोध पत्र भेजते रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य का यह दृष्टि कोण कि हमें इस मसले पर लड़ाई लडनी चाहिये वह ऐसी बात है जैसे .....

श्री रंगा : स्थिति बहुत गम्भीर है और हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते ।

श्री नाथ पाई : क्या उन्हें अगले खण्ड को पूरा करना है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वाक्य पूरा कर लेने दीजिये । उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से हम इस मसले पर लड़ाई नहीं कर सकते । मैं समझती हूँ कि इस स्थिति में सुधार करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि देश में ही कुछ कार्यवाही की जाये । हम वे उपाय करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । जैसा मंत्री महोदय ने कहा है हम कई उपाय कर चुके हैं और बहुत से लोगों को सीमा पार करने से रोक दिया गया है । इसके बावजूद कुछ चले ही जाते हैं ।

श्री हेम बरुआ : 300 लोग मीजो पहाड़ियों से पाकिस्तान चले गये हैं और 300 लोग यहां आये हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कुछ लोग अवश्य जाते हैं और कुछ अवश्य आते हैं । हम सीमा के पार जाने और सीमा पार करके देश में आने से रोकने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री स्वैल : समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि मीजों पहाड़ियों में सैनिक शासन कर दिया गया है । इसलिये मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इस खबर में कितनी सच्चाई है तथा क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह पग उठाने की प्रार्थना की थी ।

श्री नाथ पाई : यदि वह ऐसा करने जा रहे है तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, नहीं ?

श्री स्वैल : इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसी प्रार्थना नहीं की गई है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में मीजो समस्या चिर-काल से प्रस्तुत की जा रही है । क्या सरकार इस समस्या को दूर करने के लिये ठोस प्रयत्न करेगी । क्या सरकार अपने सैनिको को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है तथा क्या इस अभियान में हेलीकाप्टरों का प्रयोग किया गया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए सेना को सप्लाई क्यों न किया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : हमें इस समस्या का पूरा ज्ञान है और हम उसे सुलझाने के लिये यथा सम्भव उपाय कर रहे हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यह बता देना चाहती हूँ कि छापामार युद्ध का प्रशिक्षण हमारे अन्य सैनिक प्रशिक्षण का एक भाग है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या सरकार को प्रशिक्षण शिविरों में चीनी में अधिकारियों की उपस्थिति का पता लगा है तथा क्या उन्हें यह भी पता लगा है कि वे हिदायतें देने का काम भी कहते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : हमें जानकारी मिली है कि चीनी अधिकारी कुछ प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेते हैं ।

Manufacture of Electronic Equipments

*126. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the progress made in the manufacture of electronic equipments indigenously in accordance with the recommendation made by the Bhabha Committee to make India self-sufficient in the field of defence equipment ; and

(b) whether it is a fact that his Ministry prefers to purchase electronic equipments from individual industries instead of manufacturing themselves ?

Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) (a) and (b) A statement has been placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The recommendations made by the Bhabha Committee have been accepted by the Government. In addition to defence equipments it is connected with electronic equipments. There has been increase in the quality and quantity of the Bharat Electronics, Indian Telephone Industries and Hindustan Teleprinters.

A new unit has been established for the manufacturing of radar and micro wave plant.

The number of the schemes connected with food products and electrical equipments have been forwarded to the various laboratories. These important steps have been taken, keeping in view the defence requirements of the country. The aim is to make the country self-sufficient in this direction.

(b) The requirement of strategic importance are met with production done at the public sector industries. But the arrangements are being made to have them even in the private sector.

Shri Maharaj Singh: I want to know whether the Bhabha Committee has recommended the manufacturing of electric goods in the public sector or private sector and whether we are going according to the schedule in manufacturing these equipments.

Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

We are going according to the schedule. In order to take follow-up action we have formulated a Committee under the leadership of Dr. Sarabhai. So far as the question of manufacturing the equipments in public and private sectors are concerned, it has been told in reply to part (b) of the question tnat mostly the equipments will be made in public sector. In case we are not able to manufacture equipments in the public sector or if it becomes necessary we can do this work in private sector also.

Shri Maharaj Singh Bharti : Whether it is a fact that the Bhabha Committee recommended to give training to three lakh engineers in the country and whether we will not be able to train them according to the schedule ?

Shrj L. N. Mishra : We have prepared a phased programme in this connection. We have manufactured two plants. We have expanded the Bharat Electorics and Telephone Industries. We have employed people in them and we are working according to schedule.

श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या सरकार को डा० भगवन्तम द्वारा दिये गये वक्तव्य की जानकारी है जिसमें कहा गया है जिस प्रकार से इलैक्ट्रानिक्स उद्योग में प्रगति हो रही है उसके अनुसार अगामी दस वर्षों में हमारी आवश्यकताओं और उत्पादन में 1,400 करोड़ रुपये का अन्तर हो जायेगा जिससे न केवल देश की प्रतिरक्षा की आवश्यकतायें संकट में पड़ जायेंगी बल्कि देश की अन्य आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होंगी ।

श्री ल० ना० मिश्र: जी नहीं, स्थिति ऐसी नहीं है । जहाँ तक हमारी वर्तमान योजना का सम्बन्ध है यदि हम निर्धारित योजना के अनुसार चलते रहे तो हम प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में 1971 तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे । जहां तक देश की अन्य आवश्यकताओं का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में हमें 1975 तक आत्मनिर्भर हो जाना चाहिये ।

अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों तथा अफसरों के लिये सुविधायें

*127. **श्री रणधीर सिंह** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम क्षेत्रों में अथवा उच्च स्थानों पर अथवा कठोर परिस्थितियों में सेवा कर रहे भारतीय सेना के जवानों तथा अधिकारियों को अच्छे भोजन तथा कपड़ों, दुगनी छुट्टी, मनोरंजन तथा परिवहन सुविधायें तथा प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो किस तारीख से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अग्रिम क्षेत्रों में अथवा उच्च स्थानों पर अथवा कठोर परिस्थितियों में सेवा कर रहे भारतीय सेना के जवानों को अतिरिक्त राशन और अतिरिक्त कपड़ा देने के आदेश पहले ही हैं । जहां तक अग्रिम क्षेत्र में सेवा कर रहे सैनिकों की छुट्टी का सम्बन्ध है, वे आवाजाही कैम्प से आरम्भ और समाप्त होती हैं और उनके काम के स्टेशन से नहीं । ये शिविर सामान्यतया रेल के अन्तिम स्टेशन पर लगाये जाते हैं ।

उनको छुट्टी में और रियायत देने का प्रस्ताव नहीं है । अग्रिम क्षेत्रों में सेवा कर रहे सैनिकों के मनोरंजन के लिये प्रति व्यक्ति सुविधा अनुदान और मनोरंजन दल उपलब्ध हैं परन्तु उनमें वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस समय अग्रिम क्षेत्र में सेवा कर रहे पदाधिकारियों और जवानों के परिवारों और उनके समान को पिछले-कार्य के दफ्तर से, भारत में किसी चुने गये निवास तक मुफ्त ले जाने के या उन्हें उस जगह पर रहने के आदेश हैं । इस सम्बन्ध में और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) उक्त विचाराधीन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई निश्चित तारीख देना सम्भव नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

Shri Randhir Singh : The officers and the Jawans posted at the forward areas think of the country or the God or at the most of their families. I want to know whether some facilities like employment, housing and protection from litigations will be provided to their children and their families. If so, the details thereof ?

श्री स्वर्ण सिंह : जिन सुविधाओं के उल्लेख सदस्य महोदय ने किया, उनके दिये जाने का मैं स्वागत करता हूँ। इनमें से कुछ सुविधायें गैर सरकारी संगठन जैसे ऐड टू सोलजरस द्वारा प्रदान की जा रही हैं। जहाँ तक शिक्षा सुविधाओं का सम्बन्ध है सशस्त्र सेना में सेवा कर रहे जवानों के बच्चों राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं । मैं माननीय

सदस्य और सभा से यह अनुरोध करूँगा कि वे राज्य सरकारों पर उन्हें और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये जोर दें ।

Shri Randhir Singh : My second question is whether there is any proposal to give them double leave, allowances and salaries because the salary gets by a peon in Delhi is one and a half times more than the a Jawan who is protecting 50 crores people at the height of fifteen to twenty thousand feet ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उनके वेतन दुगने करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री गिरिराज शरण सिंह : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूँ कि अग्रिम क्षेत्र में विभिन्न यूनिटों के रखने के समय में कमी किये जाने और उनकी बारी की गति में तेजी करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है और मैं इसका उल्लेख सम्बन्धित व्यक्तियों से करूँगा ।

Shri N. A. Khan : I want to know whether it is a fact that their are some officers in forward areas who have not been permitted to leave for homes for five to six years and as a result of this the soldiers have suffered a special type of disease and this fact has been reported to the officers of the forward areas of the Government of India ? Whether the attention of the Government has been drawn to this fact and whether the Government is considering some scheme under which there will be provision for them to visit their homes twice or at least once a year ?

श्री स्वर्ण सिंह : अग्रिम क्षेत्रों में दो वर्ष में एक बार उन्हें किसी भी दर पर वार्षिक छुट्टी लेने का अधिकार है । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि यदि उन्हें इसके विपरीत कोई जानकारी है तो वह मुझे दें । बिना इसके मैं कोई जाँच नहीं कर सकता ।

श्री नम्बियार : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार उन संतप्त परिवारों को पेन्शन देने का है जो अग्रिम क्षेत्र में युद्ध में लड़ते हुये वीरगति को प्राप्त न होकर जिनकी मृत्यु प्रतिदिन का अपना कार्य करते हुये हुई ।

श्री स्वर्ण सिंह : विभिन्न वर्गों को इस प्रकार की पेन्शन देने का प्रश्न इस प्रश्न से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है ।

श्री रंगा : क्या अग्रिम क्षेत्रों में सेवा करना एक प्रकार का दण्ड है जिस प्रकार असैनिक नौकरियों में जिन व्यक्तियों का कार्य संतोषजनक नहीं होता उन्हें दण्डनीय पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री रणधीर सिंह और कांग्रेस के दूसरे सदस्यों ने अग्रिम क्षेत्रों में सेवा करने वाले सैनिकों को अतिरिक्त भत्ते देने का सुझाव दिया तो सरकार ने उस पर उचित विचार नहीं किया । मंत्री महोदय ने सिर्फ यही किया कि मामला विचाराधीन है । ये लोगों को प्रोत्साहन देने का उचित तरीका नहीं है ।

श्री स्वर्ण सिंह :— अग्रिम क्षेत्रों में नियुक्ति की जाना कोई दण्ड का मामला नहीं बल्कि यह

तो उनके लिये बहुत मान का मामला है जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं यह चाहूँगा कि सभा भी इस पर इसी प्रकार विचार करे और इस प्रश्न पर इस प्रकार विचार न करें।

श्री रंगा : ऐसा महसूस करना प्रतिरक्षा मंत्री का काम है।

श्री स्वर्ण सिंह: मैं ऐसा महसूस करता हूँ और यदि माननीय विपक्षी सदस्य भी इसी प्रकार विचार करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जो भी सैनिक अग्रिम क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं चाहे वे पदाधिकारी हैं या जवान हैं, उनके लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी कारण इनको अतिरिक्त कपड़े, राशन और दूसरी सुविधायें प्रदान की जाती हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है अतः मुझे ऐसा कहना पड़ता है। ये सब देश में उपलब्ध होने वाले स्रोतों पर निर्भर है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे सैनिक, पदाधिकारी शस्त्र सेना के लोगों में देश भक्तिकी भावना है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें। हम अपने स्रोतों को ध्यान में रखते हुये अपने समर्थ के अनुसार ऐसा कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि पदाधिकारियों और जवानों को दिये जाने वाली खाद्य सामग्री और कपड़े में जो अन्तर है इसको मंत्री महोदय का किस प्रकार पूरा करने का विचार है ? मुझे अग्रिम क्षेत्रों में सेवा कर रहे जवानों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें कहा गया है कि पदाधिकारियों को दिये जाने वाले कुछ खाने पीने की वस्तुयें और कपड़े उनको देने से इन्कार किया जाता है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दूँगा कि यदि उन्हें आपत्ति न हो तो वे पत्र मुझे दे दें।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं ऐसा नहीं करूगा क्योंकि आप उन्हें दण्ड देंगे और उनको परेशान करेंगे।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने यह कहा कि राज्य सरकारों को सैनिकों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिये। क्या यह सच नहीं है कि अग्रिम क्षेत्रों में सेवा कर रहे सैनिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा भत्ता दिया जाता है ? इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। केन्द्र सरकार स्वयं ही राज्य सरकारों से यह कहने का दायित्व अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती कि राज्य सरकारें उनके बच्चों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करें या ऐसे स्थानों पर स्कूल खोलें जहां उन सैनिकों के बच्चे बिना कठिनाई के शिक्षा प्राप्त कर सकें ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से सैनिकों के बच्चों के लिये विशेष स्कूल खोलने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन सैनिकों के बच्चे देश के विभिन्न भागों के होंगे। इस सम्बन्ध में व्यवहार के योग्य उपाय यह होगा कि उनकी फीस में रियायत करें या उन्हें छात्रवृत्तियाँ दें। मुझे यह जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही ये रियायतें दीं हैं। उन्होंने फीस की छूटें और छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। हम राज्य सरकारों पर यह दबाव डालते रहते हैं कि वे उन्हें इस प्रकार की अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Manufacture of Transmitters

*125. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a factory for the manufacture of transmitters with the collaboration of Yugoslavia;

(b) if so, the progress made in this direction;

(c) the time by which the manuafcture will start;

(d) the pla ce where the proposed factory is likely to be located; and

(e) the broad details of the scheme ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) ; (a) No, Sir.

(b) to (e) Do not arise.

नागाओं का चीन से वापिस आना

*128. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 150 नागा, जो अप्रैल 1967 में चीन चले गये थे, अक्तूबर 1967 में प्रशिक्षण प्राप्त करके तथा हथियारों और गोलाबारूद के साथ भारत वापिस आ गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय सुरक्षा दल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार, नवम्बर 1966 से अप्रैल 1967 तक की अवधि में छिपे नागाओं के तीन दल बर्मा होकर चीन गये थे। उनमें से कुछ अब लौट आये हैं। इस आशय की, हमारे पास कोई ठीक सूचना नहीं है कि उन्हें कितना गोला-बारूद और अन्य सहायता प्राप्त हुई।

(ख) और (ग) नागाओं को हमारी सीमायें चोरी-छिपे पार न करने देने के लिये, निरन्तर सतर्कता बरती जा रही है। बहुत बड़ा और कठिन इलाका होने के कारण कुछ छिपे नागा, जो कि आमतौर से थोड़ी संख्या में घूमते हैं, भारत से चुपके से चले जाते हैं और आ जाते हैं।

पकिस्तान के साथ वार्ता

*130 **श्री हेम बरुआ** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पाकिस्तान के साथ कतिपय पारस्परिक समस्याओं पर बातचीत करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो किन विषयों पर बातचीत करने का प्रस्ताव है तथा इस प्रस्ताव पर बातचीत के सम्बन्ध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बातचीत के लिये कोई तिथि तथा स्थान निश्चित किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) से (ग) जनवरी 1966 में ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर होने के समय से ही भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बारम्बार यह पेशकश की है कि दोनों देशों के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये दोनों के बीच की विभिन्न समस्याओं पर बातचीत की जाये। अक्तूबर 1967 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और वे दोनों देशों के बीच दूर संचार व्यवस्था को 1965 के स्तर पर पुनः लाने पर राजी हुये थे, उसके बाद आज तक किसी खास मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई।

वार्षिक योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाना

*131. **श्री प० गोपालन :** **श्री नम्बियार :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री रमानी :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री उमानाथ :**
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चालू वर्ष की वार्षिक योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने की योजना का परित्याग कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल द्वारा नेताजी की तलवार का सम्मान अभिवादन (गार्ड आफ आनर)

*132. **श्री समर गुह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के कर्यकारी निर्देशक ने मार्च 1967 में जापानी जनरल फुजीरा द्वारा नेताजी संग्रहालय को नेताजी की तलवार भेंट की जाने के समारोह के समय राष्ट्रीय छात्र सेना दल सम्मान अभिवादन देने के लिये पश्चिम बंगाल तथा अन्दमान के राष्ट्रीय छात्र सेना दल के निदेशालय से प्रार्थना की थी;

(ख) क्या उस प्रार्थना को स्वीकार किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय छात्र सेना दल के छात्रों को प्रशिक्षण के लिये अधिकतम समय उपलब्धता कराने की प्राथमिक आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय छात्र सेना दल से गार्ड ऑफ आनर के हकदार प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संख्या निम्नतम कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, विद्या वर्ष चूंकि समाप्त होने वाला है इसलिये कैडेटों के कपड़े और उपकरण वापस ले लिये गये हैं और उनके द्वारा भाग लिया जाना सभव नहीं हो सकता था । फिर भी इस अवसर के लिये सरकार द्वारा सैनिक ब्रास बैंड के प्रयोग की अनुमति दे दी गई थी ।

विमान द्वारा वस्तुओं के गिराये जाने पर होने वाला नुकसान

*133. **श्री क० लकप्पा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965 से विमान द्वारा वस्तुओं के गिराये जाने पर हुई हानियों की परीक्षण के तौर पर कोई जांच की है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल वस्तुओं के कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है; और

(ग) विमानों द्वारा वस्तुयें गिराये जाने पर होने वाली हानि को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1965 से कुछ ऐसी स्वचालित व्यवस्था की गई है जिससे वस्तुयें पृथ्वी पर धीरे-धीरे आती हैं और जो हानि होती है उसकी जाँच स्थानीय फॉर-मेशन कमान्डरों द्वारा की जाती है और ये सेना की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

(ख) नुक्सान होने के विभिन्न कारण हैं जैसे कि भूमि का स्वरूप, मौसम की हालत; वस्तुयें गिराते समय की संचालन स्थिति तथा यह कि किस प्रकार का विमान प्रयोग में लाया गया था । 1966 में पूर्वी थियेटर में औसत तौर पर 3.84 प्रतिशत भार की हानि हुई और पश्चिमी थियेटर में 3.4 प्रतिशत भार की हानि हुई ।

(ग) नुक्सान के कारणों और परिस्थितियों की जाँच निरन्तर रूप से की जाती है और नुक्सान को यथासम्भव कम करने के लिये समय समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं । इन उपायों में मानवीय दक्षता उपकरणों, पैकिंग और वस्तुयें गिराने के क्षेत्रों में सुधार करना शामिल हैं ।

Pakistani Troop Concentration on Jammu and Kashmir Border

*134. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri N. K. Sanghi : **Shri D.N Deb :**
Shri R.R. Singh Deo : **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has concentrated large number of troops along five hundred miles of cease-fire line in Jammu and Kashmir;

(b) whether Government are aware that some Pakistani spies come to Kashmir and send back all sorts of information; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) The Pakisatani troops continue to be in usual strength along the cease-fire line.

(b) and (c) Some Pakistani spies do try to operate in Kashmir with a view to giving information to Pakistan Government continue to be vigilant to foil their designs.

Supply of Arms by Saudi Arabia to Pakistan

135. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Saudi Arabia has decided to supply additional arms to Pakistan.

(b) the nature and quantity of arms supplied so far; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) and (b) Government have seen reports from time to time about Saudi Arabia providing defence equipment to Pakistan but there is no firm evidence pointing to such supplies having been effected.

(c) Government have already made it clear that any such arms assistance would be regarded by them as an unfriendly act and that such assistance would not be conducive to peace on the sub-contenent and would impede the implentation of the Tashkent Declaration.

Purchase of Tungsten Metal

*136. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that this Department had purchased tungsten metal during the last few years from either the Government of Rajasthan or some undertaking of that Government;

(b) if so, the price per ton at which the same was purchased;

(c) the **c.i.f.** import price of the metal at that time;

(d) whether Government have looked into the question that the Government of Rajasthan had sold this metal to the Central Government at Rs. 17,200 per ton, whereas the same was sold by it to private companies at about Rs. 9,500 per ton; and

(e) if so, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra) (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट

*137. **श्री स० मो बनर्जी**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने स्टाफ आर्टिस्ट्स नियमित सरकारी कर्मचारियों के पदों पर अर्थात् सह-सम्पादकों के स्थान पर स्टाफ आर्टिस्ट, अनुवादक/समाचार वाचक के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये सभी आर्टिस्ट्स नौकरी से हटा दिये जायेंगे और उनमें से कुछ आर्टिस्टों को नोटिस दिये गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनके हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) : 23.

(ख) और (ग) सभी असैनिक पदों पर नियुक्तियाँ प्रत्येक श्रेणी के भर्ती सम्बन्धी नियमों के अनुसार करनी होती है। तदनुसार स्टाफ आर्टिस्टों को जिनका लगाया जाना तदर्थ व्यवस्था की प्रकृति का है, अन्ततः बदलना पड़ता है। तथापि आकाशवाणी में असैनिक पदों की कुल श्रेणियों और स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्तियों की स्थिति में संशोधन किया जा रहा है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सम्बन्धित असैनिक पदों को निर्धारित भर्ती-नियमों के अनुसार भरने के कारण नियमित पदों पर काम कर रहे स्टाफ आर्टिस्टों के हितों को कोई नुकसान न हो।

भारतीयों द्वारा कीनिया तथा अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों का परित्याग

*138. **श्री न० कु० साल्वे :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय लोग कीनिया तथा अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों को छोड़ कर अन्य देशों में जा कर बस रहे हैं, क्योंकि उन देशों में अफ्रीकीकरण का कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह):

(क) हाल ही में वहां से (कीनिया से) भारतीय मूल के कुछ लोग आए हैं, लेकिन हमारी सूचना के अनुसार इन लोगों की संख्या इतनी नहीं है जितनी कि कुछ अखबारों की खबरों को देखने से लगती है। कीनिया में हाल ही में आप्रवास कानून लागू किया गया है उससे गैर-नागरिकों की नौकरी पर कतिपय प्रतिबन्ध लग गए हैं, और कीनिया से उनके उत्प्रवास का यही प्रमुख कारण है।

(ख) नए कीनिया आप्रवास अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जिस काम को कीनिया के नागरिक कर सकते हों उस पर विदेशियों को नहीं रखा जाएगा। भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों ने स्थानीय नागरिकता ले ली है यह नया कानून उनके खिलाफ नहीं पड़ता।

राज्यों की वार्षिक योजनाएं

*139. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की वर्ष 1967-68 की वार्षिक योजनाओं के परिव्यय में, योजना आयोग द्वारा अपनी स्वीकृति दिये जाने के बाद, और कटौती कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के इस समय के परिव्ययों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्यों की योजनाओं के परिव्यय में कितनी कटौती की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

U.S.A. Arms From Arab Countries Reaching Pakistan

*141. **Shri Shiv Kumar Shastri** : **Shri Prakash Vir Shastri** :
Dr. Surya Prakash Puri : **Shri Ram Avtar Sharma** :
Shri Ramji Ram:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Goverment are aware that arms supplied to the Arab countries by U.S.A. are reaching Pakistan.

(b) whether any notes have been exchanged between the Government of India and U.S.A. in this regard; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Government have no information about arms supplied to the Arab countries by the U.S.A. reaching Pakistan.

(b) and (c) Do not arise.

राज्यों की योजनाएं

*142. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह मत व्यक्त किया है कि आयोजन राज्यों का परमाधिकार होना चाहिए और वरीयता निर्धारित करने का प्रश्न सम्बन्धित राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वरीयता निर्धारित कर सकें ;

(ख) क्या अधिकतर राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार आयोजन का विकेन्द्रीकरण करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेनाध्यक्ष (चीफ आफ आर्मी स्टाफ) की पाकिस्तान यात्रा

*143. **श्री बलराज मधोक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारती सेनाध्यक्ष (चीफ आफ आर्मी स्टाफ) अक्तूबर 1967 के चतुर्थ सप्ताह में पाकिस्तान गये थे और उन्होंने रावलपिन्डी में पाकिस्तानी मुख्य सेनाध्यक्ष से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इनका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी हाँ।

(ख) दोनों सेनाध्यक्षों के बीच हुई पिछली चर्चा के अनुसरण में बातचीत हुई थी। बातचीत के परिणामस्वरूप यह तय पाया कि :

(एक) कि सीमा विवादों के चिन्हों का फैसला करने के लिये विभिन्न स्तरों पर स्थानीय कमान्डरों की संयुक्त बैठकें होनी चाहिये।

(दो) तावी के दक्षिण की ओर कार्यकारी सीमा तय करने के लिये जो विशिष्ट उपाय किये गए हैं उन्हीं के अनुसार तावी के उत्तर की ओर सीमा को तय करने के लिए भी उपाय किये जाने चाहिये।

(तीन) सीमा के प्रत्येक ओर 1000 मीटर की सीमा रखी जानी चाहिये जहां तक कि सेवा विमानों को जाने की अनुमति हो और उचित सूचना देने पर उन विमानों को इस सीमा से परे भी जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(चार) सामान्य क्षेत्र शकमा लाँग रिज को छोड़ कर जहाँ पर कि वर्तमान पिकेटों का सर्वेक्षण भारत तथा पाकिस्तान दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिये, पिकेटों को खाली करने के सम्बन्ध में प्रत्येक पक्ष द्वारा यू० एन० एम० ओ० जी० आई० पी० का फैसला क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

(पाँच) पाकिस्तान की ओर के सम्बन्ध में सम्पर्क के कुछ स्तर स्वीकार किये गये थे।

पाकिस्तान में ईरान के विमान

144. **श्री नन्दकुमार सोमानी :** **श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'एवियेशन वीक एन्ड स्पेस टेक्नोलोजी' के 7 अगस्त, 1967 के अंक की ओर दिलाया गया है जिस में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि ईरान द्वारा भेजे गये 90 एफ 36 सेवर जेट विमान अभी भी पाकिस्तान में है और वे विमान वहां रहेंगे ?

(ख) क्या इस बारे में हमारे कराँची स्थित उच्चायोग से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तब सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) हमने इस मामले में पूरी सावधानी बरती है और जहां कहीं आवश्यक हुआ, उचित कार्रवाई भी की है। ईरान की सरकार ने हमें कई स्तरों पर आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को मरम्मत, सफाई और परिवर्तन के लिए हवाई जहाज भेजे गए थे और वे अन्ततः ईरान वापस आ जाएंगे। ईरान सरकार ने हमें यह भी बताया है कि बहुत से हवाई जहाज ईरान वापस आ चुके हैं। लेकिन भारत सरकार को बराबर ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि ये जहाज अब भी पाकिस्तान में हैं।

नाथूला की मुठभेडों के बारे में समाचार-पत्र वालों को हिदायतें

*145. **श्री शारदा नन्द :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री श्री चन्द गोयल :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1967 के दूसरे सप्ताह में नाथूला की मुठभेड़ के दौरान दिल्ली में प्रतिरक्षा अधिकारियों द्वारा केवल एक बार 12 सितम्बर, 1967 को प्रेस को संक्षिप्त रूप स्थिति समझाई गई थी;

(ख) क्या गंगटोक में नियुक्त पत्रकारों और वहां पहुंचे टेलीविजन के संवाददाताओं को गोलीबारी बन्द होने के लगभग दो सप्ताह पश्चात् 28 सितम्बर, 1967 को वहां जाने की अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या सरकारी फोटोग्राफर युद्ध बन्द होने के पश्चात नाथूला पहुंचा था, और

(घ) सरकार द्वारा हमारे प्रतिरक्षा प्रचार की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) नाथूला में गोलीबारी की पूरी अवधि के दौरान सरकारी प्रवक्ता ने पत्रकारों को एक संगठित सामान्य ब्रीफिंग के अतिरिक्त प्रायः गैर-अनुसूचित ब्रीफिंग भी दी थी।

(ख) सामान्य रूप से सभी क्षेत्र के पत्रकारों के दौरों का प्रबन्ध किया जाता है। समाचारपत्रों के संवाददाताओं के दरों का प्रबन्ध स्थिति से सम्बन्धित गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया गया था। नाथूला की यात्रा करने के लिये प्रेस के चार दलों को 25 सितम्बर 1967 से बागडोगरा के बाहर सुविधाएं दी गई थीं। जिन दलों ने नाथूला का दौरा किया उनमें गंबटोक स्थित प्रेस संवाददाता भी थे।

(ग) सरकारी फोटोग्राफर और साइन कैमरा मैन नाथूला में 15 सितम्बर को पहुंचे। इस बीच समाचारों के साथ पहले से उपलब्ध स्थानीय फोटोग्राफर लगाये गये थे।

(घ) प्रतिरक्षा प्रचार में सुधार करने के लिये अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इनमें स्थानीय तथा फील्ड यूनिट स्थापित करना सरकारी संवाददाता दलों तथा समाचारपत्रों के संवाददाताओं द्वारा अग्रिम क्षेत्र के समाचारों का भेजा जाना, बेस प्रेस कैम्पों का स्थापित किया जाना, प्रेससामग्री और फोटोग्राफों आदि की शीघ्र सुरक्षा निकासी करना शामिल है।

'स्पाट लाइट-आसाम का पुनर्गठन' प्रसारण

*146. **श्री जो० ना० हजारिका :**

क्या सूचना और प्रसारण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आकाशवाणी के स्पाट लाइट कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 अगस्त 1967 को आसाम का पुनर्गठन नामक प्रसारण में कही गई बातों की ओर दिलाया गया है जिसके बारे में आसाम सरकार ने आपत्ति उठाई हैं;

(ख) यदि हां तो भविष्य में इस प्रकार की उलझन पैदा न होने के लिए इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस प्रकार के 'स्पाट लाइट' समाचार के प्रसारित किये जाने से पहले उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा जाँच की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हां।

(ख) स्पाट लाइट का फोरम हर प्रकार के दृष्टिकोणों के लिए उपलब्ध है ताकि सुनने वालों को इस बात का अवसर दिया जाए कि वह अपनी राय कायम कर सके और किसी नतीजे पर पहुंच सके। यह केवल उस दृष्टिकोण की जिसे सरकारी कहा जा सके, ही व्याख्या करने के लिए नहीं है।

(ग) स्क्रिप्टों की जांच पड़ताल की जाती है, परन्तु उनका मापदन्ड किसी दृष्टिकोण को पेश करना होता है यदि किसी दृष्टिकोण पर किसी समय अधिक जोर दिया गया हो तो विभिन्न या विपरीत दृष्टिकोण से उसका समंजन कर दिया जाता है। उसमें जो तरीका बरता जाता हैं वह दृष्टिकोण और विपरीत दृष्टिकोण पेश करने का है। ऐसी स्थिति में जहां अनेक प्रसारणों से संतोष हो सकता है वहां किसी एक प्रसारण से असंतोष भी हो सकता है।

चीन से खतरे के बारें में दक्षिण एशिया के देशों के साथ वार्ता

*147. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से खतरे का सामना करने के लिये कार्यवाही के बारे में दक्षिण एशिया के देशो के साथ कोई वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। चीन की धमकियों का मुकाबला करने के उपायों के बारे में सरकार ने किसी देश के साथ बातचीत नहीं की।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नागाओं का चीन चला जाना

*148. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि कुछ छिपे हुए नागा हाल ही में सीमा पार करके चीन चले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार छिपे नागाओं के तीन दल बर्मा होते हुए चीन में प्रवेश कर गए हैं । इनमें से कुछ लौट भी आए हैं । यह सूचना और इन दलों के सदस्यों की ज्ञात संख्या सदन को 24 जुलाई 1967 को तारांकित प्रश्न सं० 1321 और 1330 के पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताई गई थी ।

(ख) सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं । फिर भी कठिन रास्ते और विस्तृत क्षेत्र के कारण कुछ छिपे नागा चोरी-छिपे भारत से आने जाने में सफल हो जाते हैं ।

भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन

*149 **श्री स० कुन्दू**: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हूमायुं कबीर समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए डा० सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की परिषद् द्वारा नियुक्त की गई समिति के विचारों की जानकारी सरकार को है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देशमुख समिति ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है जो इलेक्ट्रानिक कम्पूटर डिविजन (विद्युत चालित संगणक विभाग) का भारत में इसके आरम्भिक कार्य को ध्यान में रखते हुए, पुनर्गठन करने के लिए अर्थोपायों का सुझाव दे; और

(ग) सरकार इसके निर्णयों को कार्यान्वित करने में कितना समय लेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) आशा की जाती है कि महीने के भीतर निर्णय कर लिये जायेंगे और उन्हें यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा ।

भारतीय शिष्टमंडल का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तानी शिष्टमंडल का भारत आना

*150. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज**: क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त में अक्तूबर, 1967 के दौरान कितने सरकारी और गैर सरकारी शिष्टमंडल भारत से पाकिस्तान गये थे ।

(ख) उन शिष्टमंडलों के सदस्यों के नाम क्या है और उनकी यात्रा के उद्देश्य क्या थे;

(ग) इसी अवधि में कितने सरकारी और गैर-सरकारी शिष्टमंडल पाकिस्तान से भारत आये और उनके यहां आने का क्या उद्देश्य था; और

(घ) क्या उन सभी शिष्टमंडलों ने, जो पाकिस्तान की यात्रा पर गये थे कोई प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है और यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में क्या कहा गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1633/67]

नागा नेताओं की विदेशों में भेंट

997. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका स्थित अपने राजनयिक मिशन के माध्यम से तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उस गलत धारणा को दूर करने का प्रयत्न किया है जो मि० ए० जेड० फिजो ने अपनी न्यूयार्क की यात्रा के दौरान उत्पन्न कर दी थी;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दो छिपे नागा नेताओं, मि० थिनू सेलाई और मि० बुइवा, जो फरवरी में भाग कर चीन चले गये थे, और मि० फिजो के बीच चालू वर्ष के उत्तरार्ध में किसी समय यूरोप में भेंट होगी; और

(ग) क्या इन दोनों नागा नेताओं को भारत होकर यूरोप जाने से रोका जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) चूंकि नागालैंड राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है, इसलिए उस राज्य से या उसके निवासियों से सम्बद्ध कोई भी मामला आंतरिक मामला है जिसकी चिंता करना सिर्फ भारत का काम है । श्री फिजो, जो कि अब ब्रिटिश नागरिक हैं, पहले भारतीय नागरिक थे और जैसा कि 10 जुलाई 1967 को लोकसभा में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जबाव में विदेश मंत्री ने बताया था न्याय से बचकर निकल गए थे । बताया जाता है कि, कुछ महीने पहले (अप्रैल/मई 1967) अमरीका की यात्रा के दौरान उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका की किसी सरकारी एजेंसी से किसी प्रकार की सहायता या प्रोत्साहन नहीं मिला और संदर्भ में माननीय सदस्य कृपा कर 22 मई 1967 को इस सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर को देखें जो कि विदेश मंत्री ने दिया था । चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी सदस्य राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए सयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि को इस बारे में कार्यवाही की जरूरत नहीं। रैवैरंड माइकल स्टाक जैसे व्यक्तियों ने नागालैंड से संबद्ध मामलों को..... को गैर-कानूनी तरीके से संयुक्त राष्ट्र की दो समितियों में उठाने की जो कोशिश की उस पर समिति में हमारे प्रतिनिधियों ने समुचित कार्यवाही की ।

(ख) और (ग) हालांकि कोई अधिकृत सूचना सुलभ नहीं है, फिर भी यह सम्भव है कि जिन व्यक्तियों का जिक्र किया गया है वे फिजो से यूनाइटेड किंगडम में मिलने के लिए फर्जी नामों से निकल गए हों और किसी तीसरे देश की सहायता से राष्ट्रयिता ले ली हो । भारत सरकार के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति की कोई प्रार्थना नहीं आई है । किसी भी हालत में भारत से होकर जाने का प्रश्न नहीं उठता । अगर इस तरह की किसा ने प्रार्थना की तो उस पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

पाकिस्तान का सैन्य बल

998. **श्री कवंर लाल गुप्त :** **श्री चरण जीत राय :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना बढ़ा ली है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रतिरोधी उपाय किए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) जैसा कि 22 मई,1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 77 में पहले ही बता दिया गया है कि पाकिस्तान ने 1965 के मुकाबले अपनी सेना की शक्ति दूगनी कर ली है। इसमें आजाद कश्मीर सैनिक दल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त हथियारों में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। हमारी प्रतिरक्षा योजनाओं में इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं का ब्यौरा जन हित में नहीं होगा।

पाकिस्तान के लिए हथियार और पुर्जे

*999. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान को विभिन्न देशों से हथियार और पुर्जे मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में पाकिस्तान को कितने पुर्जे और हथियार मिले ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में अमरीका ने पाकिल्तान को कितने पुर्जे तथा सैनिक सहायता दी है ;

(घ) क्या पाकिस्तान को हथियार देने का भारत ने विरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो अमरीका ने क्या उत्तर दिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) से (ङ) : 1965 में भारत के साथ लड़ाई के बाद से पाकिस्तान न केवल लड़ाई में हुई क्षति को पूरा करने के लिए बल्कि अपनी हथियारी ताकत को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्रोतों से हथियार और उपकरण प्राप्त करने की कोशिश करता रहा है।

हमारी सूचना के अनुसार लड़ाई के बाद से अमरीका ने पाकिस्तान को कोई फौजी मदद नहीं दी है। अप्रैल 1967 में, अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान और भारत, दोनों को घातक हथियारों के फालतू पुर्जे बेचने पर से प्रतिबंध उठा लिया था। इस मामले को वाशिंगटन-स्थित हमारे राजदूतावास और नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास के जरिये अमरीकी सरकार के साथ उठाया गया था। यह बताया गया था कि ऐसा करने से पाकिस्तान की फौजी ताकत बनेगी और इस तरह उप महाद्वीप में तनाव बढ़ेगा।

अमरीका की सरकार ने जबाब दिया है कि पहले दिए गए उपकरण के फालतू पुर्जों को इस तरह की बिक्री से हथियारों की होड़ नहीं बढ़ेगी। अमरीका की सरकार ने हमें यह यकीन भी दिलाया है कि इस तरह की सप्लाई एक-एक मामले की पूरी जांच के बाद ही की जायेगी।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हताहत जवान

1000. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना, वायु सेना तथा नौसेना के कितने जवान भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मारे गये, लापता हुये अथवा घायल हुए ;

(ख) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मारे गये, लापता हुये अथवा घायल हुए तथा उच्च अधिकारी के नाम क्या हैं ; और

(ग) 1965 के संघर्ष में मारे गये किन-किन अधिकारियों के उत्तराधिकारियों को कितना मुआवजा तथा पेंशन दी गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग)

एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1625/67]

पाकिस्तान में नष्ट किये गये मन्दिर तथा गिरजाघर आदि

1001. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1947 से लेकर अब तक पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं, सिखों, तथा बौद्धों के कितने मन्दिर तथा ईसाइयों के कितने गिरजाघर और मिशन नष्ट किये गये ;

(ख) अगस्त, 1947 से लेकर अब तक कितने हिन्दुओं, बौद्धों तथा ईसाइयों को पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ने तथा भारत में आने के लिये मजबूर किया गया ;

(ग) कितने हिन्दू, बौद्ध तथा ईसाई अब भी पूर्वी तथा पश्चिम पाकिस्तान में रह रहे हैं, वे किस-किस सम्प्रदाय के हैं और वे किन-किन स्थानों पर रह रहे हैं ;

(घ) पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्प-संख्यकों के जीवन तथा हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और उसके क्या परिणाम रहे हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान में जो धर्मस्थान नष्ट किए गए, उनकी सही संख्या मालूम नहीं है। सुलभ सूचना के अनुसार, पश्चिम पाकिस्तान के कुछ बड़े-बड़े मंदिरों को छोड़कर सारे हिन्दू मंदिरों की या तो उपेक्षा कर दी गई है अथवा उनपर गैर-कानूनी कब्जा किया हुआ है। सितम्बर 1965 के भारत पाक संघर्ष के दौरान सक्खर में साधवेला जैसे कुछ हिन्दू मंदिरों को

सीलबंद कर दिया गया था। हमारे विरोध-पत्रों के उत्तर में पाकिस्तान के अधिकारियों ने भारत सरकार को सूचना दी है कि पाकिस्तान में संबंद्ध स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हिन्दू मंदिर वापस कर दिया जाय। पाकिस्तान में कुछ सिख गुरुद्वारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है। जहां तक पूर्व पाकिस्तान के बौद्ध मंन्दिरों का संबंध है 1965 के बाद एक बौद्ध विहार अपवित्र किया जा चुका है। पाकिस्तान के ईसाई गिरिजाघरों के बारे में सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) अगस्त 1947 से अगस्त 1967 तक की अवधि में पूर्व पाकिस्तान से कुल मिलाकर 49,35,435 व्यक्ति भारत आ चुके हैं।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1626/67]

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों की दुरवस्था के बारे में पाकिस्तान सरकार से बार-बार शिकायत की है और 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अन्तर्गत उनके दायित्व के प्रति ध्यान दिलाया है जिसमें उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने अल्प संख्यकों को सुरक्षा, पूर्ण स्वतंत्रता और समान अधिकारों की गारंटी दें। खेद है कि वहाँ के अल्संख्यकों की दशा बराबर खराब चली आ रही है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना एक ऐसा दायित्व है जो पाकिस्तान सरकार को अपने राष्ट्रिकों के प्रति निभाना चाहिए।

आकाशवाणी में कर्मचारी

1002. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनके वेतन आदि पर तथा वहाँ के प्रशासन पर प्रतिबर्ष कितना खर्च आता है ;

(ख) देश में कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं और वे कहाँ-कहाँ पर हैं ;

(ग) नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के 20 प्रमुख अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनका मासिक वेतन तथा उपलब्धियाँ कितनीं हैं ;

(घ) आकाशवाणी ने कितने पर्फार्मिग कलाकार, गायक, संगीतज्ञ तथा अन्य सकलाकार नियुक्त किये हुए हैं और पारिश्रमिक के रूप में उन्हें प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है ; और

(ङ) गायकों को किस दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है और उनका चयन कैसे किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क), (घ) और (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरणों में दी हुई है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1627/67]

Communtication Exchanged with China

1003. **Shri G.C. Dixit** : will the Minister of **External Affairs** be please to state:

(a) whether any communications at diplomatic level were exchanged with the Government of People's Republic of China after the termination of the last Session of Parliament; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indra Gandhi) :

(a) Yes; Sir.

(b) From the 12th August uptil the 12th November 26 notes were exchanged between the Government of India and the Government of China. We have received 12 notes and have sent 14. In accordance with our practice these will be laid on the Table of House.

काठमांडू में भारतीय सहायता से बनाया गया हवाई अड्डा

1004. **श्री दामानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में काठमाण्डू के दक्षिण में भारतीय सहायता से एक नया हवाई अड्डा बनाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सहायता की कितनी राशि की व्यवस्था की गई है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अग्रेतर सहायता देने का वचन दिया है और यदि हाँ, तो यह सहायता किस प्रकार की होगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां । नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज ने जनकपुर, नेपाल के हवाई अड्डे का उद्घाटन 24 सितंबर 1967 को किया था ।

(ख) और (ग) भारतीय सहायता से नेपाल में बने हवाई अड्डों की पूरी जानकारी 10 जुलाई 1967 को लोकसभा प्रश्न संख्या 1033 के उत्तर में पहले ही दी जा चुकी है । भारत सरकार को इस सूचना से अधिक कुछ नहीं कहना है ।

गुजरात में सैनिक स्कूल

1005. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने सैनिक स्कूल और कहां-कहाँ पर हैं;

(ख) उनमें कितने छात्र शिक्षा पाते हैं ; और

(ग) उन पर वार्षिक कितना व्यय होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) यह सैनिक स्कूल बालाचाडी में स्थित है।

(ख) 337 (30 सितम्बर 1967 तक)।

(ग) 1966 में (जब छात्रों की संख्या 270 थी) 5.21 लाख रुपये व्यय होते थे। 1967 में 6.4 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

पर्यटकों को वीजा दिया जाना

1006. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप राज्यपाल ने उनके मन्त्रालय से अनुरोध किया है कि विदेशों में स्थित दूतावासों को हिप्पियों जैसे पर्यटकों को वीजा देने से पहले पूरा विचार किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिदिन फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन तथा डेनमार्क से 10 से अधिक हिप्पी दिल्ली आते हैं ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष के कारण सीमा शुल्क तथा प्रवेश के प्रतिबन्धों में दी गई ढील का लाभ उठाने से हिप्पियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) जी नहीं । इस तरह का कोई पत्र नहीं मिला ।

(ख) फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन अफसर, दिल्ली, के कार्यालय में रखे आंकड़ों से पता चलता है कि सितम्बर 1967 के पिछले हफ्ते से 4.5 हिप्पी रोज दिल्ली आ रहे हैं। वे अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देशों से आए हैं।

(ग) हिप्पियों ने ऐसी कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं की है जिससे कि उनके भारत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पड़े। औषधि के आयात-निर्यात करने से संबद्ध हमारे कानूनों का उल्लंघन करने के जो कुछ मामले सामने आए हैं उनपर समुचित कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर दी गई है। उनकी अवांछनीय कार्रवाइयों के विरुद्ध अधिक सतर्कता भी बरती जा रही है।

गुजरात के दैनिक समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन

1007. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 और 1966-67 में केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिये गुजरात के दैनिक समाचारपत्रों को कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए गुजरात राज्य में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों को दी जाने वाली राशि इस प्रकार थी :—

1965-66	..	1,79,398/- रुपए
1666-67	..	1,76,028/- रुपए

गाजा में मारे गये संयुक्त राष्ट्र सेना के भारतीय जवान

1008. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य तथा इसराइल के बीच हाल में हुए युद्ध के दौरान गाजा में तैनात संयुक्त राष्ट्र सेना के भारतीय जवानों के इसराइलियों द्वारा मारे जाने के कारण क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा इसराइल से कोई मुआवजा माँगा है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मास्को स्थित इसराइली दूतावास के माध्यम से इसराइल सरकार को कोई विरोध पत्र दिया था, जिसे उसने लेने से इन्कार कर दिया था;

(ग) सरकारी कार्यवाही के क्या कारण हैं जबकि बम्बई में इसराइल का वाणिज्य दूत है;

(घ) क्या यह सच है कि यह विरोध पत्र बाद में बम्बई स्थित इसराइल के वाणिज्य दूत को दिया गया, जिसने उसे ले लिया ; और

(ङ) क्या भारतीय जवान मारे जाने के सम्बन्ध में इसराइल सरकार ने खेद व्यक्त किया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई में जो कर्मचारी मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्रीय नियमों के अनुसार मुआवजा देता है यानी उन्हीं शर्तों पर जिन पर कि भारत मेंकार्रवाई के दौरान हताहत होने वाले भारती सैनिक कर्मचारियों को दिया जाता है । तदनुसार, गाजा में हताहत होने वाले कर्मचारियों को भारत सरकार ने पेंशन संम्बन्धी नाम के रूप में जितनी रकम दी थी वह संयुक्त राष्ट्र से वसूल करने का विचार है । इस सिलसिले में दावें तैयार किए जा रहे हैं । इसे देखते हुए, इसराइल की सरकार से इस प्रकार का मुआवजा लेने का सवाल नहीं उठता ।

(ख) यह सच है कि भारत सरकार ने मास्को स्थित अपने राजदूतावास के जरिए इस सिलसिले में 8 जून को इसराईल की सरकार को एक विरोध पत्र दिया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से न सिर्फ इन्कार ही किया बल्कि इस पत्र को तेल अवीव भेजने के लिए तत्काल कार्रवाई की ।

(ग) : यह विरोध-पत्र मास्को-स्थित अपने राजदूतावास के जरिए इसलिए दिया गया कि बम्बई में इसराईल का जो कौंसल रहता है उसका काम कौंसली मामलों को देखना है और सामान्यतः उससे राजनयिक मामलों को निबटाने की उम्मीद नहीं की जाती ।

(घ) जैसे कि ऊपर बताया गया है, जब यह विरोध-पत्र इसराईल को ट्रांसमिट किया जा चुका तो इसकी एक प्रति इसराईल के कोंसल को भी सूचनार्थ भेज दी गई ।

(ङ) इसराईल की सरकार ने भारतीय कर्मचारियों के हताहत होने पर खेद प्रकट किया, लेकिन भारतीय टुकड़ी के कर्मचारियों पर जान-बूझकर किए गए हमले की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया ।

Activities of Mohammed Rahamtullah of H. A. L., Bangalore

1009. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one, Mohammed Rahamtullah an employee of the Hindustan Aircraft Ltd. supplied information regarding the activities of aeroplanes of our Air Force to Pakistan during the Indo-Pakistan conflict and tampered with the engines of our aeroplanes ;

(b) if so, the number of the Pakistani agents in our Air Force Service who were detected during the Indo-Pakistan conflict ; and

(c) the action taken by Government against them ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) One Mohammed Rahamtullah, an employee of Hindustan Aircraft Ltd, was apprehended by the Indian Air Force authorities on 8th September 1965, at Yellahanka (Bangalore) on being suspected of transmitting messages to Pakistan on wireless Telegraphy from a parked I. A. F. aircraft.

(b) No person belonging to the Air Force Service suspected of indulging in such anti-National activities, was detected during the Indo-Pakistan conflict in September 1965.

(c) Mohammed Rahamtullah was handed over to the civil police for investigation of the case. The C. I. D. has instituted a case under the Defence of India Rules, 1962 and the trial is in progress in Bangalore.

Statements of Vietnam

1010. **Shri Madhu Limaye** : **Shri M. L. Sondhi** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards various official statements on Vietnam including those made by the Prime Minister and the Defence Minister ;

(b) whether Government have received any information from the Government of North Vietnam to the effect that North Vietnam is now ready to take fresh initiative for holding talks and negotiations with pre-conditions or without conditions ;

(c) if so, the broad outlines thereof , and

(d) whether Government have contacted the U. S. Government in this connection ?

The Prime Minister , Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Government is naturally aware of statements made by the Prime Minister and the Defence Minister.

(b) to (d) The Government of India is in touch with various parties concerned including the U. S. Government and the Government of the Democratic Republic of Vietnam. As the situation in Vietnam is a very delicate one and the information is of a confidential nature, it would not be proper to disclose the reactions of the various parties concerned.

मुख्य सूचना अधिकारी

1011. **श्री अ० क० गोपालन:**
श्री उमानाथ:
श्री रमानी:
श्री अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ने उनके मंत्रालय के अधीन प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरों के वर्तमान मुख्य सूचना अधिकारी के विरुद्ध उनकी इस पद पर नियुक्ति से पहले जाँच की थी;

(ख) क्या जाँच का सम्बन्ध उनके नई दिल्ली में एक बड़ा बंगला बनाने से था;

(ग) क्या जाँच का सम्बन्ध उनके बम्बई की एक विज्ञापन एजेंसी का आतिथ्य तब स्वीकार करने से था जबकि यह विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के निर्देशक थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की इस सम्बन्ध में उपपत्तियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह).

(क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू और काश्मीर के बीच राजपथ

1012. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और श्रीनगर के बीच राजपथ को बार-बार टूटने से रोकने तथा बड़े-बड़े कटावों को रोकने के लिये इसे चौड़ा किया जा रहा है तथा उसमें सुधार किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें अब तक किस प्रकार के सुधार किये गये हैं जिस से यह इतना मजबूत बन जाये कि बढ़ते हुए यातायात का बोझ सहन कर सके और कटावों को रोका जा सके ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) और (ख) जम्मू और श्रीनगर के बीच राजपथ को चौड़ा किया जा रहा है और इसमें ऐसा सुधार किया गया है कि यातायात बिना रुके चले। विनाशकारी कार्यवाही को रोकने तथा सड़क को समतल करने के बहुत से स्थानों पर दिवाल और पुलिया का निर्माण किया गया है।

बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीयों की सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन

1013. **श्री शशि भूषण वाजपेई :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 10 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के उत्तर के संबंन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा में भारतीयों द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्तियों के प्रत्यावर्तन के बारे में बर्मा की सरकार से बातचीत की है; और

(ख) यदि हां तो इसका ब्योरा क्या है तथा क्या निर्णय हुआ है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) इस बारे में बातचीत चल रही है।

हिन्दू नागा शान्ति मिशन

1014: **श्री एस्थोस :**
श्री उमानाथ :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री चक्रपाणि :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दू नागा शान्ति मिशन के उपनेता श्री एस० पी० शास्त्री के व्यक्तव्यों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो श्री शास्त्री ने किस प्रकार के वक्तव्य दिये थे और उनके संगठन का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या उनके वक्तव्य बिल्कुल मनगढ़न्त थे ; और

(घ) इस प्रकार के वक्तव्य देने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) से (ग) सरकार का ध्यान कुछ वक्तव्यों की ओर दिलाया गया जो श्री एस० पी० शास्त्री नाम के किसी व्यक्ति ने नागालैंड के बारे में दिए हैं। उन्होंने जो मसले उठाए हैं, उनकी छानबीन की गई है और यह पाया गया है कि उनके वक्तव्य निराधार हैं।

(घ) लगता है कि उन्होंने संविधान के अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता का उपयोग करने से अधिक कुछ नहीं किया है, इसलिए इस विषय में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

चलचित्रों का वितरण

1015. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
डा० रानेन सेन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है कि चलचित्रों का वितरण तथा उनका प्रदर्शन राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि चलचित्रों का छात्रों के चरित्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

(ख) क्या ऐसा भी एक प्रस्ताव रखा गया है कि चलचित्रों का सेंसर शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के हाल ही के अधिवेशन में यह सुझाव नोट किया गया था कि फिल्मों का वितरण तथा उनका प्रदर्शन सरकार के हाथ में होना चाहिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार की यह सुविचारित राय है कि अन्य जन माध्यमों की तरह, स्वतन्त्र समाज में, ऐसा करना सार्वजनिक हित में नही होगा ।

Steps Taken by Nagaland State Against Chinese Intruders

1017. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Y. S. Kushwah :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Government of Nagaland have made special security arrangements to stop the entry of Chinese intruders into Nagaland ;

(b) if so, whether the State Government have apprised the Central Government also of the activities of the communists in this regard ; and

(c) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) to (c) As the State of Nagaland does not have a common border with any part of China the question of Chinese intruders does not arise. The Government of India in exercise of their constitutional responsibility relating to India's external relations have taken all possible security measures to prevent illegal entry of any person into India.

जालन्धर (पंजाब) में पकड़े गए जाली पारपत्र के मामले

1017. **काशी नाथ पाण्डे :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पुलिस ने जाली पारपत्रों के विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में जालन्धर में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) पंजाब पुलिस ने पासपोर्ट के 16 मामले दर्ज किए हैं और अब तक 33 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं । कहा जाता है कि इनमें से 25 ने जाली सत्यापन प्रमाण-पत्र बनाये, 7 ने अपनी पासपोर्ट की अर्जियों में झूठा विवरण दियां और झूठी शपथ ली और कहा जाता हैं कि 1 ने यूनाइटेड किंगडम जाने के इच्छुक व्यक्तियों को धोखा दिया ।

Gandhi Memorial Fund

1018. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the assistance of Government machinery was obtained in collecting contributions for the Gandhi Memorial Fund;

(b) if so, whether the accounts of this Fund are examined by Government;

(c) whether it is also a fact that only one group has the control over the said Fund; and

(d) whether Government are chalking out any scheme to ensure that the Fund is administered in a democratic manner?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The Fund is managed by a Board of Trustees consisting of leading non-officials. It is governed by the Deed of Declaration of Trust drawn up and registered by the Fund. Government are not directly represented on the Board.

भारत नेपाल सीमा पर कौनाली नदी पर जल विद्युत परियोजना

1019. **श्री बलराज मधोक** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत नेपाल सीमा पर कौनाली नदी पर एक जल विद्युत् परियोजना के निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन का अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) 21 नवम्बर 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1957,3 अप्रैल 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 367 और 26 जून 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3586 में इसी विषय पर उत्तर दिए गए थे। नेपाल की दिलचस्पी ठीक ही है कि क्योंकि कर्नाली थाले में जो बिजली पैदा होगी उसका भारत ही खरीदार होगा।

इस परियोजना का प्रारम्भिक तकनीकी अध्ययन पूरा किया जा चुका है और इस क्षेत्र में बिजली की अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से और आगे अध्ययन किया जा रहा है। पिछले महीने नेपाल की यात्रा के समय उप प्रधान मंत्री ने नेपाल के महामहिम की सरकार को यह आश्वासन दिलाया था कि भारत के हित की दृष्टि से इस परियोजना का तकनीकी आकलन जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इस अध्ययन की गति तीव्र की जा रही है।

बिना विभाग का मंत्री

1020. **श्री श्री धरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना विभाग के मंत्री को कोई विभाग दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हे कौन सा विभाग दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) जी हां, श्री सत्य नारायण सिन्हा अब स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय कानूनों को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करने के बारे में लोक-सभा में पुर:स्थापित विधेयक के बारे में पाकिस्तान का विरोध-पत्र

1021. **श्री मरंडी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने लोक सभा में एक ऐसे विधेयक के पुर: स्थापन का विरोध किया है जिसका उद्देश्य कुछ केन्द्रीय कानूनों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करना है।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सूचित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) पाकिस्तान का विरोध-पत्र भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप है क्योंकि संघ सरकार और इसके अंग राज्य जम्मू तथा कश्मीर के बीच संबंधों का मामला ऐसा है जिसे भारत ही तय कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को इन विचारों से अवगत किया जा चुका है।

Defence Laboratories

1022. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is a ratio of 3 :1 in the number of workers employed on the job of conducting experiments in Defence Laboratories and those who are posted on the administration side;

(b) if so, the nature of duties entrusted to employees posted on the administration side;

(c) whether it is a fact that Five Year Plans of Research and Development Laboratories do not coincide with the Five Year Plans of the country; and

(d) if so, what is the basis of assessing the expenditure and what is the source from which the expenditure is incurred on the plans of these Laboratories during the five years period?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) The ratio between the number of Scientific/Technical Officers and staff to that of Officers and staff on the administration side is 15 :1 approximately.

(b) Recruitment, promotions, discipline, stores, budget, accounting, watch and ward, pay and allowances etc.

(c) Research and Development Five Year Plans coincide with the Fourth Five Year plan period. Individual schemes included in the plan however may extend beyond five years.

(d) The expenditure is related to the cost of various projects and is met from Defence Services Estimates.

Research and Development Projects

1023. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that normally the targets for completion of Research and Development Projects are not fixed and if so, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that the projects are not completed on the due dates ; and

(c) whether Government have enquired into the reasons and if so, the result thereof ?

The **Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra)** :

(a) In the case of most of the development projects the target date for completion is fixed before funds are sanctioned and the project is taken up for execution. Fixing such a target date is, however, not possible in every case.

(b) and (c) subject to unforeseen delays inherent in development work, the time schedules are usually adhered to. Progress of the projects is kept under constant review.

बेरुत स्थित दूतावास में रखे गये सन्दूक की चोरी के सम्बन्ध में की गई शिकायत

1024. **श्री जनार्दनन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरुत स्थित हमारे राजनयिक दूतावास अथवा किसी सम्बन्धित अधिकारी को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त हुई है कि अगस्त और सितम्बर, 1967 में विदेशों का दौरा कर रहे केरल कला मण्डलम कथाकली दल के प्रबन्धक का एक बक्सा कथित रूप से चोरी चला गया था जिसमें धन था, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या संदूक और धन राशि को बरामद करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) केरल कला मंडलम कथकली नर्तक दल के मैनेजर ने बेरुत-स्थित हमारे राजदूतावास को 5 सितम्बर 1967 को यह सूचना दी थी कि कीमती चीजों से भरा उनका एक सूटकेस गुम हो गया था। उन्होंने यह नहीं बताया कि सूटकेस में रुपया-पैसा भी था या नहीं। हमारे राजदूतावास ने इस मामले को तत्काल बाल बैक फैस्विल के अधिकारियों तथा मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स के साथ उठाया। मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स ने राजदूतावास को सूचना दी है कि सूटकेस का 9 सितंबर को फ्रेंकफर्ट पर पता चला जहां से वह 11 सितंबर को एथेन्स भेज

दिया गया और उसके बाद 14 सितंबर को पेरिस भेज दिया गया । ख्याल है कि वह सूटकेस उसके मालिक को पेरिस में दे दिया गया है ।

विज्ञापनों पर व्यय

1025. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशक ने 1965-66 और 1966-67 में समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों पर कितना धन व्यय किया;

(ख) किन-किन समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये गये तथा उन्हें कितनी धनराशि दी गई, और

(ग) अँग्रेजी और हिन्दी के समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों पर पृथक-पृथक कितना धन व्यय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

1965–66	—	82,43,560 रुपए
1966–67	—	77,78,409 रुपए

(ख) भिन्न-भिन्न समाचार-पत्रों को दिए गए विज्ञापनों और उनको दी गई धन-राशि के ब्यौरे के बारे में जो सूचना है वह विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और सम्बन्धित पत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है । सम्बन्धित पत्रों की पूर्व सहमति के बिना इस बारे में इकतरफा सूचना देना अच्छी व्यापार नैतिकता नहीं है ।

(ग)

	1965-66	1966-67
	रुपए	रुपए
अँग्रेजी	44,33,681	45,32,188
हिन्दी	11,03,242	9,38,914

समाचार-पत्रों को विज्ञापन देना

1026. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्रों को विज्ञापन देने में किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) क्या विज्ञापन देने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की गई है अथवा क्या यह काम सम्बन्धित अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है;

(ग) विभिन्न समाचारपत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों की दरों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है और क्या समाचारपत्रों की विज्ञापन-दरें मानी जाती है अथवा ये दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं;

(घ) सरकार किन-किन बातों को ध्यान में रख कर दरें निर्धारित करती है; और

(ङ) वर्ष 1961-62 की दरों के मुकाबले में वर्ष 1965-66 में कितने समाचार-पत्रों के मामले में विज्ञापन का दरें 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई और ये समाचारपत्र कुल समाचार-पत्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)

(क) विज्ञापन देने में सब से बड़ा ध्यान इस बात का रखा जाता है कि हमारे पास जो सीमित धन-राशि उपलब्ध है उसके अन्दर ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विज्ञापन देने के लिए समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का बड़ी सोच समझ के साथ चयन किया जाता है ताकि विज्ञापन उन पढ़ने वालों तक पहुंच जाये जिनके लिए वे हों। खास तौर पर सजावटी विज्ञापन, जिन में आम जनता के लिए संदेश होते हैं, इस तरह दिए जाते हैं कि उनसे हर तरह के लोग लाभ उठा सकें।

(ख) विज्ञापन कुछ निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर दिए जाते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि (क) उनकी खपत प्रभावी हो, (ख) नियमित रूप से प्रकाशित होने हों (ग) उन्हें किस किस्म के लोग पढ़ते हैं और किस भाषा और किस इलाके में विज्ञापन देने का इरादा है, (घ) वे मानी हुई पत्रकारिता के नैतिक स्तरों पर हों (ङ) अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है जैसे कि छपाई का स्तर आदि।

नीति के तौर पर, उन समाचार-पत्रों को विज्ञापन देना रोक दिया जाता है जो साम्प्रदायिक घृणा और अहिंसा को भड़काते हो और जो मानी हुई सामाजिक मर्यादाओं और सार्वजनिक शिष्टाचार और नैतिकता पर प्रहार करें या राष्ट्र विरोधी कामों को प्रोत्साहन दें।

उपरोक्त नीति की परिधि के अन्दर विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशक को अपनी सूझ-बूझ और विवेक से काम लेना होता है।

(ग) और (घ) समाचार-पत्र और पत्रिकाएं अपने-अपने विज्ञापनों की दरें निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं। विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय उन्हीं समाचार पत्रों को इस्तेमाल करता है जिन की दरें उन्हें स्वीकार्य होती हैं।

(ङ) क्योंकि अधिकांश समाचार-पत्रों की हर साल दरें बदलती रहती हैं, इसलिए इस सूचना को एकत्रित और संकलित करने में जो परिश्रम और समय लगेगा वह बहुत अधिक होगा और उस समय भी यह सूचना अधूरी रहेगी और पुरानी हो जाएगी।

पर्वतीय सीमा क्षेत्रों के लिये विशेष अनुभाग (सेल)

1027. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की जलवायु सम्बन्धी हालतों तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख कर वहां की आयोजन संबंधी योजनाओं से सम्बन्धित योजना आयोग में एक विशेष अनुभाग है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अनुभाग का ब्योरा क्या है और उसे क्या काम सौंपा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने राज्य योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत पर्वतीय तथा समावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिये जिलों में योजनाएँ तैयार करें । उनको यह भी सलाह दी गई है कि इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिये एक उचित संगठन का गठन करें । केन्द्र सरकार के मंत्रियों से भी यह अनुरोध किया गया है कि योजना की प्रगति पर निरीक्षण रखने के उद्देश्य से वे विशेष प्रबन्ध करें । योजना आयोग में जहाँ अनुभाग में राज्य की योजना सम्बन्धी कार्य पर्याप्त रूप से किया जाता है, अलग सैल खोलना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

अग्रिम क्षेत्रों में सेवा करने वाले जवानों तथा अफसरों के परिवारों को सुविधायें

1028. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन जवानों और अफसरों के परिवारों को जो बहुत कठिन हालात में अग्रिम क्षेत्रों में तथा अत्युच्च स्थानों पर कार्य कर रहे हैं और अधिक सुविधायें, प्रोत्साहन तथा रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) से (ग) अग्रिम क्षेत्रों में कार्य कर रहे पदाधिकारियों और जावानों को अग्रिम सेवा सुविधाओं के रूप में उनके परिवारों को तथा उनके सामान को पिछले काम के स्थान से भारत में किसी चुने हुए निवास स्थान पर भेजने का भाड़ा या पहले काम के स्थान पर विवाहितों को दिये जाने वाले आवाम में उनके परिवारों को रहने देने को दी जाने वाली सुविधाएँ शामिल हैं । विभिन्न चुने हुए स्टेशनों पर अलग हुए परिवारों को आवास के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है । इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय के वर्ष 1966-67 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ट 18 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिससे 1051 पदाधिकारियों, 460 जूनियर कमीशन आफिसर अन्य श्रेणी के 1518 और युद्ध में भाग न लेने वाले जो परिवार से अलग हो गये हैं, के निवास की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने सैनिक कर्मचारियों के नीचे दिए विभिन्न मामले जिनमें उनके हितों पर प्रभाव पड़ता है, सहायता की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित कराया है :—

(1) बच्चों की शिक्षा ।

(2) असमाजवादी तत्वों द्वारा उन्हें परेशान करने से रोकना ।

(3) जब वे कठिनाई में हों तो डिस्ट्रिक्ट सोलजर्ज सेल्स एण्ड एयरमन्स बोर्ड्स द्वारा सम्बद्ध अधिकार को पहुंच करना ।

(4) निकट के औषधालय, स्वास्थ केन्द्र या अस्पताल के डाक्टर द्वारा उनके घरों में मुफ्त चिकित्सा किया जाना ।

(5) मुकदमे के लिये मुफ्त कानूनी सहायता का दिया जाना ।

(6) यदि उन्होंने आवेदन किया हो, तो राज्य निर्माण बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले मकानों में उन्हें प्राथमिकता देना ।

(7) दौरा करने वाले पदाधिकारियों जैसे तहसीलदार, असिस्टेन्ट डिप्टी कलक्टर और कन्ट्रोलर द्वारा अपने गाँव का दौरा करते समय अपने परिवारों से मिलने देना।

राष्ट्रपति नासिर के विदेशी मामलों के सलाहकार का भारत में आना

1029. **श्री चेंगलराया नायडू : श्री देवेन सेन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति नासिर के विदेशी मामलों के सलाहकार सितम्बर, 1967 के महीने में भारत आये थे और उन्होंने पश्चिम एशिया में शान्ति के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले थे ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) जी हां :

(ख) डाक्टर फौजी की यात्रा से आपसी हित के मामलों पर विचारों के आदान-प्रदान करने का मौका मिला जिनमें पश्चिम एशिया के संकट के समाधान का प्रश्न भी शामिल था।

चीन से नागाओं की वापसी

1030. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत के नागा बर्मा की सीमा की ओर रहते हैं तथा वे भूमिगत नागाओं के साथ निश्चित रूप से सहयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बर्मा सरकार से कहा है कि भूमिगत नागाओं को चीन जाने से रोकने के लिये भारत सरकार की सहायता करे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

(क) जी हां। नागा लोग बड़ी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार बर्मी प्रदेश की तरफ रहते हैं। सरकार के पास जो सूचना सुलभ है, उसके अनुसार छिपे नागाओं को तांग्सा नागाओं से और बर्मा में रहने वाले अन्य नागाओं से कुछ सहायता मिली।

(ख) बर्मा के अधिकारियों ने इस विषय में संभव सहयोग दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-पकिस्तान सर्वेक्षण सम्बन्धी वार्ता

1031. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 तथा 26 सितम्बर, 1967 को ढाका में भारत-पाकिस्तान सर्वेक्षण वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर बातचीत हुई;

(ग) क्या पाकिस्तान ने उस सम्मेलन में बेरूबाड़ी सीमा रेखांकन के प्रश्न पर चर्चा की थी;

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन में इस प्रश्न पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ङ) इस सम्मेलन में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) जी हां : इन तारीखों पर भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक, पश्चिम बंगाल तथा भू अभिलेख एवं सर्वेक्षण निर्देशक, पूर्व-पाकिस्तान, की बैठक ढाका में हुई थी ।

(ख) विचार-विमर्श के मुख्य विषय थे :

(i) पूर्व पाकिस्तान-पश्चिम बंगाल सेक्टर में बाकी सीमाअंकन का काम ।

(ii) सीमांकित क्षेत्रों में लापता और क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भों को फिर से लगाना ।

(iii) अन्य तकनीकी मामले ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता ने बताया कि बेरूबाड़ी का मामला अभी तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने है और न्यायालय व्यादेश (कोर्ट इन्जेक्शन) के खत्म हो जाने पर ही बेरूबाड़ी के सीमाअंकन का कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है ।

(ङ) दोनों पक्ष सीमाअंकन क्षेत्रों में लापता और क्षतिग्रस्त स्तम्भों को फिर लगाने पर सहमत हुए । वे इस सीमा के $1\frac{1}{2}$ मील के शेष हिस्से को भी सीमाअंकन करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने नक्शे तैयार करने और कार्यक्षेत्र (फील्ड वर्क) से संबद्ध कुछ तकनीकी काम भी पूरा किया जो कि 16 नवम्बर से शुरू होने वाला था ।

पंजाब में भूमि का अर्जन

1033. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री रमानी :
श्री उमानाथ :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1964 में खसरा संख्या 1676/3-9 और 1675/1-12 में, पंजाब के जिला रोपड़, तहसील खरड़ ग्राम तथा डाकखाना मुल्लनपुर गरीबदास में स्वर्गीय श्री शादी राम की विधवा श्रीमती पार्वती देवी की भूमि प्रतिरक्षा प्रयोजनों हेतु अर्जित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि के मालिक को मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भूमि के मालिक को भूमि में खेती करने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, सितम्बर 1964 और अप्रैल, 1965 के बीच में पंजाब के जिला रोपड़, तहसील खरड़, मुल्लनपुर गरीबदास तथा फिरोजपुर में श्रीमती पार्वती देवी की 197.71 एकड़ भूमि प्रतिरक्षा प्रयोजनो के लिये अर्जित की गई थी।

(ख) और (ग) श्रीमती पार्वती देवी को 1,777,09 रुपये दिये गये हैं। स्थानीय नागरिक प्राधिकार, जो उनको शीघ्र ही इस राशि का देने का प्रयास कर रही है, ने उन्हें अभी यह राशि नहीं दी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भूमि सरकार की सम्पत्ति हो चुकी है। ना ही उनसे इस भूमि पर खेती करने के लिये अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब का भारत पर आरोप

1034. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान में ढाका में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जिसमें उन्होने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध बड़ी संख्या में सेना जमा रखी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी हैं कि 21 अगस्त 1967 को ढाका जाते हुए राष्ट्रपति अयूब खां ने अखबार वालों को बताया था कि भारत ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर 'भारी संख्या' में सैनिक जमाव किया है और वे अधिकांश संख्या में पश्चिम क्षेत्रीय सीमा में हैं।

(ख) यह खेद की बात है कि इस तरह का बयान किया गया जिसका कोई आधार नहीं है।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र का विकास

1035. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **प्रधान मंत्री** 6 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4779 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र का विकास करने की योजना पर अन्तिम रूप से विचार इस बीच कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में भेजे गये पर्यटक रुचि वाले चलचित्र

1036. **श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्रीमती तारा सप्रे :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इस वर्ष पर्यटक-रूचि के कितने चलचित्र विदेशों में भेजे गये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने भारत के सभी भागों के सम्बन्ध में पर्यटक रुचि वाले चलचित्रों का कोई व्यापक सूची तैयार की है ?

सूचना और प्रसारणमंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) 28, 1 मार्च से 31 अक्तूबर, 1967 तक ।

(ख) जी, नहीं ।

Meetings of Indian and Pakistan Army Commanders

1038. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Dr. Surya Prakash Puri**
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri Ramji Ram :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any meetings of the Indian and Pakistan Army Commanders were held sometime back to resolve the border dispute ;

(b) if so, the main points discussed at these meetings , and

(c) the decisions arrived at and whether those have been implemented ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c) Pursuant to the Tashkent Agreement which provided for meeting,s at various levels on matters of direct concern to both countries, the Chief of Army Staff India and the C-in-C Pakistan Army have so far held 4 meetings. Methods of settling these disputes and certain specific issues arising out of these disputes were determined at these meetings. At a meeting in February, 1966, the GOC-in-C, Eastern Command, India and GOC, 14 Infantry Division, Pakistan arrived at a working agreement with regard to Lathitilla and Bhagalpur areas which were a cause of tension and firing. Besides, a number of meetings at Sector and Sub-Sector Commander levels have been held.

The object of these meetings generally has been to help reduce tension and settle border mis-understandings peacefully. This purpose has been substantially met.

Cultivable Land Around Muradnagar Ordnance Factory

1039. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Ram Autar Sharma : **Shri Ramji Ram :**
Shri Y. S. Kushwah :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether it a fact that cultivable land is lying uncultivated around the Muradnagar Ordnance Factory;

(b) if so, the reasons for not making use of this land.

(c) whether some farmers had submited proposals for cultivating this land; and

(d) if so, the decision taken thereon?

The Minister of state (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Two applications were received for allotment of certain areas of land for cultivation purposes, but these could not be agreed to as the land asked for had already been leased out to Cooperative Societies for cultivation purposes.

श्रीनगर में एक अड्डा बनाने की अमरीकी योजना की रिपोर्ट

1040. **श्री मयाबन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पेकिंग रेडियों के इस प्रसारण की ओर दिलाया गया है कि अमरीका ने भारत की सहमति से श्रीनगर में एक अड्डा स्थापित करने की योजना बनाई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कथन का खण्डन किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हाँ । रेडियो पीकिंग ने एक प्रसारण में कहा है कि 14 अक्तूबर 1967 के पाकिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार "भारत पड़ोसी देशों में जासूसी करने के लिए भारत अधिकृत कश्मीर के श्रीनगर नामक स्थान में एक हवाई अड्डा बनाने की गरज से अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ सहयोग कर रहा है ।"

(ख) और (ग) जी नहीं । यह बयान झूठा और बेहूदा है और सरकार औपचारिक तौर पर इसे खण्डन की संज्ञा देना भी आवश्यक नहीं समझती ।

कलपक्कम में परमाणु विद्युत केन्द्र

1041. **श्री पार्थसारथी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियर परमाणु शक्ति केन्द्र, कलपक्कम का डीजाइन तैयार कर रहे हैं और उसका निर्माण कर रहे हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्युत केन्द्र के लिये आवश्यक स्टीम टर्बाइन भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हाँ ।

(ख) इस बारे में बातचीत हो रही है । हमारी वर्तमान योजनाओं का उद्देश्य है - कि स्टीम टर्बाइन भारत में ही बनाया जाये ।

(ग) भारत में टर्बोजेनरेटर बनाने से मद्रास परमाणु बिजली घर के निर्माण पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत होगी।

परमाणु विद्युत केन्द्र, कलपक्कम

1042. **श्री पार्थसारथी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्पक्कम में थिरियम तथा पुलूटोनियम को मिलाकर यूरेनियम 233 का उत्पादन करके ब्रीडर रियेक्टर टैक्नालोजी का बिकास किया जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस से परमाणु बिजली का उत्पादन करने से हमारे भावी तरीके में परिवर्तन हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) मद्रास परमाणु बिजली घर के समीप ही एक रिऐक्टर विकास केन्द्र स्थापित करने की योजना विचाराधीन है। इस केन्द्र में फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर टैक्नोलाजी का विकास किया जायेगा। फास्ट रिऐक्टरों, जिनमें मूल ईंधन तत्व के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया जायेगा, मैंथोरियम की सहायता से यूरेनियम 233 तैयार करने के सम्बन्ध में भी अध्ययन किये जायेंगे।

(ख) फास्ट ब्रीडर टैक्नोलाजी के विकास से हमारे लिये यह सम्भव हो सकेगा कि हम ऐसे वाणिज्यिक किस्म के फास्ट पावर रिऐक्टर लगा सकें जिनमें जितने ईंधन तत्व की खपत हो उससे ज्यादा ईंधन तत्व तैयार हो जायें। इन रिऐक्टरों में उत्पादित बिजली भी ताप बिजलीघरों में उत्पादित बिजली की अपेक्षा सस्ती होने की सम्भावना है ;

भारतीयों का मलयेशिया का दौरा

1043. **श्री पार्थसारथी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि मलयेशिया सरकार के नेताओं ने, भारत से वहाँ गए कुछ भारतीयों की यात्रा तथा उनकी गतिविधियों का बुरा माना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बिगाड़ने की चेष्टा करने वाले ऐसे भारतीयों की यात्राओं को बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं, लेकिन हमारे हाई कमीशन को इस मामले से अवगत करा दिया गया है।

(ख) जब हमारे हाई कमिश्नर ने मलयेशिया के प्रधान मंत्री से इस मामले पर बातचीत की, तब मलयेशिया के प्रधान मंत्री ने हमारे हाई कमिश्नर को बताया कि उन्हें हमारी नीति के बारे में कोई सन्देह नहीं है और यह मामला कोई बड़े महत्व का नहीं है। इसलिए कोई कदम उठने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Clash in Gun and Shell Factory, Cossipore

1045. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.4384 on the 3rd July, 1967 and state:

(a) whether the enquiry into the causes of the clash that took place in the Gun and Shell Factory at Cossipore, Calcutta has since been submitted;

(b) if so the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra)

(a) As indicated in the reply to Unstarred Question no.4384 on 3rd July 1967. the Report of the Enquiry had already been received at that time.

(b) Trouble started in the Gun and Shell Factory, Cossipore, at about 5.30 PM on 9.5.67 when the workers became agitated about the supply of a spurious brand of cold drink in the Factory canteen. This was immediately tackled by the Officers of the Factory. Soon after this, fresh trouble arose on account of certain allegations about short supply of rations which arrived in a truck at that time. Starting from these two incidents, the agitation became more serious and other labour demands were brought up. The agitation continued overnight and took a violent turn on several occasions with the result that several officers and staff were injured. The Army moved in next morning and the atmosphere calmed down towards the evening of the 10th May 1967.

(c) Does not arise.

राज्यों के योजना बोर्ड

1046. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री बसवन्त :**
श्री मयावन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अब तक राज्य योजना बोर्ड बनाये हैं ; और

(ख) राज्यों में इन योजना बोर्डों का गठन किस प्रकार किया गया है ?

प्रधानमंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) हाल ही में केरल में राज्य योजना बोर्ड बनाया गया है ।

(ख) राज्य के इस योजना बोर्ड के गठन और कार्यों के सम्बन्ध में एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 1628/67] ।

दीवाल समाचारपत्र

1047. **श्री तुलसी दास दासेप्पा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के दृश्य-श्रव्य प्रचार विभाग ने समूचे देश में वितरण करने के लिये दीवाल समाचारपत्र छापना शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस नवीन योजना से विशेष लाभ क्या होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने एक अच्छा दीवाल समाचार-पत्र छपाने का पड़ताली यत्न किया था ।

(ख) आवश्यक धन-राशि की कमी और एक अच्छे दीवाल समाचार पत्र के छापने और उसे जारी रखने की कठिनाइयों के कारण प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ।

संस्कृत में समाचार

1048. **श्री शशि भूषण बाजपेयी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से संस्कृत में समाचार प्रसारित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्यक्रम किस तारीख से आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चलचित्र सेन्सर व्यवस्था सम्बन्धी समिति

1049. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्रों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये चलचित्र सेन्सर व्यवस्था सम्बन्धी समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हाँ ।

(ख) मामला अभी बिचाराधीन है ।

(ग) समिति से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव है कि वह अपना काम शुरू करने की तारीख से लगभग चार महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दे ।

नये परमाणु विद्युत केन्द्र

1050. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नये परमाणु विद्युत केन्द्र बनाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ये किन-किन स्थानों पर तथा किस किस के सहयोग से स्थापित किये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) : इस समय कुछ अध्ययन जारी हैं, जिनके पूरा होने पर नये बिजली घर स्थापित करने के प्रश्न पर गौर किया जायेगा ।

Broadcast of Foreign News

1051. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri Ramji Ram :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is fact that foreign news items occupy a very large portion in our news bulletins;

(b) whether it is also a fact that in other countries, much importance is not accorded to foreign news as is given to the inland news; and

(c) if so, whether any directions have been issued to make improvements in this regard in the news Bulletin?

The Minister of Information And Broadcasting (Shri K.K. Shah):

(a) an analysis made by the Research and Reference Division in May 1967 (**Copy placed on the table, Placed ia Library See No. LT--1629/67**) shows the relative positions foreign and home news enjoy in All India Radio and several important networks of other countries.

(b) The place that foreign news occupy in the home news net works of other countries radio almost directly reflects the measure of those countries commitments, stakes and responsibilities in the course of world events. In that way A.I.R. news bulletins reflect India's commitments, stakes and responsibilities in world events. Besides, as all important national dailies will bear out, the Indian citizen is in some ways more interested in foreign news that citizens in many other countries.

(c) The relative position and weightage that Home and Foreign news enjoy or should enjoy are under regular review in All India Radio.

राडार स्क्रीन

1052. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन के साथ लगती भारत की उत्तरी सीमा पर हवाई हमले के विरुद्ध समय रहते चेतावनी देने के लिये बारह मास काम करने वाली संचार प्रणाली सहित राडार स्क्रीन स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस सम्बन्ध में जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

सिक्किम को जाने वाली सीमावर्ती सड़क

1053. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती सड़क संगठन को जिसका कार्य सिक्किम को जाने वाली सीमावर्ती सड़क को भारी मोटर गाड़ियों के लिये खुला रखना है, मौसम तथा पूर्वी हिमालय की खतरनाक छोटी-छोटी पहाड़ियों के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) हिमालय क्षेत्र भूतत्वीय दृष्टि से मजबूत हैं अतः अस्थिर हैं । सिक्किम क्षेत्र में भारी वर्फ पड़ने पर निर्भर करता है । भूमि का ऊपरी भाग जिसमें ज्वाला मुखी-मिट्टी है और हाल ही में बनी नर्म चट्टान शमिल है, वर्षा के दौरान पानी जाने से बह जाती है । सड़कें सामान्यता जिस रास्ते से नदियाँ गुजरती हैं उसी ही का अनुसरण करती हैं और नदी पहाड़ी ढलान के निचले भाग का कटाव करती रहती है । नदी द्वारा कटाव के कारण हुई क्षति को न्युनतम करने तथा सड़क समतल बनाने के उद्देश्य के बचाव का कार्य किया जा रहा है ।

(ख) अधिक कठिन मामलों में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण की दक्ष तकनीकी सलाह ली जा रही है ।

वियतनाम के बारे में अन्तर्राष्टीय नियन्त्रण आयोग की बैठक

1054. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करने के लिये भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की एक बैठक नई दिल्ली में बुलाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अन्य सदस्य देश इस पर राजी हो गये हैं ; और

(ग) बैठक कब बुलाई जायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) दिसंबर 1966 में कनाडा और पोलैंड के प्रतिनिधियों से तीन कमीशन देशों की मीटिंग के प्रस्ताव पर अनौपचारिक रूप से सलाह ली गयी थी । चूंकि कोई सामान्य सहमति नहीं थी, इसलिए इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया गया ।

Indian Hostel In Jerusalem

1055. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question no. 885 on the 3rd July, 1967 and state:

(a) whether Government have since considered the matter relating to the destruction of an Indian hostel in Jerusalem by the Israeli forces;

(b) if so, the decision taken in this matter ;

(c) if not, when this matter would be taken up; and

(d) the amount spent on the construction of this hostel ?

The Prime Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi.)

(a) to (d) There appears to be no immediate prospect for a settlement of the West Asian crisis. Israel continues in occupation of the areas occupied by her after the out-break of hostilities in June, 1967, and has even taken steps to integrate the city of Jerusalem within her territory. The question of the rebuilding of the Indian hostal can only be considered after the situation normalises in West Asia.

Indians Under Detention in Burma and other Countries

1056. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indians under detention in Burma ;

(b) the grounds on which they have been put under detention by the Burmese Government ;

(c) the steps taken by Government to secure release of these Indians ;

(d) whether Indians have been detained in some other countries also ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) 111.

(b) 28 are detained for alleged economic offences ; 60 for immigration offences ; 17 for criminal offences ; 6 for political offences.

(c) Our Embassy is in constant touch with the Burmese authorities regarding the release or early trial of these detenus.

(d) and (e) Full information is not available at present. The facts are being collected and will be placed on the Table of the House when received.

Compaigns by Non-White Peoples' Organisations of Africa

1057. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether some representatives of the non-white peoples' organisations of South Africa; Mozambique and Rhodesia have come to India to set up their centre here for their campaign ;

(b) if so, the action taken by Government to help them in their mission ;

(c) whether Government have received any suggestion in respect of bringing popular Governments in power in those areas and getting them recognition ; and

(d) whether Government propose to take initiative to start negotiations with the friendly Nations in this behalf ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) The African National Congress, which is the liberation movement connected with the struggle against apartheid in South Africa has set up an external office in New Delhi. This is the first A. N. C. office in Asia.

(b) The Government of India have welcomed the establishment of this office and are giving technical and material assistance for its running.

(c) No, Sir.

(d) The Government of India is in constant touch with all friendly Governments in the matter of assistance to movements fighting against apartheid in Southern Africa and for the liquidation of the remaining pockets of colonialism in Africa as envisaged *in* Resolution No. 1514 (XV) of the U. V. General Assembly and numerous other U. N. Resolutions, on decolonisation.

Death of Army Officers in Motor Boat Accident Near Poona

1058. **Shri K. P. Singh Deo** : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1190 on 17th July, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the causes of a motor boat mishap near Poona whioh resulted in the death of six Army Officers has since been completed;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when it is likely to be completed ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) The proceedings of the Court of Inquiry have revealed that on the night of 29/30th June 1967, a storm boat was carrying 16 personnel, including officer trainees, who were doing a Bridging Training exercise, as part of their normal course of instructions, in the river Mula at Poona. When the storm boat was in mid-stream, another motor-driven storm boat passed by it at a high speed. Due to the turbulence created by this second motor boat, water slipped into the first boat from the bow end and it was disturbed. The disturbance created a panic among the persons on the boat. Some af the passengers started moving from one place to another, This movement of the passengers increased the disturbance of the boat, resulting in some of the passengers being washed over-board while some others left the boat on their own. As a result of this six students officers were drowned.

(c) Does not arise.

नागालैण्ड सम्बन्धी विषय गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपा जाना

1059. **श्री दामानी:** क्या प्रधान मंत्री 22 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड राज्य सम्बन्धी विषय इस बीच गृह-कार्य मन्त्रालय को सौंप दिय गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह विषय कब गृह-कार्य मन्त्रालय को सौंपा जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) जी नहीं, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

गुजरात में भारी पानी तैयार करने वाला कारखाना

1060. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में भारी पानी तैयार करने वाला एक कारखाना लगाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्तिमंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नये आयुध सामग्री बनाने वाले कारखाने

1061. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब नये आयुध सामाग्री बनाने वाले का खानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि तहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चौथी योजना के दौरान परम्परागत हथियार उत्पादन करने के सम्बन्ध में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री, (श्री ल० न० मिश्र)

(क) जी नहीं ।

(ख) ब्रिटेन और अंमरीका द्वारा सैनिक सहायता बन्द किये जाने के कारण आयातित संयंत्र और मशीनरी के प्राप्त किये जाने में देरी हुई और इसके परिमाणस्वरूप चन्दा और आम्बाझारी के कारखानों में उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ।

जबलपुर गाड़ी कारखाने को 1965 में स्वीकृत दी गई थी और इसके 1969-70 में चालू किये जाने की सम्भावना है ।

फरवरी 1965 में स्वीकृत ऐसीलियरैटिड उराइड फैक्टरी चालू वर्ष में काम करना आरम्भ कर देगी ।

(ग) हमारा उद्देश्य इन कारखानों को रूढ़ हथियार के उत्पादन में आत्मनिर्भर करना है और इसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इन हथियारों के उत्पादन में प्रगति हो रही ।

जापान और फिजी में भवन खरीदना

1062. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में हमारे दूतावास के लिए भवन खरीदने पर 34 लाख रुपये और फिजी में उच्चायुक्त के निवास स्थान पर 2.5 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह व्यय करने का क्या कारण है जबकि इन देशों में बहुत सस्ते भवन मिल सकते थे ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) टोकियों में भारतीय राजदूतावास की बिल्डिग 1953 में 3,38,760 रुपए की लागत से खरीदी गई थी। चांसरी और स्टाफ क्वार्टरों समेत पांच अन्य बिल्डिगें 1952 से 1953 के दौरान 31,39,454 रुपए की कुल लागात से खरीदी या बनवाई गई थीं।

सुवा, फिजी, में कमिश्नर की रिहायश के लिए एक बिल्डिग 1965 में 2,52,000 रुपए की लागत से खरीदी गई थी।

(ख) जैसा कि जाहिर है, यह खर्च कई वर्षों पर फैला हुआ था और सरकार को संतोष है कि इन संम्पत्तियों का खरीदना और नई इमारतों का निर्माण करना अन्ततः लाभकारी रहा है और इसलिए देश के हित में रहा है।

सयुंक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जैट विमानों का निर्माण

1063. **श्री न० कु० साल्वे** :
श्री मणिभाई जें० पटेल० :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जैट लड़ाकू विमान निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

एच० एफ०-24 विमान ढांचे के ई-300 ईंजन के सम्बन्ध में संयुक्त अरब गणराज्य में उड़ान विकास परीक्षण में प्रगति है। संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट लड़ाकू विमान के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में इन परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही विचार किया जायेगा।

पहाड़ी डिवीजन

1064. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी उत्तरी सीमाओं के लिये आवश्यक सेना के सभी पहाड़ी डिवीजनों को बनाने तथा सुसज्जित करने में कहाँ तक प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

सभी पहाड़ी डिवीजनों को बनाने और प्रशिक्षण देने का कार्य पूरा हो चुका है और उनको सुसज्जित किये जाने का कार्य संतोषजनक है ।

आयुध कारखानों में प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण

1065. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सामान दो पृथक-पृथक आयुध कारखानों में बनाया जा रहा था जबकि एक कारखाने में उत्पादन लागत दूसरे कारखाने में उत्पादन लागत से अधिक थी ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आयुद्ध कारखानों में ऐसे सामान बनाने का समन्वय करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)।

(क) यह सच है कि उत्पादन लागत को ध्यान में रखे बगैर कुछ समान दो पृथक पृथक आयुद्ध कारखानों में बनाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) माल के आर्डर उसकी उत्पादन क्षमता की उपलब्धता और उसकी शीघ्रता से आवश्यकता के अनुसार, एक से अधिक कारखानों को दिये गये हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लागत का पहले से पता नहीं लगाया जा सकता । इन परिस्थितियों में इस प्रकार के मामलों को पूरी तौर से समाप्त नहीं किया जा सकता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए युद्ध सामग्री कारखानों में बड़े मदों के भार को डायरेक्टर जनरल आर्डनेस फेक्टरी के हेडक्वार्टर से वितरित किया जाता है ।

पत्रकारों का प्रशिक्षण

1066. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सूचना और प्रसार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों के, विशेषकर प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों के लिये काम करने वाले पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिये की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सिफारिश करने हेतु नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनके बारे में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) से (ग) सरकार ने कोई समिति स्थापित नहीं की है। तथापि भारतीय प्रेस परिषद् ने पत्रकारिता के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान सुविधाओं का सर्वेक्षण करने और उनमें संभव सुधार और विस्तार के लिए उपाय सुझाने के लिए एक छोटी समिति नियुक्त की है। इस समिति का काम चालू है।

आकाशवाणी से विदेशी भाषाओं में प्रसारण

1067. **श्री चिन्तामणि पांणिग्रही :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने रूसी तथा मलायावी भाषाओं में प्रसारण आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन भाषाओं में प्रसारण कब से आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के०शाह) : (क) और (ख) आकाशवाणी से मलायावी में 30 मिनट की और रूसी भाषा में 45 मिनट की दैनिक सेवाएँ शुरू करने का निर्णय हो चुका है ; परन्तु, इन भाषाओं में कार्यक्रम संचालित करने के लिए व्यक्तियों के मिलने में कठिनाइयों के कारण इन सेवाओं को चालू करना अभी तक संभव नहीं हो सका है । ज्योंही न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी मिल जाएँगे, ये सेवाएँ चालू कर दी जाएँगी ।

उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक

1068. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में इस समय कितने भूतपूर्व सैनिक हैं ;

(ख) सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उनमें से कितने अभी तक बेरोजगार हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) सम्बद्ध स्टेट सोल्जर्स, सेलर्स एण्ड एयरमेन्स बोर्ड से जानकारी मांगी गई है और जब वह प्राप्त होगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास के लिये निम्नलिखित रियायतें तथा सुविधाएँ दी गई हैं :—

नौकरी के लिये

(1) सैनिक बल से निवृत्त होने से छः महीने पूर्व उनकी इच्छा के काम दिलाऊ दफ्तर में उन्हें रजिस्टर किये जाने की अनुमति का दिया जाना ।

(2) काम दिलाऊ दफ्तरों में असैनिक नौकरी के लिये उन्हें तीसरी प्राथमिकता का दिया जाना ।

(3) सशस्त्र सेना में दी जाने वाली आयु छूट के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, उन्हें तीन वर्ष की छूट का दिया जाना ।

(4) रक्षा संस्थापनों और सुरक्षा दलों की नौकरियों में, जिनका उन्हें अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

(5) 1 जुलाई, 1966 से सर्वप्रथम दो वर्ष के लिये श्रेणी तीन और श्रेणी चार के स्थायी पदों में, केन्द्र में उनके लिये 10 से 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया जाना ।

उड़ीसा सरकार ने भी श्रेणी तीन और श्रेणी चार की राज्य सेवाओं के पदों में से 10 से 20 प्रति पदों में आरक्षित किये जाने के आदेश दिये हैं ।

इसके परिणामस्वरूप जनवरी 1967 से जून 1967 तक उड़ीसा में 59 और उत्तर प्रदेश में 844 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ।

नौकरी की अधिक आशा के लिये प्रशिक्षण

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये भूतपूर्व सैनिक के लिये वजीफे सहित 5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण ।

2. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये प्राथमिकता दिया जाना ।

3. ट्रेक्टर और कृषि फार्म का प्रशिक्षण ।

4. 3000 सैनिकों पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष उनके निकट के रेजीमेन्ट केन्द्र के निकट स्थापित और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ चुने हुए व्यापारों का प्रशिक्षण दिया जाना ।

(ग) काम दिलाऊ दफ्तरों के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में 556 और उत्तर प्रदेश में 4994 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को 30 जून, 1967 तक कोई नौकरी नहीं दी गई ।

1950 की भारत-नपाल सन्धि

1069. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1950 की भारत-नेपाल सन्धि में यह व्यवस्था है कि भारत और नेपाल के नागरिक दोनों देशों में सम्पत्ति खरीद सकते हैं तथा रख सकते हैं ;

(ख) क्या नेपाली नागरिकों द्वारा भारत में सम्पत्ति खरीदने तथा रखने के लिये सरकार ने को संविहित उपबन्ध किया है ताकि नेपाल की सरकार भी उसी प्रकार के संविहित उपबन्ध तथा बर्ताव करे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है और यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, । 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के अन्तर्गत केवल भारत-नेपाल संधि नहीं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, दोनों सरकारें पारस्पारिकता के आधार पर एक-दूसरे के नागरिकों को एक दूसरे के देश में संपत्ति के स्वामित्व के मामले में विशेषाधिकार देने को सहमत हुई हैं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार इस मामले में कोई सांविधिक व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि विदेशियों से संबद्ध केंद्रीय अधिनियमों और नियमों में विदेशियों द्वारा भूमि/संपत्ति खरीदने और बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

परमाणु बिजली घर बनाने के लिये ब्रिटेन का प्रस्ताव

1070. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात करने वाली ब्रिटेन की एक कम्पनी ने भारत में एक परमाणु बिजली घर बनाने के लिये सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) सहयोग का कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एक फर्म ने सहयोग के लिये कुछ मोटे-मोटे सुझाव अवश्य दिए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें

1071. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री जार्ज फरनेंन्डीज :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्ट संस्था ने सरकार को एक मांग-पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो संस्था द्वारा रखी गई मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(ग) जी नहीं।

(ख) और (ग) स्टाफ आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की मुख्य मांगे हैं हर पांच साल बाद ठेके नए करने की वर्तमान पद्धति को पूरे समय चलने वाले ठेके में बदलना, अंशदायी भविष्य निधि के अतिरिक्त, ग्रेच्यूटी भी देना, स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाना तथा उन्हें स्थायी करना एवं पेंशन देना, उसके फीस के स्केलों में संशोधन करना और परिवार पेंशन योजना के लिए उनका पात्र होना।

यह निर्णय किया गया है कि पंचवर्षीय ठेके की वर्तमान पद्धति के स्थान पर स्टाफ आर्टिस्टों को नियुक्ति-पत्र दिया जाए जिसमें उन्हें 55 वर्ष की आयु तक सेवा में रहने की इजाजत होगी। अंशदायी भविष्य निधि के लाभों के अतिरिक्त, उन्हें ग्रेच्यूटी देने सम्बन्धी प्रश्न पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

फीस स्केलों में संशोधन करने और स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाने के मामले पर विभागीय समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Submarines and Modern Arms for Pakistan

1072. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Ram Kishan Gupta :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Pakistan have secured submarines and most modern arms from several sources and a number of missiles from China; and

(b) if so, the Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) The Government of Pakistan have, we belive secured weapons from various sources. This House has been informed of these supplies on a number of occasions. The Government of India have no information regarding the supply of missiles by China to Pakistan.

(b) The Government of India are concerned at these developments and are taking adequate steps to meet the situation.

विविध भारती कार्यक्रम

1073. **डा० प० मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विविध भारती कार्यक्रम में कुछ रूपक बार बार और कई बार तो एक ही सप्ताह में बार-बार प्रसारित किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं, परन्तु यदि ब्योरा दिया जाए तो पूछ-ताछ की जाएगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Military Airport Constructed by Chinese in Kashmir (P. O. K.)

1074. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has constructed a military airpot in that portion of Kashmir which has been handed over to it by Pakistan;

(b) whether wide roads have also been constructed in this area which can be used for the movement of heavy military vehicles and tanks; and

(c) if so, whether Government have sent any protest note to China in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Government have received no report about the constsuction of a military airport in that part of Kashmir handed over by Pakistan to China.

(b) Government have received reports about construction of roads in this area.

(c) Government have already protested against the illegal transaction by which the Government of Pakistan ceded to the Government of China territory over which neither Government had any legal jurisdiction.

Broadcasts in Indian Languages from U. S. S. R. and China

1075. **Shri R. S. Vidyarathi** : Will the Minister of **Information and Broadcastting** be pleased to state :

(a) the names of the Indian regional languages, besides Hindi, in which broadcasts are made from the Radio Stations of U.S.S.R. and China; and

(b) the duration of the news bulletin?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) On the basis of information available, the Soviet Union is putting out broadcasts in Bengali, Hindi, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. The People's Republic of China is putting out services in Urdu, Hindi and Tamil. Lhasa radio puts out bulletin in Tibetan also.

(b) The duration of the news bulletins in each service from each country varies from 10 to 15 minutes as a normal routine, but on occasions it is more than 15 minutes also.

भूटान को सहायता

1076. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने भूटान को सहायता देना कब आरम्भ किया था ;

(ख) भूटान को उसके विभिन्न विकास कार्यों के लिए अब तक कितनी सहायता दी गई है ;

(ग) क्या भूटान सरकार ने भारत सरकार से इस सहायता को बढ़ाने के लिये प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 1956 में।

(ख) 31-10-1967 को 15,44,59,203 रुपए ।

(ग) और (घ) भारत सरकार भूटान की दूसरी पंच वर्षीय योजना (अप्रैल 1966–मार्च 1971) को 20 करोड़ रुपए की सीमा तक इस शर्त पर निम्नांकित करने को सहमत हो गई है कि धन का वास्तविक विनिधान व्यय की सावधिक समीक्षा और योजना के अमल को वास्तविक प्रगति के आधार पर नियत किया जाएगा ।

भारतीय चलचित्र संस्था

1077. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र संस्था में शिक्षा का माध्यम क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्देशकों तथा निर्माताओं ने माँग की है कि प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) अभिनय पाठ्यक्रम को छोड़ कर सभी पाठ्यक्रमों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है । अभिनय पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी/उर्दू और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, प्राक्कलन समिति (1967-68) की प्रथम रिपोर्ट (चतुर्थ लोक सभा) के पैरा 6 में यह बताया गया है कि मद्रास और कलकत्ता के कुछ प्रोड्यूसरों और निर्देशकों ने समिति के अध्ययन दल को इस प्रकार का सुझाव दिया है ।

(ग) इन्स्टीट्यूट, जो पड़ोसी देशों के विद्यार्थिओं को भी आकर्षित करती है, के अखिल भारतीय स्वरूप के अनुरूप अभिनय पाठ्य-क्रम के लिए अंग्रेजी और हिन्दी / उर्दू का प्रयोग जारी रखने का विचार है ।

विमान तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग

1078. **श्री यशपाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान तथा इलैक्ट्रानिक उद्योग के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त एवियेशन परिषद् नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की कब घोषणा होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) और (ख) विमान और दूसरे उपक्रमणों की लम्बी के योजना और उसके रूप, विकास तथा उसके उत्पादन के सम्बन्ध में अध्ययन कर और सिफारिशें देने के लिये 10 नवम्बर, 1967 को एक उच्चस्तरीय आयोग की नियुक्ति की गई । इस समिति के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक उद्योग नहीं आता, इस सम्बन्ध में कार्य कराने के लिये पहले ही दिवंगत डा० एच० जे० भाभा की अध्यक्षता में एक दूसरी उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई थी ।

चलचित्र निर्माताओं के लिये विदेशी मुद्रा

1079. **डा० रानेन सेन :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में चलचित्र बनाने के लिए कुछ चलचित्र निर्माताओं तथा निदेशकों को विदेशी मुद्रा दी जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में कितनी राशि मंजूर की गई है तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)

(क) जी हाँ ।

(ख) 1966 और 1967 में क्रमशः 13,400/- पाउंड और 22,000/- पाउंड की विदेशी मुद्रा देने की मंजूरियां दी गई। क्योंकि कुछ निर्माताओं ने स्थानों की शूटिंग अभी तक मुकम्मल नहीं की हैं, अतः इस्तेमाल की गई वास्तविक राशि के बारे में पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है ।

M. Ps. Visit to Nathu La

1080. **Shri Yash Pal Singh :** **Shri Bedabrata Barua :**
Shri D. N. Deb : **Shri R. R. Singh Deo :**

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether some Members of Parliament had recently gone to Nathu La and Cho-La passes to see the Jawans posted there;

(b) whether any joint report or seperate reports have been submitted by them; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) No Sir, not to Government.

(c) Does not arise.

आदिवासी लोगों के लिये कार्यक्रम का प्रसारण

1081. **श्री गणेश:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने विशाल आदिवासी जनसंख्या के लिये कार्यक्रम प्रसारित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम का प्रसारण कब से होने लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) खासी आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों तथा उनके इर्द गिर्द के इलाकों में स्थित आकाशवाणी के 9 केन्द्रों से 87 आदिवासी बोलियों में कार्यक्रम पहले ही प्रसारित हो रहे हैं ।

(ख) कार्यक्रमों का ब्योरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया हुआ है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०1630/67**]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोफिया (बलगारिया) में दूतावास

1082. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलगारिया सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि भारत को सोफिया में राजदूत स्तर का दूतावास खोलना चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हाँ ।

(ख) जैसा कि हाल की बल्गारिया यात्रा के दौरान कहा था, सरकार जल्दी ही बल्गारिया में एक कार्यालय खोलने का विचार कर रही है ।

दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सैनिकों की सहायता के लिये ब्रिटिश फ़ौगमैन

1083. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के समाचार पत्रों में हाल ही में किये गये इस रहस्योद्घाटन की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन के फ़ौगमैन (नौ सैनिक) दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सेना की गुप्त रूप से सहायता कर रहे हैं;

(ख) क्या वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई जाँच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस जाँच के निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रधानमंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ख) और (ग) इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है ।

विदेशों में भारतीय दूत तथा उच्चायुक्त

1084. **श्री म० ला०सोंधी** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन देशों में हमारे राजदूत तथा उच्च आयुक्त है उनकी संख्या कितनी है तथा वहाँ कितने कर्मचारी हैं;

(ख) हमारे ऐसे राजदूत तथा उच्च आयुक्त तथा अन्य कर्मचारी कितने थे जो उन देशों की अच्छी प्रकार से भाषा बोल सकते थे जहां उन्हें तैनात किया था; और

(ग) प्रत्येक दूतावास में उन्हीं देशों के कितने व्यक्ति सेवा करते हैं तथा उनका वे किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ;

दार्जिलिंग में अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर

1085. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री दार्जिलिंग जिले में सैनिक प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि के लिये प्रतिकर दिये जाने के बारे में 24 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1326 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष राशि बांट दी गई है ;

(ख) क्या उन 313 परिवारों को, जितनी कृषि भूमि पर इसका प्रभाव पड़ा है, उसके लिये प्रतिकर मिला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिकर देने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जैसा की 24 जुलाई, 1967 के प्रश्न संख्या 1326 के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि 15,38 लाख रुपये के अतिरिक्त स्थानीय नागरिक प्राधिकार ने 15,464·00 और रुपये मुआवजे और किराये के रूप में वितरित किये हैं।

(ख) जिन परिवारों के कृषि भूमि लेकर उन्हें स्थानीय नागरिक प्राधिकार ने मुआवजा दिया है, उनकी संख्या निश्चित की जा रही है और इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) स्थानीय प्राधिकारों को यह सलाह दी जा रही है कि बचे हुए निर्धारण का कार्य वित्तीय मंजूरी और उसका विवरण यथाशीघ्र करें।

पश्चिम बंगाल के गांवों में सशस्त्र पाकिस्तानी

1086. **श्री यज्ञदत्त शर्मा**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी बस्ती दाहाग्राम और पश्चिम बंगाल पूर्व पाकिस्तान सीमा के बीच स्थित पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गांवों में सशस्त्र पाकिस्तानी अब भी उपद्रव कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सिद्ध करने के लिए, सरकार को कोई प्रमाण मिला है कि इन गाँवों पर जबरदस्ती कब्जा करने और दाहाग्राम को पूर्व पाकिस्तान के मुख्य भूमि से मिलाने के उद्देश्य से पाकिस्तानी दंगे कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) 26 जुलाई और / अगस्त 1967 की गम्भीर वारदातों के बाद डिप्टी कमिश्नर रंगपुर (पाकिस्तान) और डिप्टी कमिस्नर, कूच बिहार (भारत) के बीच 16 अगस्त 1967 को यह समझौता हुआ था कि तनाव को कम करने के लिए भू नियमों का ईमानदारी के साथ पालन किया जाए। तबसे यह क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत है।

(ख) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण सुलभ नहीं है जिस से यह पता चलता हो कि पाकिस्तान सरकार की ऐसी कोई मंशा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरों को टेलीविजन सम्बन्धी प्रशिक्षण

1087. **श्री अब्दुल गनी दार**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 से अब तक टेलीविजन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये कुल कितने इंजीनियर विदेशों में भेजे गये ;

(ख) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ; और

(ग) उन में से कितने इंजीनियरों के अगले तीन वर्षों में सेवानिवृत होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) 10 (दस) । इनमें से 5 अभी प्रशिक्षण ले रहे है ।

(ख) और (ग) शून्य ।

टेलीविजन का प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार इंजीयनियर

1088. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 4 अप्रैल 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीविजन का प्रशिक्षक्ष प्राप्त बेरोजीगार इंजीनियर की सेवाओं का उपयोग करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के०के०शाह) : अब तक 20 इंजीनियरों को टेलीविजन का प्रशिक्षण दिया गया है । इनमें से एक की मृत्यु हो गई है और 2 दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर है । शेष 17 में से 4 दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में काम कर रहे हैं और 6 टेलीविजन के योजना और विकास के काम से सम्बन्धित हैं ।

फिलहाल केवल एक टेलीविजन केन्द्र ही दिल्ली में काम कर रहा हैं, अतः सीमित संख्या में ही इंजीनियरों का उपयोग किया जा सकता है । आकाशवाणी की चौथी पंच वर्षीय योजना में दिल्ली के टलीविजन केन्द्र का विस्तार करने से अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में भी टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । उम्मीद है कि जब ये केन्द्र स्थापित हो जाएँगे, हमारे पास उपलब्ध प्रशिक्षित इंजीनियरों की सेवाओं का पूरी तरह उपयोग किया जाएगा ।

भारी टैंक

1089. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोटारी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारी टैंकों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या भारी टैंकों के निर्माण के लिए मध्यम श्रेणी के टैंक बनाने वाले वर्तमान कारखाने का विस्तार किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) इस समय देश में भारी टैंक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विदेश-स्थित भारती दूतावासों के अधिकारियों का भाषा सम्बन्धी ज्ञान

1090 **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने इस बात के लिये क्या कार्यवाही की है कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के अधिकारियों की उन देशों की भाषाओं का सामान्य ज्ञान है; और

(ख) क्या इन अधिकारियों को नियुक्त करते समय अथवा एक दूतावास से दूसरे दूतावास में स्थानान्तरित करते समय इन अधिकारियों का भाषा सम्बन्ध ज्ञान तथा योग्यता को भी ध्यान में रखा जाता है?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्यमंत्री (श्रीमती इंन्दिरागांधी): (क) भारती विदेश सेवा में भर्ती किए गए अधिकारियों को एक विदेशी भाषा अनिवार्य रूप से दी जाती है जो उन्हें सीखनी होती है। उन्हें अपनी पसंद की अन्य विदेशी भाषाएं सीखने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है। विदेश-स्थित हमारे कुछ मिशनों में हमारी इन नीति के अनुरूप अधिकारियों को स्थानीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध किया जाता है कि सभी अधिकारियों को उन देशों की भाषाएं सीख लेनी चाहिए जहां कि वे भेजे जाते हैं।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ हमारे विदेश-स्थित मिशनों से अधिकारियों का स्थानांतरण और वहां नियुक्ति करते सशय स्थानीय भाषा के ज्ञान के प्रश्न को निश्चय ही ध्यान में रखा जाता है।

चीनी दूतावास पर लगाये गये प्रतिबन्ध

1091 **श्री शारदानन्द :**
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री अटल विहारी वाजपेयी :
श्री वेणीशंकर शर्मा

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी दूतावास तथा उसके कर्मचारियों की गतिविधियो पर उसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये हैं जैसे चीन की सरकार ने पेकिंग में हमारे दूतावास पर लगाये हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चीनियों ने इन प्रतिबन्धों का कई बार उल्लंघन किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं जिससे भविष्य में इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन न हो?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सुरक्षा कारणों से और पीकिंग-स्थित हमारे राजदूतावास के व्यवहार के अनुरूप नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास से कहा गया है कि वह दिल्ली और नई दिल्ली की म्यूनिसिपिल

सोमा के बाहर जाने, भारत छोड़कर जाने और चीनी राजदूतावास तथा उसके कर्मचारियों द्वारा भारत सरकार को प्रत्यायित राजनयिकों को छोड़कर अन्य लोगों को निमंत्रण देने के बारे में वैसी ही प्रक्रिया का पालन करें।

(ख) चीनी राजदूतावास ने इन विनियमों का उल्लंघन करने की कई बार चेष्टा की है।

(ग) भारत सरसार ने चीनी राजदूतावास का ध्यान इन अनियमिताओं की ओर दिलाया है और उनसे माँग की है कि चीनी राजदूतावास उसी तरह भारत सरकार के नियमों का पालन करे जैसा कि पीकिंग-स्थित भारतीय राजदूतावास चीन सरकार के नियमों का पालन करता है।

Wrong Projection of Image of India Abroad by Foreign Photographers

1092 **Shri O. P. Tyagi** : Will the minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that foreign visitors especially T. V. photographres take photos of the poor, beggars and slums in India for exhibition in foreign countries, thereby creating a distorted picture of India abroad; and

(b) if so, the steps taken by Government to check such activities of the foreign photographers and to counter-act the wrong impression thus crated ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Yes, Sir. Some foreign TV and news photographers visiting India for general news coverage have made adverse publicity for India abroad.

(b) In such cases we have made representations to the newspaper and TV organisations concerned, and we take steps to see that there is no repetition of such activities. Further more our Embassies try to project a balanced and correct picture of India through talks, distribution of documents, screening of our films etc.

जम्मू तथा काश्मीर का दौरा करने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी

1093. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय तथा आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर जम्मू तथा काश्मीर का दौरा करते रहते हैं;

(ख) क्या 1967 में वे जम्मू तथा काश्मीर गये; और

(ग) यदि हां, तो कितनी बार तथा वहां अपने ठहरने की अवधि में वे किन राजनैतिक दल अथवा किन राजनैतिक दलों के लोगों से मिले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) किसी से नहीं।

चौथे आम चुनाव में रेडियो काश्मीर से चुनाव सम्बन्धी प्रसारण

1094. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या सूचना और प्रासारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आम चुनावों के दौरान रेडियो काश्मीर, श्रीनगर और रेडियो काश्मीर जम्मू द्वारा किये गये चुनाव सम्बन्धी पक्षपात पूर्ण प्रसारण के बारे में अनेक शिकायतें आई हैं;

(ख) क्या तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री को इन शिकायतों के बारे में लिखित रूप से बताया गया था ;

(ग) क्या इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Chinese Entering India in the Garb of Tibetans

1095. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese are entering India via Chamoli and Pithoragarh in the garb of Tibetans and forged currency notes have been recovered from them; and

(b) if so the action taken by government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise. However, all Tibetans who are entering India now are thoroughly screened to ensure that none of them is a Chinese agent.

अटोमिक मिनरल्स डिवीजन

1096. **श्री ना० स्व० शर्मा :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अटोमिक मिनरल्स डिवीजन में इस समय कितने कर्मचारी अस्थायी हैं;

(ख) श्रेणीवार उनका सेवा काल कितना-कितना हैं; और

(ग) उन्हें अब तक स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी से युक्त एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1631/67]

(ग) सन् 1966 में, तब तक प्रभाग द्वारा पूरे किये गये सर्वेक्षणों तथा भविष्य में किये जाने वाले कार्यों के आधार पर प्रभाग की दीर्घकालीन आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया था। प्रभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाने का कार्य तब से जारी है।

नवीन राडार पद्धति

1097. **श्री वेदव्रत बरुआ :** **श्री न० कु० सोंधी ।**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रा० रा०सिंह देव :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर एटलान्टिक संधि संगठन शीघ्र ही राडार की सब नवीन शृंखला स्थापित करने वाला है जिससे मित्र तथा शत्रु देशों के विमानों का पता लग सकेगा,

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उपकरणों को प्राप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) इस सम्बन्ध में हमारे पास जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कूच बिहार में अज्ञात विमान

1098. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जुलाई 1967 को कूच बिहार के मेकलीगंज थाना क्षेत्र में खरखरिया में एक अज्ञात गैर विमान उड़ता हुआ देखा गया था ;

(ख) क्या इस मामले में जाँच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है।

श्रीलंका में कार्य कर रहे भारतीय बैंक

1099. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने वहाँ कार्य कर रहे भारतीय बैंकों पर यह गम्भीर आरोप लगाया है कि वे सांस्थानिक परिवर्तनों द्वारा उस देश के आर्थिक विकास में अंशदान देने में असफल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आण्विक खनिज विभाग

1100. **श्री ना० स्व० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आण्विक खनिज विभाग को अणु शक्ति संस्थान के माध्यम से अनुदान दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि के अनुदान दिये गये ;

(ग) इस विभाग के वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि लाखों रुपये वापिस किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) परमाणु खनिज प्रभाग की बजट व्यवस्था परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसका यह प्रभाग एक संघटक यूनिट है, के बजट से की जाती है।

(ख) और (ग) अनुदानों तथा व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

	1964–65		1965–66		1966-67	
	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(लाख रुपयों में)					
वार्षिक अनुदान	1.85	82.90	0.31	95.00	2.00	102.80
वास्तविक खर्च	1.70	80.38	0.21	92.66	1.82	101.63

(घ) तथा (ङ) पिछले तीन वर्षों में वापिस की गई राशि, जिसकी वापसी का कोई विशेष उल्लेखनीय कारण नहीं था, नीचे दी गई है।

1964–65	1965–66	1966–67
(लाख रुपयों में)		
2.67	2.44	1.35

भूतत्वज्ञों के पदो पर पदोन्नति

1101. **श्री ना० स्वा० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक भूतत्वज्ञों को भूतत्वज्ञ तथा वरिष्ठ भूतत्वज्ञ के ग्रेड में पदोन्नति करने की कसौटी क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितने सहायक भूतत्वज्ञों को भूतत्वज्ञ तथा वरिष्ठ भूतत्वज्ञ के पदों पर पदोन्नत किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) विज्ञान अधिकारी ग्रेड एस बी (रु० 350–900) से विज्ञान अधिकारी (भूविज्ञान) ग्रेड एस सी 2 (रु० 400–950) या ग्रेड एस डी 2 (रु० 700–1250) में पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षण योग्यता है भूविज्ञान में एम० एस सी० की डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनन कर्म या भूविज्ञान में डिप्लोमा। ग्रेड एस सी० 2 में पदोन्नति के लिए यह आवश्यक है कि विज्ञान अधिकारी ग्रेड एस बी के पद पर प्रत्याशी ने कम से कम तीन वर्ष कार्य किया हो तथा विज्ञान अधिकारी (भूविज्ञान) ग्रेड एस डी–2 के पद में पदोन्नति के लिए आवश्यक हैं कि प्रत्याशी ने विज्ञान अधिकारी ग्रेड एस सी 2 के पद पर पांच से सात वर्ष तक कार्य किया हो।

दोनों ही पदों पर पदोन्नति तभी सम्भव है जब स्थान रिक्त हों तथा योग्य प्रत्याशी उपलब्ध हों। किसी भी प्रत्याशी की योग्यता की जांच तदर्थ नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति कमेटियों द्वारा उसकी गोपनीय रिपोर्ट तथा इंटरव्यू के समय उसके द्वारा दिये गए उत्तरों के आधार पर की जाती हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में विज्ञान अधिकारियों (भूविज्ञान) ग्रेड एस बी को विज्ञान अधिकारी (भूविज्ञान) ग्रेड एस सी 2 तथा / विज्ञान अधिकारी (भूविज्ञान) ग्रेड एस सी 2 को विज्ञान अधिकारी (भूविज्ञान) ग्रेड एस डी 2 के पद पर पदोन्नति मिली। इसके अतिरिक्त, कुछ वैज्ञानिकों की पदोन्नति इस समय विचाराधीन हैं।

परमाणु वैज्ञानिक द्वारा आत्महत्या

1102. **श्री ना० स्व० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री एक परमाणु वैज्ञानिक द्वारा आत्महत्या के बारे में 10 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5094 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता, अधिकारी ने इस बीच जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरागांधी):

(क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Demonstrations Before Indian Embassy at Peking

1103. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 12th September, 1967, the Chinese held demonstrations in front of the Indian Embassy at peking several times;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any damage was caused to the Indian Embassy ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Yes, Sir.

(b) the reasons for these officially engineered demonstrations are best known to the Chinese Government. It would appear that these were primarily motivated to serve Chinese propaganda purposes both at home and abroad.

(c) No, Sir.

परमाणु शक्ति के लिए उपकरण

1104. **श्री न० कु० सोंधी:**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव:
श्री रा० रा० सिंह देव:
श्री य० अ० प्रसाद:
श्री वेदव्रत बरुआ:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परमाणु शक्ति की बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए क्या देश में ही पर्याप्त तकनीकी जानकारी प्राप्त करने तथा आवश्यक उपकरणों का निर्माण करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) जी, हां।

(ख) तारापुर तथा राणाप्रताप सागर के परमाणु बिजलीघरों के निर्माण से प्राप्त अनुभव की सहायता से भारतीय इंजनियर अब इस योग्य हो गये हैं कि वे बिना किसी विदेशी सहायता के मद्रास परमाणु बिजलीघर का निर्माण कर सकेंगे। मद्रास परमाणु विजलीघर पर होने वाले खर्च का 20 प्रतिशत से भी कम विदेशी मुद्रा में होगा। अब तक प्राप्त की गई तकनीकी जानकारी में लगातार सुधार किया जा रहा है।

परमाणु बिजलीघरों के लिए आवश्यक अत्यन्त सूक्ष्म एवम् श्रेष्ठ किस्म के उपकरण तैयार करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक इलैक्ट्रानिक्स फैक्ट्री स्थापित की गई है। न्यूक्लीय ईंधन तथा अन्य विशिष्ट पदार्थ तैयार करने के लिए संयंत्रों का एक समूह स्थापित किया जा रहा हैं। परमाणु बिजलीघर बनाने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता इस बात पर निर्भर है कि स्टेनलैस स्टील, विशिष्ट धातुमिश्र तथा अधिक क्षमता के टर्बोजेनित्र जैसे उपकरणों तथा अन्य कच्चे पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्योग धन्धे भी विकसित हों।

सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण

1105. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अगस्त, 1967 को जब दाहाग्राम बस्ती से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भारतीय

क्षेत्र के पयास्ती गांव में घुस आये थे, तो पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा दल ने दो पाकिस्तानियों को गोली से मार दिया था और एक को गिरफ्तार कर लिया था ;

(ख) क्या सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सीमा के इस अतिक्रमण के विरुद्ध भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त को कोई विरोधपत्र दिया गया था; और

(ग) यदि पाकिस्तान से कोई उत्तर मिला है तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) और (ख) जी हां ।

(ग) पाकिस्तान हाई कमीशन ने इस आरोप से इन्कार किया है और आरोप लगाया है कि उक्त घटना पाकिस्तान के प्रदेश में हुई थी ।

पाक-चीन साजिश के बारे में राष्ट्रपति अयूब खां का वक्तव्य

1106. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति अय्यूब खाँ ने अगस्त, 1967 में अपने पहले मासिक प्रसारण में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान चीन साजिश को गलत प्रचार की संज्ञा दी है और कहा कि भारत यह प्रचार अधिक सैनिक सहायता लेने अथवा लोगों को आन्तरिक समस्याओं से ध्यान बदलने के लिए, कर रहा है तथा आरोप लगाया है कि भारत अपनी शक्ति बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार पाक-चीन की सांठगांठ के खतरे के प्रति पूरी तरह सजग है जो कि मूलतः भारत के विरुद्ध है । चीनी और पाकिस्तानी नेताओं ने एक स्वर से बार-बार अपनी दोस्ती और भारत के प्रति समान विरोध की बात कही है । पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आरोप स्पष्टतः निराधार हैं ।

इंटरनेशनल सिख ब्रदरहुड प्रतिनिधि मंडल के नेता के साथ नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के अधिकारियों का दुर्व्यवहार

1107. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी दूतावास के एक अधिकारी ने इन्टरनेशनल सिख ब्रदरहुड प्रतिनिधि मंडल के नेता जो कि दूतावास में 31, अक्तूबर, 1967 को चीन में चीन सरकार द्वारा बलपूर्वक गुरुद्वारों को अपने अधिकार में लेने के विरोध में एक विरोध-पत्र देने गये थे, के साथ दुर्व्यवहार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) इस आशय की एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है ।

(ख) चीनी कार्यनायक को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और उसे यह बताया गया था कि राजनयिक मिशनों के सदस्यों से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है । उसे यह भी बताया गया था कि चीन सरकार ने शंघाई में गुरुद्वारों पर जबर्दस्ती कब्जा करने की जो इकतरफा कार्यवाई की है उससे सभी भारतवासी क्षुब्ध हैं और उनको यह पूरा अधिकार है कि वे चीन सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष इसके खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रकट करें।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर

1108. क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड बंगलौर में जनवरी, 1967 से अब तक कितने रिक्त स्थानों को भरा गया है; और

(ख) वहां, नये व्यक्तियों को नियुक्त करते समय किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) 1 जनवरी, 1967 से 14 नवम्बर, 1967 तक भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर में कुल 556 रिक्त स्थान भरे गये थे । इस संख्या में प्रशिक्षणार्थी शामिल नहीं हैं । 556 रिक्त स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) **सीधी भर्ती**

	तकनीकी	गैर-तकनीकी	कुल
(एक) गैर-कार्यकारी	173	306	479
(दो) कार्यकारी	54	8	62
कुल	227	314	541

(2) **प्रतिनियुक्तियां**

	तकनीकी	गैर-तकनीकी	कुल
(एक) गैर-कार्यकारी	7	—	7
(दो) कार्यकारी	7	1	8
कुल	14	1	15

ऊपर (1) और (2) का जोड़ 556

(ख) रिक्त स्थानों की अभिकार्य अधिसूचना अधिनियम के अनुसार बाहरी भर्ती के लिये सभी रिक्त स्थानों की अधिसूचना उपयुक्त रोजगार दफ्तरों को दे दी जाती है । 200 रु० या इससे अधिक के वेतन वाले पदों का विज्ञापन साथ साथ दिया जाता है । रोजगार दफ्तरों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों तथा विज्ञापनों के उत्तर में प्राप्त आवेदनपत्रों की जाँच पड़ताल की जाती है और उचित रूप से गठित समितियों द्वारा पात्र आवेदकों का इन्टरव्यू लिया जाता है । नियुक्तियां, इस प्रकार चुने गये उम्मीदवारों की तालिकाओं में से की जाती हैं ।

श्रमिकों से सम्बन्धित पत्रिकाएँ

1109. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रकाशित होने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित समाचार पत्रों, दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक पत्रिकाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उनकी कितनी-कितनी प्रतियां बिकती हैं तथा उनका वित्तीय दायित्व क्या है; और

(ग) वे किसी न किसी रूप में कितने मजदूर संघों से सम्बद्ध हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें श्रमिकों से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाओं की राज्य-वार और प्रकाशन-अवधि-वार संख्या तथा उसमें जिन पत्र-पत्रिकाओं की खपत संख्या उपलब्ध है वह दी हुई है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1632/67**] उनकी वित्तीय परिसम्पत्ति या मजदूर संघों से उनके सम्बद्ध होने के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

मिट्टी के कबूतर (क्ले पीजन) पर चांदमारी करने के लिये शॉटगन (छर्रे वाली बन्दूक) के कारतूस

1110. **डा० कर्णी सिंह** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिट्टी के कबूतर (क्ले पिजन) पर चान्दमारी करने के लिये भारतीय आयुध कारखाने में निर्मित शॉटगन (छर्रे वाली बन्दूक) के कारतूस का विस्तृत परीक्षण किया है और क्या इन परीक्षणों में नमूना बनाने का (पैटर्निंग) परीक्षण भी शामिल है ; और

(ख) यदि हां, तो 40 गज की दूरी से पूरी चोक बैरलों वाली बन्दूक से, 30 गज की दूरी से परिवर्धित चोक बैरलों वाली बन्दूक से और 20 गज की दूरी से सिलिन्डर बैरलो वाली बन्दूक से इन नमूनों के साथ निशाना बांधने में कितने प्रतिशत सफलता मिली है और क्या उक्त प्रत्येक नमूने के साथ निशाना बांधने में 70 प्रतिशत सफलता मिली है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) :

(क) और (ख) इस समय आयुद्ध कारखानों द्वारा बिक्री के लिये भेजे जाने वाले 12 बोर के $2\frac{1}{2}''$ के कारतूस उचित स्तर के हैं और कबूतर (क्ले पीजन) पर चान्दमारी करने के लिये नहीं हैं इससे 30 गज की दूरी से 60 प्रतिशत और 40 गज की दूरी से 40 प्रतिशत निशाने में सफलता मिली है ।

नैशनल राइफल एसोसिऐशन द्वारा कुछ जाँच किये जाने के पश्चात् कबूतर पर (क्ले पीजन) पर चांदमारी करने के लिये 300 कारतूस विशेष तौर पर बनाये गये हैं जो नैशनल राइफल एसोसिऐशन को परीक्षण और उसकी रिपोर्ट के लिये भेज दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में विकास/सुधार उसकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर किये जाँयेंगे । पूरी चोक बैरल पर किये गये परीक्षण 90 प्रतिशत सफल रहे ।

हज की तीर्थयात्रा

1112. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में कुल कितने मुसलमान 'हज' की यात्रा करने गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि जितने मुसलमान प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा करने के लिये आवेदन करते हैं; वे सब सरकारी प्रतिबन्धों की वजह से तीर्थयात्रा नहीं कर पाते हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में मुसलमानों के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार को मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं अथवा किसी मुसलमान व्यक्ति विशेष से इस विषय पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो उन अभ्यावेदनों का सार क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान जो तीर्थयात्री हज यात्रा पर गए, उनकी संख्या इस प्रकार है; इनमें बच्चे भी शामिल हैं :

1963	15102
1964	16537
1965	18267
1966	15533
1967	15544

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण सरकार किसी भी वर्ष हज जाने वाले तीर्थ-यात्रियों की संख्या की सीमा निर्धारित कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हज यात्रा के लिए अर्जियां देने वाले सभी मुस्लिम हज करने में असमर्थ रहते हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा की स्थिति संतोषजनक होने पर यह कठिनाई दूर हो जाने की संभावना है।

(घ) विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन, व्यक्ति और केन्द्रीय हज समिति भी यह सुझाव देते रहे हैं कि हज जाने वाले तीर्थयात्रियों की सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार करे।

वायु सीमा

1113. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन समाचारपत्रों को ध्यान मे रखते हुए कि चीन परमाणु हथियारों वाले मध्यम दूरी तक वार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों को भारतीय राज्यक्षेत्र के पार हिन्द महासागर में फेंकने की योजना बना रहा है, क्या उनके मंत्रालय के विधि तथा सन्धि प्रभाग ने विशेषज्ञों द्वारा ठीक पता लगाने के लिए उच्चस्तर पर कोई जाँच करवाई है कि भारतीय वायु सीमा कहां समाप्त होती है और कहाँ से दूसरे देश की वायु सीमा आरम्भ होती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या निर्णय किये गये हैं;

(ग) क्या किसी अन्य देश ने अपनी वायु सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) भारत की वायु सीमा और उसके भी परे बाह्य सीमा अंकित करने का सवाल विदेश मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) अन्य देशों द्वारा अपनी वायु सीमाओं से संबद्ध किसी घोषणा के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत में अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी०आर० ए०) की गतिविधियों के बारे में रहस्योद्घाटन

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : श्रीमान, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"भारत में सेंट्रल इन्टैलिजेन्स एजेंसी की गतिविधियों के बारे में अत्यन्त चिन्ताजनक रहस्योद्घाटनों की ओर, जोकि समाचारपत्रों के अनुसार सेंट्रल इन्टैलिजैन्स एजेंसी के एक भूतपूर्व कर्मचारी जौह्न स्मिथ ने मास्को में किये हैं।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): सरकार का ध्यान भारत में अमरीकी दूतावास के एक भूतपूर्व कर्मचारी के वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है। हमें सम्बंधित लेखों की पहली किस्त मिल गई है। दूसरी किस्त के सारांश भी समाचार पत्रों में छपे हैं। हम उसका पूर पाठ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इन लेखों से राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण समस्या पर जनता का ध्यान गया है। सरकार ऐसी गतिविधियों के बारे में पूर्णतया सतर्क है और उन्हें रोकने के लिये समय-समय पर उचित कार्यवाहियां की गई हैं।

श्री जौह्न स्मिथ की अन्य देशों से सम्बन्धित गतिविधियों के बारे में सरकार कोई वक्तव्य नहीं देना चाहती। उसने अपने लेख में जो बातें लिखी हैं, उनमें से कुछ ठीक दिखाई नहीं देती। सी० आई० ए० के एजेंटों तथा नागा नेताओं की 1956 में इम्फाल में भेंट के बारे में उसका वक्तव्य

ठीक नहीं है । उन दो सेना के अफसरों के बारे में जो इस बीच सेवा निवृत हो चुके हैं आरोपों की पुष्टि के सम्बन्ध मे रिकार्ड में कोई बात नहीं है । (**अन्तर्बाधायें**) ।

श्री हेम बरुआ : श्री जोह्न स्मिथ द्वारा किये गये रहस्योदघाटन से देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है । जब ऐसे मामले से कोई विदेशी राजनयिक सम्बंधित हो तो उसे तुरंत अवांछनीय व्यक्ति घोषित करके देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिये । दुर्भाग्य के इस देश में ऐसे भी भारतीय हैं जो विदेशों से धन लेकर देश को बेचने के लिये तैयार हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जासूसों की गतिविधियों के सम्बन्ध में हमने कई बार कार्यवाही की है । सरकार निश्चित रूप से स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगरानी रख रही है और अपराधी पाये गये व्यक्तियों को दंड दे रही है ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : माननीय मंत्री को ऐसी बातों का स्वागत करना चाहिये क्योंकि इससे इन्हें इस विषय पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने यह जानने के लिये क्या कार्यवाही की है कि भारत सरकार द्वारा दूतावासों को भेजे गये पत्रों के बारे में जानकारी यहीं से ही तो किसी को नहीं मिल जाती और क्या अमरीकी दूतावास अथवा अन्य किसी दूतावास में राजनैतिक अधिकारी अथवा आर्थिक अधिकारी के नाम पर जासूसों की कार्यवाहियां तो नहीं चल रही और क्या कुछ ऐसे लोग जो अपने को सी० आइ० ए० के विरोधी बताते हैं, क्या वे स्वयं सी० आई० ए० के एजेंट तो नहीं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य द्वारा कही गई यह बात बिलकुल सही है कि इन बातों में हमें इन मामलों पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है । इस बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि हम जासूसी के विरुद्ध क्या कार्यवाहियाँ कर रहे हैं क्योंकि जासूस यही जानकारी चाहते हैं ।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Foreign missionaries and particularly American Missionaries are political agents and their activities are political. In view of that do Government propose to turn them out of India and impose certain restrictions on the aid being given to them out of P. L. 480 funds.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब भी इस बात के लिये कोई साक्ष्य मिलता है कि विदेशी पादरी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा हो, तो हम कड़ी कार्यवाही करते हैं ।

Shri Kanawar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Chief Minister of Assam has written to you about it.

श्री यशवन्तराव चौव्हाण : मेरी आसाम के मुख्य मंत्री से बातचीत हुई है । हम उनके विचारों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): Mr. John Smith has named two army officers for their connections with C.I.A. May I know whether the Government have tried to ascertain the veracity of this fact.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : रिकार्ड में इस आरोप को सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है । जब भी मुझे इस सम्बन्ध में और साक्ष्य मिलेगा मैं अवश्य उसकी जाँच करूँगा ।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (विवरण) विधेयक

UNLAWFULL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं व्यक्तियों तथा संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ ।

साक्ष्य

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं व्यक्तियों तथा संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिए तत्संसक्त विषयों के लिए उपलब्ध करने वाले विधयकों सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ ।

पाउन्ड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DEVALUATION OF THE POUND STERLING

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : ब्रिटेन की सरकार द्वारा पौण्ड का अवमूल्यन करने का फैसला किये जाने के सम्बन्ध में, मैं इस अवसर पर एक छोटा-सा वक्तव्य देना चाहूँगा । अवमूल्यन 14.3 प्रतिशत किया गया है और इस प्रकार, नई विनिमय दर के अनुसार, एक पोण्ड अब 2·40 अमरीकी डालरों के बराबर है, जबकि पुरानी दर के अनुसार वह 2·80 डालरों के बराबर था । अब एक पौण्ड 18 रुपयों के बराबर होगा जब कि पहले वह 21 रुपयों के बराबर था ।

सोने या संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर के रूप में रुपये की विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात् वह वही रहेगी जो 6 जून 1966 को निर्धारित की गयी थी ।

माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि ब्रिटेन की इस कार्यवाई का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा । पौण्ड के विनिमय-मूल्य में यह जो परिवर्तन हुआ है वह मामूली

है । सामान्य रूप से इसका परिणाम यह होगा कि भारत और दूसरे देशों में बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में बनी वस्तुओं की प्रतियोगिता-शक्ति बढ़ जायेगी ।

हाल के वर्षों में ब्रिटेन से होनेवाला हमारा आयात हमारे कुल आयात का लगभग 10 प्रतिशत रहा है । इस आयात में मुख्यतः पूंजीगत सामान धातु और रासायनिक पदार्थ शामिल हैं । पौण्ड के अवमूल्यन का परिणाम यह होगा कि रुपये के रूप में और अन्य देशों से किये जाने वाले आयात की तुलना में ये चीजें हमारे लिए सस्ती हो जायेंगी ।

हमने 1966-67 में ब्रिटेन को जो निर्यात किया उसका मूल्य 2700 लाख अमरीकी डालर के बराबर या उस वर्ष के हमारे कुल निर्यात के मूल्य का लगभग 17 प्रतिशत था । ब्रिटेन की विनिमय दर में परिवर्तन किये जाने से हमारे कुछ निर्यात में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं; पर हमारे द्वारा निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं की माँग पर सम्भवतः इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । कुल मिलाकर, ऐसी आशंका नहीं है कि हमारे निर्यात पर इसका कोई बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

ब्रिटेन, विदेशी ऋणों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और पौण्ड के रूप में हमारा विदेशी ऋण लगभग 2450 लाख पौण्ड है । यह रकम विदेशी मुद्रा में चुकाये जानेवाले भारत के कुल विदेशी ऋण के दस प्रतिशत से अधिक है । पौण्डों के रूप में हमारी देनदारियों पर इस अवमूल्यन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । लेकिन ब्रिटेन को ब्याज सहित ऋण चुकाने का बजट-सम्बन्धी भार रुपयों के रूप में 14·3 प्रतिशत कम हो जायगा ।

जैसा कि सदन को मालूम है, ब्रिटेन से जो सहायता हमें मिलती है उसका सम्बन्ध ब्रिटेन से मिलने वाले सामान और सेवाओं से है । ब्रिटेन की विनिमय दर में परिवर्तन हो जाने से विदेशी सहायता की किसी राशि का रुपया मूल्य स्वभावतः घट जायगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटेन के सामान और सेवाओं के रूप में उस सहायता की क्रयशक्ति पर इसका प्रभाव पड़े । इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश सरकार की नयी नीतियों के कारण ब्रिटेन से सम्बन्धित शोधन-सन्तुलन में जितना सुधार होगा विकास के लिए वित्त-व्यवस्था करने की क्षमता में भी उतना ही सुधार होगा ।

जहाँ तक प्रारक्षित निधियों पर इसके प्रभाव का सम्बन्ध है, ब्रिटेन की विनिमय दर की कमी से सभी विदेशी के पास जितना पौण्ड है उसका मूल्य सोने या डालर के रूप में 14·3 प्रतिशत घट गया है । हमारे पास पौण्डों के रूप में जो रकम जमा है अर्थात् रिजर्व बैंक और सरकार के पास जमा है वह पुरानी दर के अनुसार लगभग 340 लाख पौण्ड या लगभग 71 करोड़ रुपया है । सोने या विदेशी मुद्रा के रूप में हमारी जो कुल प्रारक्षित निधि है यह रकम उसका लगभग $\frac{1}{6}$ भाग है । यद्यपि हमारी प्रारक्षित निधि के इस भाग का मूल्य सोने के रूप में कम हो गया है, पर ब्रिटेन के प्रति हमारी देनदारियों की अदायगी के लिये इसके मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है ।

अभी तक मैंने पौण्ड के सम मूल्य में किये गये परिवर्तन के प्रभावों की चर्चा की है । हमें समाचार मिला है कि आयरलैण्ड, और कुछ अन्य देशों ने भी अपनी विनिमय दर घटा दी है

अन्य देश भी अपनी विनिमय दर को इसी के अनुकूल बनायेंगे या नहीं और यदि वे ऐसा करेंगे तो किसी हद तक, यह अभी देखना है, स्वभावतः हम घटनाचक्र पर दृष्टि रखेंगे और अपने हितों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए जो भी उपाय आवश्यक हों उन पर विचार करेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय रुपये के सममूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

श्री दी० चं० शर्मा (**गुरदास पुर**): मैंने इस सम्बन्ध में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी परन्तु मालूम होता है उसकी अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का वक्तव्य ध्यान दिलाने वाली सूचना से पहले प्राप्त हुआ था। इसलिये ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार नहीं की जा सकती थी।

सूती कपड़ा कम्पनियाँ (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) विधेयक

COTTON TEXTILE COMPANIES (MANAGEMENT OF UNDERTAKINGS AND LIQUIDATION OR RECONSTRUCTION) BILL

The Minister of Commerce (**Shri Dinesh Singh**) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide in the public interest for the liquidation of cotton textile companies while keeping the undertakings thereof as running concerns, or for the reconstruction of cotton textile companies in certain cases and for matters connected therewith.

अध्यक्षक्ष महोदय : प्रश्न वह है "कि जनहित में कतिपय मामलों में सूती कपड़ा कम्पनियों परिसमापन के लिए, उनके उपक्रमों को चालू रखते हुए, अथवा सूती कपड़ा कम्पनियों के पुनः-स्थापन के तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:

The motion was adopted

Shri Dinesh Singh : I introduce the Bill.

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : REPORT OF EDUCATION COMMISSION AND REPORT OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON EDUCATION—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा होगी। श्री अमृत नाहता अपना भाषण जारी करें।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Mr. Deputy Speaker' we have not been able to frame a concrete policy in regard to education. Now the Education Commission has presented a comprehensive report. I may congratulate the Government of India and the Education Minister for this.

There is much controversy these days about the medium of education. I personally feel that language is a poor medium of education. Rousseau and Wordsworth have stated that all education can be imparted through the medium of nature's beauty. Tagore did the same through Sangeet and art. Education can be imparted through games too. Education can be considered complete if it enables one to develop fully.

Regarding language as a medium of education I can say that only mother tongue can be the best medium of education, It takes little effort and lesser time in imparting education. Those who advocate English to be the medium of education are doing so with a view to secure more jobs through that. We should make our national language or the mother tongue as the medium of education.

I feel that it is easier to impart Science education through the medium of mother tongue than to teach humanities through it. I feel that only very brilliant students should be permitted to take to the study of humanities whereas Science should be tought to the majority of students although it may result in lowering of educational standard for some time.

I am in favour of the system of neighourhood School. If you cannot do so you should make those institutions available for all children and the school fees in them should be reduced. The students produced by these institutions considered themselves to be a class part.

We should make our education Science—oriented.

The most notable recommendation of Education Commission pertains to gaining experience of labour. I feel that in the villages an adept Kisan should be entrusted with this job who may take for students to fields and teach them the art of cultivation. Similarly in the towns some technician or craftman must be asked to give education to children in his art. These kisans and craftman must be paid some remuneration by the Government.

There should be reduction in the number of vacations given to students and the school hours should be increased.

The teachers should not be transferred at all. If you do so they would devote all their lives for the betterment of the schools.

The films are creating a very bad effect on our youngmen. The Educaeion Minister should do something about it.

I want that Nehru Chairs should be created in the Universities so that young people may take inspiration from the life and works of the Jawahar Lal Nehru.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Mr. Deputy Speaker, I want to congratulate Shri Trigun Sen for constitutiion of Education Commission the report of which are discussing today. His predecessors were more of politicians than educationists. Many revolutionary suggestions have been given in the report.

While discussing this report we should know for whom is this education. It

should be for the people. If it is for the people then we should give it in the language of the people. The Britishers had introduced English for their own selfish ends. All over the world the principle of mother tongue being the medium of education has been recognised. We can learn science and efficiency through the mother tongue. Those who advocate English medium have no love for the culture of this country. They are not patriots. My Anglo-Indian friends who advocate English are half Indians and half Englishmen. We want them to be full Indians.

श्री जेवियर (तिरुनलवैल्लि) : महोदय, उन्हें आधा भारतीय कहना उस समाज का अपमान करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शिक्षा तथा भाषा के प्रश्नों पर यह कहना उचित नहीं कि वे पूरे नागरिक नहीं हैं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, I am saying what is written in the Constitution

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

Many people advance strange arguments in favour of retention of English as medium of education. But the people who support English are only handfull in the population of India. They never mix with the masses. They consider themselves superior to the general mass of population in this country. Some say that the unity of the country will be in jeopardy if you abondon English. To me these appear to be hollow arguments. Another argument advanced in favour of English is that it is our window on the world. But we accept that argument then we should read Russian and Japanese languages also so that our window in that direction may also remain open.

There should be two qualities in the educational system. One that it should be available to all and secondly it should have utility. We still have two types of schools-one where the cost on education per child is only Re. 1/- and then there are schools where cost on education per child is Rs. 500/-. Those who advocate public schools want to perpetuate their hold on services. We should put an end to the public school system.

The report has only shown lip service to the study of Sanskrit. We should do more for it. We should encourage the Gurukul system of education as that was truly socialistic system where children of poor and rich studied together.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the education commission has a historical importance about education. I can say that we should look to the integrity of the nation first and to anything else later on. Education is the base in every sphere of our life. There should not be any hurry in matter of education. We should implement the assurance of late Shri Jawahar Lal Nehru. We cannot force language on anybody.

The students who come out of Schools are disturbed in their mind. When they came out of schools and Colleges they hanker after Jobs which are not available. The present educational system has created a tendency in us that those persons who have passed B. A. and M. A. want to get only white-collared jobs. They have no love for labour.

The people who obtain third division in the degree become teachers and lecturers when they do not find any other job. What result can we expect from such people ? I, therefore, ant you to increase the pay scales of teachers so that the quality of students may be good.

Secondly I want to reveal that the plight of the teachers in private schools is very bad. I request you to take over these institutions and give them the Pay Scales which you give to teachers in Delhi.

The sons and daughters of Harijans and poor people are not sent to school because if they send their children to school, they will not be in a position to make their both ends meet. We have free and compulsory education in out Directive Principles and hence it should be implemented.

The practical training should be included in the curricula of schools and colleges. They should be utilised for community development work. They should not be given their Certificate unless and until they complete the practical training.

It is because of education that you will find people in Kerala so clean in their clothes.

We should start a powerful compaign in favour of female education.

I would again repeat that the Pay Scales and service condition of teachers in Haryana should be improved.

श्री समर गुह (कटाई) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली में बैठे सरकारी कर्मचारी अपने आपको बुद्धि में देश में सब से श्रेष्ठ मानते हैं।

शिक्षा आयोग के 15 सदस्यों में से 5 तो विदेशी थे 6 दिल्ली के थे और बाकी 4 सारे देश में से लिये गये थे। ऐसी ही स्थिति उस आयोग की समितियों की थी। वहां भी अधिक सदस्य दिल्ली से लिये गये थे। इस लिये शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें सारे देश के विचारों की छाप नहीं है।

शिक्षा आयोग ने क्षेत्रीय भाषा के बारे में कहा है। मेरा कहना तो यह है कि मातृ भाषा होनी चाहिये थी जैसा कि गाँधी जी ने भी कहा था।

बड़े दुःख की बात है कि "अंग्रेजी हटाओ" का प्रचार हो रहा है। यह बात कोई भ्रमित देशभक्ति का व्यक्ति अथवा कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति कहेगा जो हमें बैलगाड़ी के काल में ले जाना चाहता है। अंग्रेजी को दासता की भाषा कहना धोखा देने के बराबर है। संस्कृत भाषा पर भी विदेशों का प्रभाव पड़ा था। 200 वर्ष के अपने कार्य से अंग्रेजी ने भी इस देश की भाषा बनने का अधिकार ले लिया है। मुझे श्री मोरार जी देसाई से यह आशा नहीं थी कि वह

इस प्रकार की बात कह देंगे जैसी कि उन्होने लंदन में कही कि अंग्रेजी भारत में केवल 2% लोगों की भाषा है। उनकी बात का समर्थन शिक्षा मंत्री ने भी किया है। मैं चाहूँगा कि वे जन गणना प्रतिवेदन को भी पढ़ें जहाँ लिखा है कि हिन्दी के समाचारपत्र पढ़ने वालों की संख्या 70 लाख है और अंग्रेजी के समाचारपत्र पढ़ने वालों की संख्या 1 करोड़ है।

इसका अर्थ यह नहीं कि मैं हिन्दी के विरुद्ध हूँ । परन्तु इसे राष्ट्रीय वातावरण में सुधार होना चाहिये । साथ ही हिन्दी को बलात नहीं लादना चाहिये। यदि ऐसा किया तो आप हिन्दुस्तान को एक बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। इससे आप वर्तमान शिक्षा तथा प्रशासन पद्धति को क्षेत्रीय बना देंगे तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना कठिन हो जायेगा। साथ ही परीक्षा का स्तर गिर जायेगा और न्यायालयो का ऊँचा नैतिक स्तर भी नहीं टिक सकेगा । इससे देश की प्रगति तथा एकता को ठेस लगेगी।

मैं चाहता हूँ कि हिन्दी की पुस्तकों में विज्ञान तथा चिकित्सा सम्बन्धी शब्दों को हिन्दी में सम्मिलित कर लेना चाहिये ।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि शिक्षा आयोग ने रूसी भाषा को क्यों विशेष महत्व दिया है । विज्ञान तथा तकनीकी मामलों में जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी तथा चीन भाषाओं को महत्व देना चाहिये और इन सब की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

अन्त में, मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे किसी के हाथ में खेलें नहीं अन्यथा उन्हें यह पद छोड़कर कहीं राज्यपाल अथवा राजदूत बनना होगा ।

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Deputy-speaker, I am sorry to say that although the English people have gone from this country but the English languege is still with us.

I am very proud to say that we in Eastern U. P. fought the British in our fight for independence. I am proud of Nalanda University which produced great people. I want to corgratulate the Education Minister for the brave step he has taken in introducing revolutionary changes in the education field.

Although I was born in a foreign land in Jamaica but I want an Indian language to be our link language. We have Sanskrit language which is the mother of other language. We should encourage the study of Sanskrit language.

The three-language formula introduced by the Hon. Ministar is praise worthy. The children should be given education in any one of the 14 regional languages. Through the medium of these languages they will study their subjects in a better manner. Through the medium of English language the study of Mathematics, Science etc. was very furdon songe.

I want to draw the attention of the Education Minister of the bad condition prevalent in the primary schools. You do not have ever mats for the students nor are there

proper chairs for the teachers. These things should be provided to them. The respect for teachers is not there in the schools.

There is great unemployment of educated people in our country. There are 60,000 engineers in the country who are not employed anywhere. The cost on the education of one engineer comes to Rs. 30,000. In this way we can imagine the cost involved in the education of those engineers. This is all due to English language. The dams built by such Engineers collapse soon.

The I.C.S. officers are in charge of education which is undesirable. Those departments should be in the hands of educationists.

We do not have properly trained teachers who can give good education to the children.

I must pay tribute to Dr. Ram Manohar Lohia who did so much for the propagation of Hindi language.

We should send best brains to the universities. We do not want to learn alien culture. Our own culture should be taught to us. We should develop our educational system on our ancient values. We should give pride of place to our national language. I must congratulate the Education Minister.

श्री मी० ख० मसानी (राजकोट) : भाषा के मामले पर बेकार चर्चा बहुत हो रही है। वास्तव में सभा को इस विषय में विचार करना चाहिये कि केन्द्र सरकार और संसद शिक्षा के सम्बन्ध में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में श्री लोबो प्रभु ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं उनका समर्थन करता हूँ।

हम सब इस बात को स्वीकार करते है कि सामाजिक मेलजोल बड़ी अच्छी बात है। जातिभेद या वर्ग भेद बुरी चीज है और यथा सम्भव इस भेद भाव को दूर करने में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हम यह बात भी स्वीकार करते है कि समान अवसर दिया जाना अच्छी बात है, सभी लड़कों और लड़कियों को उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिये। परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये हमें उन्ही तरीकों को अपनाना चाहिये जो प्रगतिशील देशों में अपनाये गये हैं और उन्हें इन तरीकों से सफलता मिलती है। वे तरीके ये हैं कि जिन बच्चों के माता-पिता गरीब हैं और वे बच्चों को विश्वविद्यालयों या ऊँचे स्तर वाले स्कूलों में नहीं भेज सकते उन्हें छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये और उनके लिये शिक्षा का मुफ्त प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इस प्रकार सब को समान अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

आयोग के प्रतिवेदन में जो पड़ोस में स्कूल का विचार व्यक्ति किया गया हैं, वह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं है। इस से उन लोगों को पास के स्कूलों में भेजने के लिये विवश किया जायेगा जब उन लोगों के विचारों मे बिल्कुल मेल नहीं खाते। यह दृष्टिकोण उचित नहीं

है। इससे निचले स्तर के लोगों में समानता होगी परन्तु हम चाहते हैं कि ऊपरी स्तर पर भी समानता होनी चाहिये। इस लिये हम पड़ोस में स्कूल के विचार के विरुद्ध हैं। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में यह स्पष्ट है कि अल्प संख्यक समुदाय के किसी सदस्यों को पड़ोस के स्कूल में भेजने के लिये विवश नहीं लिया जा सकता। उसे संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेजना चाहे, भेज सकता है जिसमें उनके धर्म या भाषा का प्रचार होता हो इसलिये सभी गैर-हिन्दू समुदायों पर यह कानन नहीं लागू हो सकेगा। क्या यह कहा जा सकता है कि केवल बहुसंख्यक समुदाय को विवश किया जाये? इस का उत्तर स्पष्ट है और वह यह है कि यह कार्यवाही अनुचित होगी। उच्चतम न्यायालय भी इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा।

स्वतंत्र पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि भाषा का मामला एक व्यक्तिगत मामला है। भाषा, व्यक्ति की अपनी आत्मा और उसके अपने विचारों के साथ बंधी हुई है। इस सम्बन्ध में किसी पार्टी द्वारा किसी व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नही होगा। असल बात यह है कि क्या सरकार और संसद को विश्वविद्यालयों या अन्य शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम निर्धारित करने के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने या कानून बनाने का कोई अधिकार है। हमारा उत्तर स्पष्ट 'नहीं' में है। हम इस बात में विश्वास करते है कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाए स्वतंत्र होनी चाहिये। भाषा का मामला शिक्षा संस्थाओं को विद्यार्थियों तथा उनके माता पिता से की सलाह से तय करना चाहिये।

दिसम्बर, 1966 में इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि इण्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड आफ इण्डिया के अध्यक्ष राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष के साथ बातचीत करे कि वे ऐसे मामलों के सम्ब ध में एक संसदीय परम्परा बनाएँ जिनसे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का अतिक्रमण होता है जैसे शिक्षा का माध्यम, अनुसन्धान की किस्म और क्षेत्र और अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में न तो किसी विषय को संसद में स्वीकार किया जाये और न ही कोई चर्चा की जाये। यही होना चाहिये। मुझे पता नहीं कि इस सम्बन्ध में कोई वार्ता हुई है या नहीं। मैं यह फिर कहता हूँ कि संसद को विश्वविद्यालय के माललों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। संसद द्वारा बनाये गये अधिनियमो के अनुसर ही विश्वविद्यालयों का कार्य-संचालन हो रहा है। इस प्रकार राजनैतिक ढंग से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में यदि किसी ऐसे कानून का उल्लेख है कि वहां पर अमुक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिये तो मुझे उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

श्री चपलकांत भट्टाचार्या पीठासीन हुए

Shri C. K. Bhattacharya in the Chair

मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप एकदम अवांछनीय है। बुक डिवैलपमेंट कौंसल और बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्तियों को बना दिया गया है यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। इस प्रकार की बातें हमारे जैसा संविधान के होते हुए भी नहीं होनी चाहिये।

सरकार का कार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है । सरकार इस कार्य के प्रति तो उदासीन रही है परन्तु उसके बजाय वह विश्वविद्यालय की शिक्षा में हस्तक्षेप करने लगी है जिसका कार्यक्रीक ढंग से चल रहा है । राजनीतिक लोगों को राजनीति तक ही रहना चाहिये ।

हमने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार कर किया जाना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : I agree which Shri M.R. Masani that there should be free education just as free trade and free enterprise as provided in our democratic Constitution. But democracy does not mean right and privileges for selected number of people. In fact in democracy everyone should have equal oppertunity. only two percent of our population know English very well. Only 20 or 22 percent of the total population is literate and 78 percent are illiterate. Therefor unless we provide equal opportunities in regard of education, these connot be democracy in real sense. It is wrong to say that Parliament has no right to discuss the issue of education. If it is not proper to discuss this matter in the Parliament then I want to ask that who is the appropriate autharity for considering this matter? When we go to the electorate and ask for their votes, we do not converse with them in our mother tongue. In democracy it is necessary that children of the rich and poor should get uniform education. Before we discuss the Report of Education Comnmission , we should be clear in our minds whether we have to provide education for a particular class or we have to provide education to all. In case we want to follow democratic system of education, it is necessary that we should impart education through the medium of mother tongue.

The Report of the Education Commission is comprehensive but the question of medium of instruction has been left undecided. In fact we ought to develop uniform system of education failing which there can not be national integration. If we want to eradicate illiteracy then our medium of instuction has to be regional languages. But that does not mean that no one can study any other language. Anybody can study English, French or any other language.

Before I conclude, I may say that there is a problem of discipline in our country. I feel that we do not give proper respect to our teachers. Teachers should be given due status and proper scales of pay. Disparity in various grades of pay of the teachers should be removed. Without that we cannot expect good teaching staff to join this noble profession.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित. आंग्ल भारतीय) : शिक्षा आयोग पर लाखों रुपये खर्च किये गये और 21 महीनों के बाद काफी बड़ा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । इस आयोग ने प्रादेशिक भाषाओं के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है । उन्होंने कहा है कि प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिये परन्तु इसके साथ ही उन्होंने सतर्क रहने के लिये भी कहा है । उन्होंने कहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिये अंग्रेजी का अध्ययन किया जाना चाहिये । इससे पहले सम्पूर्णानन्द भावात्मक एकता समिति ने भी विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम एक करने पर बल दिया था कि अंग्रेजी को ही सम्पर्क भाषा बनाये रखना चाहिये । यह कहा जाता है कि विज्ञान और टैक्नोलौजी के क्षेत्र में अंग्रेजी आवश्यक है, परन्तु मानव विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों के लिये अंग्रेजी आवश्यक नहीं है । उन्होंने कहा था कि

मानव और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अंग्रेजी और भी आवश्यक है। उस समिति ने कहा था कि यदि केवल प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ हो जायेगी। उन्होंने आगे कहा था कि ऐसा करने से भावनात्मक एकता नहीं हो सकेगी। परन्तु यह खेद की बात है कि उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया।

यह कहना मूर्खता होगी कि पाँच वर्ष के भीतर सभी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग सभी स्तरों पर किया जा सकेगा। उप कुलपतियों ने ठीक कहा था कि इस सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित नहीं करनी चाहिये, क्या हिन्दी के सम्बन्ध में यह स्थिति नहीं है कि पूर्व उत्तर प्रदेश की हिन्दी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं समझ सकते। भाषा आयोग के समक्ष यह बात कही गई थी। हिन्दी के समर्थक कहते हैं कि वर्ष 1961 की जन गणना में 77 बोलियों का उल्लेख है। अर्थात् प्रत्येक क्षेत्र की बोलियां भिन्न-भिन्न हैं परन्तु उनका इतना विकास कैसे हो सकता है कि वे स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर स्तर तक अध्ययन के योग्य बन सकें।

आज हमारे देश में अनुवाद के काम पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये शिक्षा पर इतना धन खर्च करना उचित नहीं है। इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक गड़बड़ी हो रही है।

प्रसन्नता की बात है कि उप-कुलपतियों ने पृथक दृष्टिकोण अपनाया है। उप-कुलपतियों ने सितम्बर में हुए अपने पिछले सम्मेलन में डा० त्रिगुण सेन की बात को रद्द कर किया और उन्होंने कहा है कि प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। ऐसा करना न केवल प्रत्येक विश्वविद्यालय पर बल्कि संस्था पर तथा विषय पर भी निर्भर करता है। उनका कहना है कि स्नातक स्तर से नीचे अंग्रेजी का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ेगा। विज्ञान, प्रौद्योगीकीय, चिकित्सा, और इन्जीनियरी की पुस्तकों के स्नातकोत्तर स्तर पर भी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

उप-कुलपतियों ने आगे कहा है कि शिक्षा, विद्यार्थियों और अध्यापकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने तथा देश की भावनात्मक एकता की दृष्टि से भी अखिल भारतीय संस्थाओं में अंग्रेजी को रखना पड़ेगा।

मास्को जाने से पूर्व एक बार डा० त्रिगुण सेन ने कहा था कि यदि अंग्रेजी हटाने में शीघ्रता की गई तो एक शून्य पैदा हो जायेगा जिसको भरना कठिन होगा। डा० सेन हिन्दी राज्यों को इस तीन भाषायी सूत्र को समाप्त करने के लिए स्वयं प्रोत्साहन देने के लिये जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि हिन्दी भाषी राज्यों ने तीन भाषी सूत्र को पूर्णतया समाप्त कर दिया है। केवल अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में इस सूत्र को लागू किया गया है। अतः मैं हिन्दी भाषी लोगों को चेतावनी दूँगा कि वे घृणा से काम न लें और 'अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन' न चलायें क्योंकि इससे 'हिन्दी हटाओ आन्दोलन' की आग भड़कने की संभावना है। इन लोगों ने

बम्बई में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को नष्ट करने का यत्न किया था । परन्तु इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि आप उनको अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने से नहीं रोक सकते क्योंकि अंग्रेजी उनकी मातृ भाषा है। यह भी अन्य भारतीय भाषाओं की तरह एक भारतीय भाषा है। 1962 में गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत गुजरात विश्व विद्यालय ने अंग्रेजी को गैर-कानूनी घोषित किया था परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस को रद्द कर दिया।

मैं संविधान के निर्माताओं में से एक हूँ। उस समय भी हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रश्न आया था और मैंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता। एक मत से ही हिन्दी को राज भाषा बनाने का संकल्प पारित हुआ था। उस समय यह भी कहा कि भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती क्योंकि भारत में हिन्दी से पुरानी बंगाली और तामिल जैसी भाषायें मौजूद हैं। इसी कारण राष्ट्रीय भाषा के बजाय राज भाषा का नाम दिया गय था ताकि सरकारो तथा कुछ अन्य प्रयोजनों हेतु हिन्दी का प्रयोग किया जा सके। संविधान बनाते समय उच्च शिक्षा के लिये हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने का कोई विचार नहीं था। संविधान के निर्माण से यह स्पष्ट रूप से पता लगता है कि प्रशासनिक तथा न्यायिक मामलों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग किया जायेगा। सभी समितियों तथा आयोगों ने अंग्रेजी को जारी रखने की सिफारिश की है। हिन्दी के विपरीत अंग्रेजी एक अखिल भारतीय भाषा है। इससे किसी विशेष प्रदेश अथवा समुदाय के किसी विशेष वर्ग को कोई लाभ नहीं है।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर स्तर तक शिक्षा की एक ही व्यवस्था जो हमारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल है और जो समानता और न्याय पर आधारित है, करने को कहा है। मेरे माननीय शिक्षित मित्र अभी भी पुराने दृष्टिकोण से सोच रहे हैं।

क्या रूस ने अँग्रेजी के बिना विज्ञान में प्रगति नहीं की है। क्या स्वयं अँग्रेजी ने यूनानी और लैटिन भाषा के बिना ख्याति प्राप्त नहीं की। कोई भी देश अपनी भाषा के बिना महान नहीं हो सकता। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि भारत में 177 भाषायें हैं और कई सौ बोलियां है। क्या उनको यह पता है कि स्वयं ब्रिटेन में कई बोलियाँ हैं। उनकी भी कई भाषायें हैं। विश्व के प्रत्येक देश में भाषा का झगड़ा चल रहा है। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम अपनी भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनायें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता हम किसी साम्राज्यवादी शक्ति के जन्मजात गुलाम रहेंगे। इसलिए अपने देश की भाषाओं को चाहे वह एक हो अथवा दो हमे गौरवपूर्ण स्थान देना चाहिये।

किसी न किसी दिन हमें अपनी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। चाहे इस में कितना ही समय क्यों न लगे। कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बुद्धिमत्ता पूर्ण सुझाव दिया है

शिक्षा मंत्री डा० त्रिगुण सेन का, जो राष्ट्रवादी तथा प्रजातंत्रवादी होने के अतिरिक्त शिक्षा विशारद भी हैं, यह सुझाव सराहनीय है कि इस आयोग के प्रतिवेदन पर पहले संसद सदस्यों द्वारा विचार किया जाना चाहिये। वास्तव में उन्होंने सदस्यों से इस प्रतिवेदन का अध्ययन करने तथा अपना निर्णय देने का अनुरोध करके देश में एक शानदार प्रजातंत्रीय परम्परा की स्थापना की है। यदि भविष्य में संसद सदस्यों को ऐसे सभी आयोगों के प्रतिवेदनों पर इस तरह विचार करने का अवसर दिया गया, तो इससे प्रजातंत्रीय परम्पराओं की नींव और भी अधिक सुदृढ़ होगी।

दूसरा प्रश्न आम स्कूलों के बारे में उत्पन्न होता है। कुछ लोग इन स्कूलों का विरोध करते हैं, मै नहीं समझ पाता कि वे ऐसा क्यों करते हैं। मुझे तो उचित यह लगता हैं कि सभी के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा इन्ही स्कूलों में मिलनी चाहिए क्योंकि इन स्कूलों में समाजवाद का वातावरण रहता है जिससे हमें आर्थिक समानता तथा आर्थिक न्याय मिलता है। समाजवादी समाज की स्थापना लिये इनसे बढ़कर और कोई स्कूल नहीं हो सकते क्योंकि वे सामाजिक भेद-भाव की भावना ही उत्पन्न नहीं होने देते।

शिक्षा निदेशालय-प्रधान अथवा मंत्रालय-प्रधान नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इस समय है। शिक्षा अध्यापक-प्रधान होनी चाहिए। कोठारी आयोग ने शिक्षा को अपने अधिकार तथा कार्यक्षेत्र में सर्वाधिक ऊँचा स्थान देकर सराहनीय कार्य किया है, इस आयोग ने अध्यापक को उसके अधिकार तथा उसकी परिस्थिति प्रदान की है। यह सच है कि अध्यापक अपनी माँगों के लिये राज्यों में आन्दोलन कर रहे हैं, तथापि उन्हें वह सत्य कुछ मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। इसलिए मेरा अनुरोध तथा सुझाव है कि इस प्रतिवेदन पर केवल कागजी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अध्यापकों की दशा में सुधार होना आवश्यक है और इस आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं और जिनकी क्रियान्वित से समाजवादी समाज का निर्णय होगा और समाजबाद के हमारे सपने को एक साकार रूप मिलेगा। अतः मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिये यथासंभव प्रयत्न करें और देश में भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्रांति लाने का श्रेय प्राप्त करें।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाड़े) : कुछ सदस्यों के भाषण सुनने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अन्य बहुत से क्षेत्रों की भाँति शिक्षा के क्षेत्र में भी शक्तिशाली लोगों का स्वार्थ निहित है। कुछ लोग जो अंग्रेजी को विश्वविद्यालय स्तर पर अथवा अन्य किसी स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखने की बात करते हैं अथवा उसके पक्ष में दलील देते हैं यह भूल जाते हैं कि अंग्रेजी केवल एक छोटे से समुदाय की भाषा है। हमारे लिये प्रादेशिक भाषाओं को सभी स्तरों पर शिक्षा तथा प्रशासन का माध्यम बनाना आवश्यक है जैसा कि कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है। वर्तमान शिक्षा मंत्री को इस सिफारिश को कार्यरूप देने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। हमारे देश में वयःस्थों तथा बड़े-बड़े शिक्षा विशारदों की कमी नहीं है। किन्तु दुर्भाग्यवश वे समय के अनुकूल नहीं सोचते, वे समय की

गति के अनुसार नहीं चलते और देश की नाड़ी नहीं पहचानते । इसलिए वे क्रियान्विति के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं ।

जहाँ तक प्रादेशिक (भाषाएँ) सूत्र की क्रियान्विति का सम्बन्ध है, उसे विश्वविद्यालयों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे वांछनीय परिणाम की प्राप्ति में विलम्ब होगा । किन्तु इसके लिये समय सीमा पांच वर्ष की निर्धारित करना आवश्यक है जिससे कि इस दिशा में निरन्तर प्रगति होती रहे । निर्धारित अवधि के अन्दर यदि हम वाँछनीय प्रगति नहीं कर सकते, तो आवश्यकतानुसार समय सीना आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं । आवश्यकता है केवल दृढ़ प्रगति होने की । जहाँ तक धन का सम्बन्ध है । यदि प्रकाशकों को निश्चित रूप से यह बता दिया जाये कि इस सम्बन्ध में समय-सीमा निर्धारित की जा चुकी है और शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन प्रादेशिक भाषाओं के रूप में निश्चित है, तो संसाधन स्वतः जुटने लगेंगे और सरकार को धन के सम्बन्ध में चिन्ता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी ।

जहाँ तक प्रादेशिक भाषाओं का सम्बन्ध है । इस सिद्धान्त पर अधिकांश लोग सहमत हैं । किन्तु हमारा यह सोचना कि इस आयोग कि सिफारिशों का अनुसरण तथा क्रियान्विति करके हम एक आश्चर्यजनक तथा महानकार्य करेंगे—गलत है और मैं इस प्रवृति के विरुद्ध सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि वह ऐसा समझती है । आयोग ने स्वतः घोषित किया है कि ये सिफारिशों शिक्षा तथा शिक्षा पद्धति में क्रान्ति लाने की दृष्टि से की गई हैं और यही शिक्षा आयोग का निर्धारित उद्देश्य है । उसने अपने प्रतिवेदन में कहा है :

"Judged from this point of view, it becomes evident that the present system of education designed to meet the needs of an imperial administration within the limitations set by a feudal and traditional Society, will need radical changes if it is to meet the purposes of a modernising democratic and socialistic society .... changes in objectives, in content, in teaching methods, in programmes, in the size and composition of the student body, in the selection and professioaal preparation of teachers and in organisation. In fact, what is needed is a revolution in education which in turn will set in motion the much desired social, economic and cultural revolution"....

इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति लाने की आवश्यकता है जिससे स्वतः वांछनीय सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति आयेगी ।

[श्री गु० सिंह ढिल्लों पीठासीन हुए ।
Shri G. S. Dhillon in the chair.]

देश में सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्ति के साथ ही यह शिक्षा सम्बन्धी क्रान्ति लायी जा सकती है । अतः सबसे पहले देश के आधारभूत ढांचे में परिवर्तत लाना होगा । इस कार्य में देश के लोगों के सभी वर्गों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ना होगा । देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मालूम होता है कि यह कार्य सरल नहीं है । हमारे समक्ष बहुत सी समस्याएं है । संविधान में कहा गया है कि हमें अपने देश में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध करनी है । यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हमें गम्भीरता से प्रयत्न करने होंगे ।

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट बहुत बड़ी रिपोर्ट है । इसमें शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया गया गया है । हमें अपने समाज के छोटे वर्ग को तो और अधिक सुविधायें देनी हैं । आयोग में भी इस ओर ध्यान दिया है । संसद सदस्यों की समिति ने भी इस विषय पर मनन किया है । विश्व के विकसित देशों में भी निम्न वर्ग के लिये विशेष सुविधायें जुटायी जाती हैं । मंत्रालय को इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये और अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये ।

शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के मामले में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिये । इस बारे में एक स्थायी निर्णय कर लिया जाना चाहिये ।

शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । हमारे राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षकों का अपना स्तर ठीक नहीं है। अध्यापन कार्य टीक प्रकार से नहीं हो रहा है । मैं यह नहीं चाहता कि निम्न वर्ग के लड़कों के लिये पृथक स्कूल खोले जायें । हमें शिक्षकों को प्रोत्साहन देना चाहिये । उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिये । उन्हीं से देश के भविष्य नागरिकों को शिक्षित करना है । इस बारे में ब्यौरेवार विचार किया जाना चाहिये । आयोग ने शिक्षकों के महत्व समझकर ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ।

हमने शिक्षा के बारे में बहुत सी समितियां और आयोग नियुक्त किये हैं । अब तो हमें उनकी रिपोर्टों को कार्यान्वित करना है ।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : शिक्षा आयोग ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है । उसने शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया है और अपने सुझाव दिये हैं । इससे पहले भी इस विषय पर बहुत से आयोग नियुक्त किये जा चुके हैं । परन्तु उनके प्रतिवेदनों को कार्यान्वित करने की दिशा में बहुत कम काम हुआ है ।

हमारे देश में पिछले बीस वर्षों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । इस अवधि से पहले हमारे देश में डा० जे० सी० बोस, रामन जैसे वैज्ञानिक तथा जादूनाथ सरकार और सावरकर जैसे इतिहासकार उत्पन्न हुए परन्तु अब ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। हमें इस बारे में गम्भीरता से विचार करना होगा ।

डा० जाकिर हुसैन ने कहा है कि अपनी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से देनी चाहिये। अब इस आयोग ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है । बल्कि यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा भी मातृभाषा में होनी चाहिये। इस आयोग की रिपोर्ट पर संसद सदस्यों की समिति ने उपकुलपतियों ने और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने विचार किया है । अब इस पर यहां चर्चा हो रही है । अच्छा होता यदि शिक्षा मंत्री यहां पर सरकार का निर्णय घोषित करते । अब समय आ गया है कि हम इस दिशा में कुछ करें । इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के समय मुझे यह आभास हुआ कि इस में धर्म निरपेक्षता की शिक्षा पर बल दिया गया है । ऐसी बातें तो राजनीति में आती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये असंगत सी जान पड़ती हैं ।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिये। हमारे देश में 15 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाएं माना गया है। हमें इन भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिये। परन्तु इन भाषाओं में बहुमत की भाषा को ही सम्पर्क भाषा बनाया जा सकता है। सभी भाषाओं के विकास के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये। हमारे देश में हिन्दी ही सम्पर्क भाषा बन सकती है क्योंकि यह बहुमत की भाषा है। यही देश की एकता का स्रोत हो सकती है।

अंग्रेजी भाषा का अपना महत्व है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। परन्तु अन्य विदेशी भाषाएं भी तो महत्वपूर्ण है। यह ठीक नहीं कि हम अंग्रेजी के बिना प्रगति नहीं कर सकते।

कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के कारण देश में एकता है। मैं इस धारणा को ठीक नहीं समझता। मेरे विचार में तो अंग्रेजी के कारण देश में फूट को प्रोत्साहन मिला है। उत्तरी भारत के राज्यों में दक्षिण की एक भाषा अनिवार्य की जानी चाहिये और दक्षिण में हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की मांग की जा रही है। ठीक है, उन्हें समाप्त कर दीजिये क्योंकि वे दफ्तरशाही के केन्द्र हैं। फिर सैनिक स्कूलों की बारी आयेंगी। फिर उन्हें भी समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि उनकी फीसें अधिक हैं। क्या फिर उन स्कूलों को भी समाप्त किया जायेगा जिनकी परम्पराएं 50 वर्ष या इससे भी अधिक समय की हैं ? उन स्कूलों में अच्छे अध्यापक हैं, छात्रों के रहने की अच्छी व्यवस्था है, अधिक सुविधाएं हैं और पढ़ाने के अच्छे तरीके हैं। गरीब लोगों को भी ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जातीं ? मेरे विचार में इस प्रकार के स्कूलों को समाप्त करने के बजाय इन 50 या 60 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर योग्यता के आधार पर दाखिला दिया जाना चाहिये। इस तरह मेरा विचार यह है कि इन स्कूलों को समाप्त न करके उनमें सुधार किये जायें।

Dr. A.G. Sonar (Ramtek) : The Report of the Education Commission in quite enhaustive. This Commission has considered the question of education right from primary stage to University stage. The Report of the Kothari Commission should be implemented in a systematic manner.

A good number of people have expressed their concern about the neighbourhood schools. I want to ask such people whether they want the rule of a particular class of society or masses. In case we want to provide equal opportunities to all classes of society in the field of education, then we have to lay emphasis on the neighbourhood schools and we have to implement this scheme vigorously. At present only a particular class of society can get their children educated in the public schools, whereas the children of laymen afford to receive good education for their children. There should be an end to such distinctions.

I want to ask whether there is any country in the world in which foreign language is being used as official language even after 20 years of achievement of independence? There is no such country in the world. If people from South do not know Hindi, English can be kept as link language for certain period but that is a different matter. It is therefore, not proper to continue to use English as official language.

In my opinion the medium of instruction should be regional languages. There should be some time limit for this purpose otherwise the same position will continue which has been going on for the last 20 years. An hon'ble Member has said that by adopting regional languages as medium of instruction a vaccum will be created· The medium of instruction would be regional languages at all levels and Hindi will remain as link language, as provided in the constitution.

I am of the opinion that there should be uniformity in system of education throughout the country. The Government should take steps to give higher salaries to the teachers.

I am not in favour of select admissions to the colleges as recommended by the Commission. I oppose it emphatically. It will be an injustice to the people living in rural and backward areas. When our people visit foreign countries, they speak in English. It is not proper. I, therefore suggest the scheme of switching over to regional languages should be implemented as early as possible.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Kothari commission and Committee of Members of Parliament on Education have dealt with the question of medium of instrution exhaustively.

There are only a limited number of people who are supporting English.

Ms. Chairman : The hon'ble Member may continue his speech tomorrow.

झरिया में खनन कार्य

Re: Mining Operations in Jharia

Shri B.S. Sharma (Banka) : There are Coal mines all round the Jharia town. There are two companies who have undertaken mining operations Underneath the Jharia Town. it is not known how our chief Inspector of Mines has allowed them to conduct these operations. It has been said that experts opinion has been taken and pillers of certain length and width are being left at proper distance in the mine. But we know how these rules are being observed there. There is general feeling among the people of that area that there have been some underhand dealing in granting permission for conducting mining operations which her endangered the life of the inhabitants of the town.

आधे घण्टे की चर्चा

Half-an-hour discussion

The people of that area fear that some officials are involved in the said underhand dealing. When the people in that area are sleeping at night, the sounds of blasts are heard which upsets the peaceful living. The people fear danger to their lives and properties.

Editorials have been published about the dangers passed by these mining operations. It has been stated there in that due to these explosions and bursting sounds at night sleeping babies are awakened, houswives are frightened and patients get nervous. Severel cracks in the buildings have developed there. Besides what has been published in the newspapers, the people have writen to the authorities. They have written to the Chief Inspector of Mines but no

reply has been received. When there is so apparent danger to the inhabitants of Jharia it is not understood why government is anxious to conduct underneath mining operertions in Jharia when there is sufficient Coal available at other places. There are huge deposits of coal is our coalfields.

There is already fire on two sides of Jharia and it is the opinion of the experts that if the ground becomes hollow, the fire can find its way in that hollow place and if the ground remains to be solid it will resist the danger of fire. In view of this position, the inhabitants of that areas have sought assurance from the authorities that mining operations underueath the town would be stopped. But no such assurance has been given. They have stated that pillars of 100'×100' are being left but where is the guarantee for such actions.

It is just possible that technically speaking there may not be any such danger but people are very much afraid of it. The government should therefore give an assurances to the people of that area that if some untoward thing happens because of the mistake of any official or any expert, severe action will be taken against the person concerned.

If the Labour Minister is worried about the employment of the labourers working in this area then it is good thing. But I want to ask whether these labourers cannot be provided employment elsewhere. I think that they can easily be observed in Coalfields of Bengal and Bihar.

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता का आदर करता हूँ । यदि लोगों को पूरी बात का पता न हो और इस प्रकार की बातें सुनी जायें कि मकान गिर जायेंगे और काफी सम्पत्ति की हानि हो जायेगी तो चिन्ता होना स्वाभाविक है । वास्तव में सही स्थिति की जानकारी के लिये ठीक ढंग से प्रचार करना चाहिये । वास्तव में स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है कि जिससे किसी प्रकार की घबराहट पैदा हो । इस सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व हमें अपने मस्तिष्क से यह बात निकाल देनी थी कि किसी प्रकार की साजिश की जा रही है । यदि लाइसेंस आदि देने में कोई गड़बड़ हुई है तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

सर्वप्रथम हमें इस बात को समझ लेना चाहिये कि झरिया नगर के नीचे जो खुदाई हो रही है वह कोयले के लिये नही की जा रही है । नगर के दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिये वहाँ से एक मार्ग बनाया जा रहा है जहां पर कोयले की खाने हैं जब हम 10×12 फुट का मार्ग बनाते हैं स्तम्भो से 100×100 फुट स्थान छोड़ दिया जाता है, उसके बाद 10 फुट का अन्तर होता है और उसके बाद 100×100 फुट स्थान छोड़ा जाता है । यह स्तम्भ 100×100 फुट का होता है और मार्ग केवल 10 फुट होता है स्तम्भ काफी बड़ा होता है । इस प्रकार के स्तम्भ दोनों ओर होते हैं । विकास कार्य के लिये यह मार्ग 200 फुट नीचे बनाया जा रहा है । हमने यह आदेश जारी किये हैं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को वहां जाना चाहिये और इस प्रकार के प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करना चाहिये जिससे वहां पर न तो कोई व्यक्ति गलती करे और नहीं कोई शरारत कर सके ।

दूसरी बात रात के समय विस्फोट की है । पहले दिन के समय में ही तीन विस्फोट कर लेते थे । परन्तु इन विस्फोटों से लोगो के दिलों में घबराहट पैदा हो जाती है । इस

लिये हमने सुझाव दिया कि में 100 बार विस्फोट करने के बजाय 70 विस्फोट किये जाये और उनमें समय का अन्तर भी बढ़ा दिया जाये । फिर यह कोई नई बात नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले 20 या 30 वर्षों के यह काम चल रहा है । ऐसी पांच खाने हैं जिनके मार्ग नीचे की ओर से बनाये जा रहे हैं । इन में से तीन का काम पूरा हो गया है और पिछले 25 या 30 वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई । फिर यह एक ही स्थान पर नहीं, बल्कि कई स्थानों पर स्थित है । हम इस सम्बन्ध में काफी सावधानी बरत रहे हैं कि स्तम्भों के अन्तर को कम न किया जाये । हमने स्पष्ट अनुदेश दिये हैं कि इनस्तम्भों के पास से कोयला न निकाला जाये । क्योंकि इस से वे कमजोर हो जाते हैं मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इन स्तम्भों के पास से कोयला नहीं निकाला जायेगा । जहां तक विस्फोठों का सम्बन्ध है हमने उनसे तीन के स्थान पर एक विस्फोट करने को कहा है । हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि रात को विस्फोट न करके दिन को ही किये जायें । क्योंकि दिन को आवाज कम सुनाई देती है । हम यह विस्फोट कोयले के लिये नहीं करते । ये विस्फोट वहां किये जा सकते हैं जहां भूतत्वीय हलचल हो या कोई सख्त चट्टान हो । कोयला खोदने के लिये इस प्रकार के विस्फोटों की अनुमति नहीं है । मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूँ कि जान और माल की सुरक्षा के साथ-साथ हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे की किसी को असुविधा न हो ।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति की छटनी हो या कोई बेरोजगार हो । परन्तु इसके साथ हमने जनता को होने वाली हानि का भी ध्यान रखना है । हम इस बात पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गलती करते हैं तो उन्हें अवश्य सजा दी जाये ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 नवम्बर, 1967/30 कार्तिक, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha adjourned till Eleuen of the clock on Tuesday, November 21, 1967/Kartik 30, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Alld.